राष्ट्रीय संस्करण

भारत में ला लीगा फुटबॉल के ब्रांड एंबेसडर बने रोहित शर्मा >> 14

वर्ष 3 अंक 185

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

दिल का मर्ज दूर करेगा नींबू और संतरे का छिलका

प्रयागराज : नीबू व संतरे का रस निकाल कर जिस छिलके को आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बड़ा गुणकारी है। यह दिल के मर्ज के लिए कारगर दवा है। यह बात इलाहाबाद केंद्रीय विवि के जैव रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एसआइ रिजवी के शोध में सामने आई है। (पेज-10)

जागरण विशेष

चाकू वाला रामपुर अब लकड़ी के लिए मशहूर

रामपुर : चाकू का जिक्र आते ही जेहन में रामपुर का नाम आ ही जाता है, लेकिन अब शहर को एक नई पहचान मिल रही है। यह नई पहचान लकड़ी कारोबार के रूप में है। इस समय रामपुर उत्तर प्रदेश में लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विधायिका में एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 10 साल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने गुरुवार को पारित कर दिया। तमाम दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सर्वसम्मति से बिल को पारित किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पश्चिमी विक्षोभ का असर बारिश से कांपी दिल्ली

नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी और उत्तर भारत के राज्यों में बारिश ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पंजाब और हरियाणा में बारिश ने तापमान गिरा दिया है। दिल्ली में भी देर शाम कई जगहों पर बारिश हुई। ठंडी हवा भी चली, जिससे ठंड महसूस हुई। अधिकतम तापमान में बुधवार की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस की कमी आई है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सरकार पर औद्योगिक उत्पादन, महंगाई दर की दोहरी मार

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत तलाश कर रही सरकार को औद्योगिक उत्पादन और खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने निराश किया है। कारखानों के उत्पादन में अक्टूबर में 3.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। यह तीसरा महीना है जब कारखानों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। वहीं, खुदरा महंगाई की दर नवंबर में 5.54 परसेंट पर पहुंच गई जो बीते तीन साल में सर्वाधिक है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ब्रेक्जिट का भविष्य तय करने को ब्रिटेन में उमड़े वोटर

लंदन : ब्रिटेन में गुरुवार को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में वोटरों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों से ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव) का भविष्य तय होगा। ब्रिटेन में 2016 से ब्रेक्जिट के चलते सियासी गतिरोध बना हुआ है। इसी वजह से इस यूरोपीय देश में पांच साल के अंदर तीसरी बार आम चुनाव कराने की नौबत आई।

पहले ही दिन सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

राह साफ ▶ अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने सर्वसम्मत फैसले पर कायम

मंदिर के लिए जमीन देने व सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से जमीन देने पर फिर मुहर

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- पर अभी भी बचा है कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प
- कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं की गई थीं दायर, दस थीं मूल पक्षकारों की
- पांचों जज ने चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये किया विचार

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने गत नौ नवंबर के अपने फैसले पर पुनर्विचार मांगने वाली सभी याचिकाएं पहली ही सुनवाई में खारिज कर अपने फैसले में किसी भी बदलाव से इन्कार कर दिया है। इस तरह कोर्ट 2.77 एकड़ का विवादित स्थान मंदिर निर्माण के लिए देने और अयोध्या में ही कहीं और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के अपने फैसले पर कायम है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के बंद चैंबर में सभी 19 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि उन्होंने इन याचिकाओं पर गंभीरता से विचार किया और उनके साथ दाखिल किए गए दस्तावेज देखने के बाद उन्हें इन याचिकाओं पर फिर से विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं में से 10 याचिकाएं मूल पक्षकारों की ओर से दाखिल हुई थीं। इनमें जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना सैयद असद रसीदी, फारुक अहमद, मौलाना मुफ्ती हसबुल्लाह, मिसबहुद्दीन, हाजी महबूब अहमद, मौलाना महफुर्जुरहमान, हाजी असद अहमद, अखिल भारत हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और शिया सेंट्रल बोर्ड की याचिकाएं थीं। इसके अलावा डॉ. मुहम्मद अयूब, तहरीक फारुक इस्लाम, अब्दुल अंसारी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बरीश कुमार, सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल लीग, प्रभात पटनायक (इनके साथ 39 और लोग याचिकाकर्ता थे) और दाल चंद कपिल की याचिकाएं भी खारिज हुईं जो कि मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। हालांकि पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद पक्षकारों के पास अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है। मूल फैसला सुनाने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे। जस्टिस गोगोई के सेवानिवृत हो जाने के कारण पीठ में पांच न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को पीठ में शामिल किया गया था।

चैंबल में न वकील होते हैं, न बहस : पांचों न्यायाधीशों ने चैंबर में सर्कुलेशन के जरिए पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिकाओं पर मूल फैसला सुनाने वाली पीठ के न्यायाधीश चैंबर में ही विचार करते हैं। उस दौरान वहां वकील और बहस नहीं होती सिर्फ मुकदमे से जुड़ी फाइलें और रिकार्ड देखकर न्यायाधीश फैसला लेते हैं। इस दौरान अगर उन्हें जरूरी लगता है तो वे पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश देते हैं। अयोध्या के मामले में पांचों न्यायाधीशों ने चैंबर में विचार करने के बाद याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने की अर्जियां और पुनर्विचार याचिकाएं दोनों ही खारिज कर दीं और 9 नवंबर के फैसले पर फिर मुहर लगा दी है। मुकदमे के एक अहम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी जबकि हिंदू पक्ष की ओर से सिर्फ अखिल भारत हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फैसले का सीमित रिव्यू मांगा था।

यह था फैसला : गत 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने करीब पांच सौ साल से चले आ रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। उस फैसले में कोर्ट ने राम जन्मभूमि का अंदरूनी और बाहरी अहाता ट्रस्ट या बोर्ड के जरिए मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। जबकि गैर कानूनी ढंग से तोड़ी गई मस्जिद के बदले मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर अयोध्या में ही दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। यह फैसला पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मत से दिया था।

कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। साथ ही ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को शामिल करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुबूतों को देखते हुए मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।

क्यूरेटिव याचिका पर ली जाएगी राय : जिलानी

लखनऊ : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने असुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार ही नहीं किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलानी ने कहा, 'अभी हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से बात करेंगे। (पेज-7)

जेएनयू में छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा का किया बहिष्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : छात्रावास फीस वृद्धि के मुद्दे पर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में गुरुवार से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गईं। आंदोलन कर रहे छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उन पर परीक्षाओं में खलल डालने का भी आरोप लगा है।

बताया जा रहा है कि सिर्फ स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की ही परीक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई। इसमें एमए के प्रथम वर्ष के 45 और एमए दूसरे वर्ष के 45 छात्रों समेत एमफिल के 30 छात्र शामिल हुए। जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस 1 एवं 2, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिट्रेचर एंड कल्चरल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जैसे स्कूलों के गेट बंद रहे। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र सुबह 9 बजे से ही यहां पहुंच गए और परीक्षाओं के संचालन में बाधा पहुंचाई। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से परीक्षाओं का बहिष्कार किया। किसी भी परीक्षा के संचालन में कोई बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन के कारण परीक्षा देने ही नहीं गए।

हालात सामान्य बनाने में जुटे कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों से भी बात की और परीक्षा में शामिल होने व प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया।

सीएबी पर असम में हिंसा, दो की मौत

- कर्फ्यू के बावजूद बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस को चलानी पड़ी गोली
- सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी

असम के डिब्रूगढ़ में गुरुवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जलाए गए टायर को बुझाते सुरक्षा बल। प्रेट्र

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को कर्फ्यू को नकारते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई जगहों पर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की भी खबर है।

सीएबी यानी कैब को दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद से असम में हिंसा ने और जोर पकड़ लिया है। हालात संभालने के लिए सरकार ने कर्फ्यू का एलान किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। प्रदर्शनकारी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं। डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने एक बस अड्डे को आग के हवाले कर दिया। यहां के एसपी गौतम बोरा ने एक साथ कई जगहों पर हो रहे प्रदर्शन को संभालने के लिए चार से पांच हजार अतिरिक्त बल की जरूरत जताई है। छात्र संगठन आसू के आह्वान पर गुवाहाटी में लाताशिल खेल मैदान में बड़ी तादाद में लोग जुटे। फिल्म एवं संगीत जगत की कई हस्तियां भी इसमें शामिल हुईं। आसू का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कैब को लाकर असम के लोगों को धोखा दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया समेत 10 जिलों में इंटरनेट पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक, आरटीआइ कार्यकर्ता अखिल गोगोई को गिरफ्तार किया गया है।

विधायक का घर फूंका : डिब्रूगढ़ जिले में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह क्षेत्र छाबुआ प्रदर्शनकारियों ने विधायक बिनोद हजारिका के घर पर आग लगा दी। वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सर्किल ऑफिस को भी फूंक दिया। गुवाहाटी-शिलांग रोड पर क्रिश्चियन बस्ती क्षेत्र के निकट असम के पुलिस प्रमुख भास्कर ज्योति महंत के काफिले पर पत्थरबाजी भी हुई।

गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हटाए गए : हालात काबू में लाने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ पुलिस में प्रशासनिक बदलाव भी किए हैं। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को हटाकर उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश अग्रवाल को सीआइडी में भेज दिया गया है। उनकी जगह जीपी सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। कुछ अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

मेघालय, त्रिपुरा में भी इंटरनेट बंद : अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में 48 घंटे के लिए इंटरनेट व एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। दोनों राज्यों से हिंसा की कोई बड़ी खबर नहीं आई है। इस बीच मेघालय को सीएबी से पूरी तरह बाहर रखने की मांग के साथ गृह मंत्री अमित शाह मिलने जा रहे राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को मुलाकात टालनी पड़ी। बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने के लिए उनके मंत्रिमंडल सहयोगी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकादमी का दौरा करने जाएंगे।

हर हाल में रखेंगे पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जारी हिंसा रोकने की अपील की है। मोदी ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पीएम ने धनबाद में एक रैली के दौरान कहा, 'अपने सेवक पर भरोसा रखें। आपकी पहचान और संस्कृति का पूरा मान-सम्मान रखा जाएगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से असम समझौते की धारा-6 के अनुरूप ही असम के लोगों के संवैधानिक, राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आंच नहीं आएगी।' (पेज-5)

नागरिकता कानून संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली : नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक संसद से पास हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। केरल के दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह राजनीतिक पार्टी केरल में कांग्रेस का सहयोगी दल है। (पेज-5)

बिल पर बवाल ▶ पृष्ठ 5 और 6

असम-त्रिपुरा में हिंसक आंदोलन में विमान और ट्रेन सेवाएं ठप

बवाल करने वाले 250 लोगों पर मुकदमा

भारत की लिसिप्रिया ने जलवायु सम्मेलन में दुनिया को झकझोरा

लिसिप्रिया कंगुजम प्रेट्र

मैड्रिड : महज आठ साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली भारतीय लड़की लिसिप्रिया कंगुजम ने अपनी चिंताओं से दुनिया को झकझोरा है। मणिपुर की इस नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीओपी-25 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसे मासूमों के भविष्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की गुहार लगाई। लिसिप्रिया ने स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग की याद दिला दी जिसने हाल में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण बचाने के लिए एक यादगार भाषण दिया था। उसे पर्सन ऑफ द इयर का खिताभ भी मिला है। (पेज-16)

हैदराबाद में हुए एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिरपुरकर की अध्यक्षता में बनाया तीन सदस्यीय आयोग
- छह महीने में जांच करके सौंपेगा रिपोर्ट

हैदराबाद में दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपितों की पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में हुई मौत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। आयोग मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच करके छह महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा।

जस्टिस वीएस सिरपुरकर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। जस्टिस सिरपुरकर के अलावा आयोग में अन्य सदस्य बांबे हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रेखा सुंदर बालडोटा और सीबीआइ के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन हैं। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ कांड पर सवाल उठाने और जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। हैदराबाद में 28 नवंबर की रात एक महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। छह दिसंबर को पुलिस चारों आरोपितों को जांच के लिए मौके पर लेकर गई थी।

पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने पुलिस के हथियार छीनकर पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें चारों आरोपित मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल कर पुलिस मुठभेड़ की जांच की मांग की गई है।

कोर्ट ने कहा-सच्चाई सामने आना जरूरी पेज>>3

एफ-16 विमान का गलत इस्तेमाल किए जाने पर अमेरिका ने पाक को फटकारा

- साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का लगाया आरोप
- भारत ने मार गिराया था पाकिस्तान का लड़ाकू विमान

वॉशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान के गलत इस्तेमाल पर फटकार लगाई है। यूएस न्यूज ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह खबर दी है। वेबसाइट के अनुसार, इसी साल अगस्त में अमेरिकी विदेश विभाग में तत्कालीन शस्त्र नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की उपमंत्री एंड्रिया थॉम्पसन ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को एक पत्र लिखा था। इसमें अमेरिका द्वारा दिए गए एफ-16 लड़ाकू विमान का गलत इस्तेमाल करने और साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था।

दोनों अधिकारियों के बीच यह पत्राचार फरवरी में भारत द्वारा एफ-16 जेट विमान मार गिराने के कुछ महीने बाद हुआ। पत्र में फरवरी की घटना का जिक्र नहीं है। 27 फरवरी को भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने राजौरी सेक्टर में भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन कर बमबारी की थी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके कुछ देर बाद ही भारत ने एक एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जो पाकिस्तान की सीमा के तीन किलोमीटर अंदर जाकर गिरा। विमान के साथ एक पैराशूट को भी गिरते देखा गया। हालांकि, इसके पायलट का क्या हुआ, यह पता नहीं चला।

एक सूत्र के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान ने एफ-16 विमानों का इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिकी मिसाइलें लगी हुई थीं। पाकिस्तान के इस व्यवहार से यह हथियार किसी तीसरे पक्ष तक पहुंच सकता था, जिससे साझा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमान समझौता इन शर्तों के साथ हुआ था कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकियों के साथ लड़ाई में करेगा। किसी अन्य देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझौते में यह शर्त भी है कि पाकिस्तान अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल मुशाफ और शाहबाज एयर फोर्स बेस से ही करेगा।

अमेरिका ने पाक को किया आगाह, हाफिज सईद मामले पर न्याय होता दिखे पेज>>13

कूटनीति

बांग्लादेश विदेश मंत्री मोमेन और गृहमंत्री खान ने रद की भारत यात्रा, भारत ने कहा, ढाका की मौजूदा सरकार नहीं कर रही अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

नागरिकता बिल पर बांग्लादेश को मनाने में जुटा भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

बुधवार को संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पारित होने के बाद पड़ोसी देश तिलमिलाए हुए हैं। भारत के बेहद करीबी पड़ोसी मित्र बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुजमां खान ने अपनी भारत यात्रा रद कर दी। मोमेन गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ ही घंटे पहले भारत को इसे रद करने की सूचना दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश विदेश मंत्री को मनाने की कोशिश शुरू ही हुई थी कि यह सूचना आई कि गृह मंत्री खान ने भी शुक्रवार को मेघालय पहुंचने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। आधिकारिक तौर पर ढाका ने कहा है कि घरेलू स्तर पर व्यस्तता को देखते हुए यात्राएं रद की गई हैं। लेकिन बांग्लादेश के आधिकारिक सूत्रों ने यह बताने में कोई गुरेज नहीं किया है कि सीएबी पर चर्चा के दौरान बांग्लादेश की आंतरिक कानून एवं व्यवस्था पर नकारात्मक टिप्पणी से उनकी छवि का नुकसान हुआ है।

साउथ ब्लॉक यानी विदेश मंत्रालय ने ढाका से आईं खबरों को गंभीरता से लिया है। फाइल

बहरहाल, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व में बंग बंधु मुजीबुर्रहमान के कार्यकाल में या मौजूदा पीएम शेख हसीना के कार्यकाल में वहां अल्पसंख्यकों का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ कहा है कि 'मौजूदा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रख रही है। वह उनके लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन पहले वहां धार्मिक उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मोमेन की यात्रा रद होने को संसद में पारित सीएबी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।'

इसके बावजूद ढाका से जो खबरें आ रही हैं वह बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। विदेश मंत्री मोमन ने वहां कहा है, 'भारत के भीतर बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें खुद ही उनसे लड़ना चाहिए। इससे हमें कोई चिंता नहीं है। एक मित्र देश होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रिश्तों पर कोई असर हो।'

गृह मंत्री खान को शिलांग में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े एक न्यास की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। वैसे उन्हें सड़क मार्ग से मेघालय की राजधानी पहुंचना था और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अपनी तीन दिवसीय यात्रा रद की है। सनद रहे कि बांग्लादेश संभवतः अभी दक्षिण एशिया में भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र देश है। सितंबर, 2019 में न्यूयार्क में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकात में दोनों नेताओं ने मौजूदा रिश्ते को द्विपक्षीय रिश्ते के सबसे सुनहरे कार्यकाल के तौर पर परिभाषित किया था। तब हसीना ने सीएबी और एनआरसी का मुद्दा उठाया था और बाद में उन्होंने कहा भी था कि मोदी ने आश्वस्त किया है कि इन विधेयकों का बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हसीना दोबारा 2008 में पीएम बनी और तभी से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होने लगे हैं। पिछले 11 वर्षों में यह पहला मौका है जब रिश्तों में कुछ खटास आई है।

इमरान को भारत ने दिखाया आईना

नई दिल्ली : पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी आदत के मुताबिक कैब के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं छोड़ा है। गुरुवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक के बाद एक तीन तल्खी भरे संदेश पीएम खान की तरफ से डाले गए। पाक पीएम ने भारत सरकार की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से की है तो भारत से उन्हें जवाब मिला कि अपने यहां के कानून देखें। (पेज-5)

बेटी पैदा होने पर ससुराल से निकाली गई बहू पढ़-लिखकर बनी जज

अंकिता भारद्वाज, पटना

अपनी बेटी के साथ वंदना मधुकर। फाइल फोटो

पटना वंदना मधुकर ने पास की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा

जिस बहू को ससुरालवालों ने उसके सांवले रंग को लेकर ताने मारे और बेटी पैदा होते ही घर से निकाल दिया, वही बहू ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास कर जज बन गई है। संघर्ष और मजबूत हौसलों की यह कहानी पटना की वंदना मधुकर (34) की है। ससुराल से निकाले जाने के बाद वंदना ने नौकरी करते हुए बेटी को पाला और पढ़ाई भी जारी रखी। मां-बाप के साथ पूरा मुहल्ला वंदना की सफलता से गदगद है।

वंदना का मायका मोकामा में है। उनका विवाह 2015 में पटना में हुआ। जब उनकी शादी हुई थी तो वह मोकामा में ही नियोजित शिक्षक के तौर पर काम करती थीं। शादी के बाद उन्होंने पटना में ही आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव का पद संभाला। इसके बाद से ही घर में कलह बढ़ गई। ससुराल वाले और पति वंदना को पूरी सेलरी घर में देने के लिए कहते थे। वंदना बताती हैं कि शादी के एक साल बाद मई, 2016 में बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद ससुराल वाले उनके सांवले रंग के साथ लड़की जन्म के लिए भी ताने देने लगे। उनका कहना था कि अगली बार गर्भवती होने पर वंदना को चेक अप कराना होगा और लड़की हुई तो गर्भपात कराना होगा। प्रताड़ना से तंग आकर वंदना 20 दिन की बेटी को लेकर मायके मोकामा चली आईं। वंदना का कहना है कि जब वह परेशानी के दौर से गुजर रही थीं, तब ही उन्हें बाढ़ कोर्ट के अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा ने जज की परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया।

32,828 यात्री अब तक तीर्थयात्रा योजना का उठा चुके हैं लाभ। करीब 63,432 लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। ऐसे में 30,604 यात्रियों को तीर्थयात्रा कराया जाना शेष है।

नपेंगे सिविक एजेंसियों के जिम्मेदार अफसर और कर्मी

सख्त रुख ▶ होटल अर्पित और अनाज मंडी में आग की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें आरोपित बनाने का फैसला किया

अदालत के बार-बार कहने पर क्राइम ब्रांच ने उठाया है कदम

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

इस वर्ष राजधानी में आग की दो बड़ी घटनाओं करोलबाग के होटल अर्पित व फिल्मिस्तान की अनाज मंडी ने जहां लोगों को झकझोर दिया, वहीं इन मामलों में संबंधित सिविक एजेंसियों की भूमिका पर भी खूब सवाल उठे। जांच से पता चला कि आग लगने के दोनों ही मामलों में कई सिविक एजेंसियां के अधिकारी व कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में होटल मालिकों व फैक्ट्री मालिकों की मदद की। सिविक एजेंसियों के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को भी दिल्ली पुलिस मुकदमे में घसीटेगी। इन अधिकारियों व कर्मचारियों को क्राइम ब्रांच ने मुकदमे में नामजद तो नहीं किया है, लेकिन आरोप पत्र में उन्हें आरोपित बनाने का निर्णय किया है।

दरअसल, क्राइम ब्रांच ने पहले इन्हें आरोपित बनाने का निर्णय नहीं किया था। लेकिन अदालत के बार-बार निर्देश पर क्राइम ब्रांच को आरोपित बनाना पड़ेगा।

ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी बड़े हादसे में सिविक एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि जिन गंभीर धाराओं में दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हीं धाराओं में इन अधिकारियों व कर्मचरियों को भी आरोपित बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने इस संबंध में क्राइम ब्रांच को हरी झंडी दे दी है।

बीते 12 फरवरी को करोलबाग स्थित होटल अर्पित में भीषण आग लगने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उक्त मामले में करोलबाग थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा की तीन धाराओं, सुबूत मिटाने व आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर होटल के मालिक राकेश गोयल, शरद इंदु गोयल, जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार व मैनेजर विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। विस्तृत जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने 14 मई को चारों के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में 42 पेज का आरोप पत्र दायर किया था।

आरोप पत्र में बताया गया था कि होटल मालिक ने किस तरह अवैध तरीके से सिविक एजेंसी नगर निगम, अग्निशमन विभाग, आबकारी विभाग व दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग की मिलीभगत से लाइसेंस व अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया था। सभी नियम कानून को ताक पर रखकर होटल चलाया जा रहा था। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब सिविक एजेंसियों के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को आरोपित बनाते हुए पूरक आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही है।

दूसरी ओर अनाज मंडी अग्निकांड में भी 43 लोग मारे गए। क्राइम ब्रांच ने भले ही इस मामले में भी अभी केवल फैक्ट्री मालिक रिहान, उसके साले सोहेल और मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार किया है। अभी करीब दर्जन भर और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में भी निगम समेत कुछ सरकारी एजेंसियों पर सहायता करने की बात सामने आ रही है। अग्निशमन विभाग ने क्राइम ब्रांच को सफाई देते हुए कहा है कि उसने फैक्ट्री मालिक को एनओसी नहीं दी थी। श्रम विभाग ने कहा है कि उसे वहां फैक्ट्री चलने की जानकारी नहीं थी। कुछ सिविक एजेंसियों से जवाब आने बाकी है। क्राइम ब्रांच को शक है कि उक्त मौत की इमारत में अवैध रूप से 18 फैक्ट्रियां चलने के लिए कई सिविक एजेंसियां व स्थानीय थाना पुलिस भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जिन सिविक एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मियों की जिम्मेदारी का पता लगेगा क्राइम ब्रांच उन्हें भी आरोपित बनाएगी।

अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद गुरुवार को घटनास्थल की डिजिटल थ्री डी मैपिंग की गई। इस दौरान कुछ अन्य विभागों के कर्मचारी भी जांच में जुटे रहे। ध्रुव कुमार

अग्निकांड की जांच के लिए एसआइटी गठित

जासं, नई दिल्ली : अनाज मंडी अग्निकांड मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने एसआइटी गठित कर दी है। एसआइटी में दिल्ली फायर सर्विस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री व बीएसईएस के टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। एसआइटी जांच कर रिपोर्ट देगी कि इमारत में आग कैसे लगी थी। लपटें कितनी ऊंचाई तक गई थीं। इमारत में मौजूद 43 लोगों की मौत कैसे हुई। उक्त रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच अपनी जांच में शामिल करेगी। उधर, अग्निकांड मामले में बुधवार को आइएसबीटी से गिरफ्तार किए गए सोहेल को क्राइम ब्रांच ने बृहस्पतिवार को तीस हजारी कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए पांच दिन पर रिमांड पर लिया है। सोहेल की भी इमारत में तीन फैक्ट्रियां चलती थीं। वह इमारत के मालिक रिहान का रिश्ते में साला है। क्राइम ब्रांच अब रिहान के भाई इमरान की तलाश में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में हर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना वाले दिन क्राइम ब्रांच ने रिहान व उसके मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया था। उधर, घटना में घायल लोगों व इमारत के आसपास रहने वाले लोगों से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। पूरी बिल्डिंग में चार दिनों से डिजिटल थ्री डी मैपिंग कैमरे के जरिये तस्वीरें ली जा रही थीं। जिसका काम गुरुवार को पूरा हो गया। फॉरेंसिक टीम ने भी कई दिनों तक वहां पहुंचकर जांच की और नमूने उठाए।

घायलों का अस्पतालों में नहीं हो रहा मुफ्त इलाज : मनोज तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। इस योजना के जरिये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कराना पड़ रहा है।

भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दस अक्टूबर को शालीमार बाग में सड़क दुर्घटना में घायल हुई छात्रा का इलाज उसके परिजनों को खुद कराना पड़ा। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के प्रतिनिधि घायल छात्रा से मिलने जरूर गए, लेकिन सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी तरह से नारायण सिंह 26 नवंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। छह दिनों तक वह कश्मीरी गेट के ट्रामा सेंटर में भर्ती रहे। इन्हें भी सरकारी सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कई और लोगों की शिकायत भाजपा को मिली है।

उन्होंने कहा कि फरिश्ते योजना के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का मुफ्त इलाज कराने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि निजी अस्पतालों में घायल व्यक्ति से पूरा खर्च वसूला जा रहा है। इस अवसर पर अपने खर्च पर निजी अस्पताल में इलाज कराने वाली छात्रा व नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

निर्भया के दोषी की याचिका पर 17 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसियां : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड में मौत की सजा सुनाए गए चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। अक्षय ने 2017 में सुनाए गए मृत्युदंड के फैसले पर अदालत से पुनर्विचार करने की मांग की है। तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अक्षय के वकील ने यह कहते हुए मौत की सजा पर सवाल उठाया है कि प्रदूषण के चलते वैसे ही लोगों की उम्र कम हो रही है। इससे पहले पिछले साल नौ जुलाई को इस मामले के तीन अन्य दोषियों-मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। अदालत ने कहा था कि इन दोषियों के मृत्युदंड पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अदालत ने उसके चार गुनहगारों को मौत की सजा सुनाई है।

इस बीच, निर्भया की मां ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार से दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज हुए 18 महीने हो गए। कोर्ट तत्काल सजा की तारीख तय करे।

तिहाड़ में बढ़ाई जा रही फांसी घर के प्लेटफार्म की चौड़ाई

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली

▶ निर्भया के गुनहगारों को फांसी की तैयारियों में जुटा जेल प्रशासन

▶ लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

निर्भया के गुनहगारों को फांसी का आदेश मिलने से पूर्व जेल प्रशासन सभी तैयारियां कर लेना चाहता है। तिहाड़ में जेल संख्या-3 के फांसी घर में अभी एक बार में दो दोषियों को ही फांसी के फंदे पर लटकाने की व्यवस्था है। फांसी घर के ढांचे को विस्तार देकर ऊपरी प्लेटफार्म की चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है ताकि यदि जरूरत पड़े तो एक साथ चार दोषियों को भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सके। मरम्मत और निर्माण से जुड़े कार्य तेजी से चल रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे चौड़ाई बढ़ाने व पुराने ढांचे को दुरुस्त करने के कार्य में जितना संभव हो तेजी लाएं। बताते हैं कि एक सप्ताह से फांसी घर में निर्माण कार्य चल रहे हैं। उधर से गुजरने वाले रास्ते पर चुनिंदा कर्मचारियों और जेल प्रशासन के भरोसेमंद कैदियों को ही आवाजाही की अनुमति है।

गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को मिली फांसी की सजा पर अमल से जुड़ा अंतिम निर्णय होना बाकी है। जेल अधिकारियों का कहना है कि नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन यदि चारों दोषियों को फांसी देने की स्थिति आती है तो जेल प्रशासन को इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। मामला एक या दो नहीं, बल्कि चार दोषियों की फांसी का है। इसके लिए जेल प्रशासन को तैयारी हर स्तर पर करनी होगी। चाहे जल्लाद का इंतजाम हो या फांसी घर की पूरी व्यवस्था का, जेल प्रशासन पूरी तैयारी रखने में जुटा है।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दोषियों की पेशी

निर्भया की मां की याचिका पर शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। जेल प्रशासन के अनुसार इस मामले में चारों दोषियों की कोर्ट में पेशी से जुड़ा प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला है। ऐसे में सुनवाई के दौरान दोषियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये ही होगी। अधिकारियों के अनुसार सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन को इस मामले में कोर्ट को चारों दोषियों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके यह बताया जाएगा कि उन्होंने अब तक अपने किन-किन अधिकारों का इस्तेमाल किया है और उनके पास कोई विकल्प बचे हैं या नहीं।

... तो लग जाएंगे कई घंटे

सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों का मानना है कि यदि वर्तमान फांसी घर में ही दोषियों को फांसी पर लटकाने की स्थिति बनेगी तो चार दोषियों के मामले में फांसी की पूरी प्रक्रिया होने में कई घंटे लग सकते हैं। यह पूरा कार्य तनाव से भरा होगा। इसलिए फांसी की प्रक्रिया को जितनी जल्दी पूरा कर लिया जाए उतना ठीक रहेगा। हालांकि जेल प्रशासन के पास विकल्प यह भी है कि दोषियों को एक ही दिन के बजाय अलग-अलग दिन फांसी दी जाए।

अनाज मंडी में फैक्ट्रियों में बाल श्रम कराने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : अनाज मंडी में नाबालिगों से बाल श्रम कराने का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अनाज मंडी में अवैध फैक्ट्री में लगी आग की घटना में 43 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही बिहार सरकार व दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर सभी का पक्ष मांगा है। बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूल्का ने पीठ को बताया कि घटना में मरे, घायल हुए और गायब हुए लोगों में से अधिकांश नाबालिग थे।

अधिवक्ता प्रभाशय कौर के माध्यम से दायर याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे आग की घटना अस्पताल में भर्ती नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करें। एनजीओ ने मामले की जांच कर रहे प्राधिकारियों को मानव तस्करी व बाल श्रम के मद्देनजर भी प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की मांग की।

सड़क से लेकर हवा तक जेवर-आइजीआइ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का सुझाव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

आइजीआइ (इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट) को वाया तुगलकाबाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जा सकता है। तुगलकाबाद से नोएडा सेक्टर 142 को मेट्रो से जोड़ने के लिए 15 किमी लंबे ट्रैक के निर्माण की जरूरत होगी। नॉलेज पार्क दो एक्वा लाइन स्टेशन से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो की डीपीआर पहले ही यमुना प्राधिकरण डीएमआरसी से तैयार करा चुका है। राइट्स ने आइजीआइ एयरपोर्ट से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए इस रूट का सुझाव दिया है। दोनों एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सड़क व हेलीकॉप्टर सेवा का भी सुझाव दिया है। रैपिड ट्रेन से कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अव्यावहारिक बताया है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2023-24 में व्यावसायिक हवाई सेवा की शुरुआत होगी। शुरुआत में सालाना एक करोड़ बीस लाख यात्री जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने का अनुमान है। सबसे अधिक यात्री दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत एनसीआर से होंगे। आइजीआइ एयरपोर्ट समेत दिल्ली एनसीआर से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए मेट्रो, रैपिड ट्रेन, सड़क आदि का ढांचा तैयार होगा। यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसमॉडल पर राइट्स से सुझाव मांगे थे। राइट्स अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी है।

आइजीआइ एयरपोर्ट-जेवर एयरपोर्ट वाया तुगलकाबाद : दिल्ली में एयरो सिटी से तुगलकाबाद तक एक्सप्रेस मेट्रो ट्रैक का निर्माण हो रहा है। इस मेट्रो को नोएडा सेक्टर 142 में एक्वा लाइन मेट्रो से जोड़कर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने का राइट्स ने सुझाव दिया है। दोनों स्टेशन को जोड़ने के लिए करीब पंद्रह किमी का ट्रैक बनाना होगा। नॉलेज पार्क दो एक्वा मेट्रो स्टेशन से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो के लिए यमुना प्राधिकरण पहले ही डीएमआरसी से डीपीआर तैयार करा चुका है। प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट को अध्ययन के लिए एनएमआरसी को भेजा है। आइजीआइ-जेवर एयरपोर्ट मेट्रो रूट करीब 68 किमी लंबा होगा। इस रूट पर एक्सप्रेस मेट्रो चलेगी, जो चुनिंदा स्टेशन पर रुकेगी। यह दूरी चालीस से पचास मिनट में पूरी होगी।

दिल्ली-पलवल प्रस्तावित एक्सप्रेस वे से प्रस्तावित खुर्जा पलवल मार्ग को जोड़कर जेवर एयरपोर्ट को सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे जेवर एयरपोर्ट को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सोहना से गुजरने वाले प्रस्तावित पलवल रेवाड़ी एक्सप्रेस-वे से भी जेवर एयरपोर्ट जुड़ेगा। गुरुग्राम को सोहना होकर रेवाड़ी पलवल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। इस मार्ग के जरिये जेवर एयरपोर्ट गुरुग्राम होते हुए आइजीआइ एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी से हरियाणा के कई जिलों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले भी जेवर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण करने जा रहा है। केंद्र ने इस एक्सप्रेस-वे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एनएचएआइ को बल्लभगढ़-जेवर के बीच सड़क मार्ग की व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

रैपिड ट्रेन के लिए शासन स्तर पर होगी वार्ता

जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर से कनेक्टिविटी देने को एनसीआरटीसी ने अव्यावहारिक बताया है। यमुना प्राधिकरण ने एनसीआरटीसी को दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर के अशोक नगर स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट रैपिड कॉरिडोर की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा था। एनसीआरटीसी के रुख के बाद शासन स्तर से इस पर वार्ता हो सकती है। यह कॉरिडोर करीब 65 किमी लंबा होगा। इसके बनने से आइजीआइ, दिल्ली, मेरठ से यात्री सीधे जेवर एयरपोर्ट कम समय में पहुंच जाएंगे।

हेलीकॉप्टर सेवा का सुझाव

राइट्स ने आइजीआइ एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए दोनों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का भी सुझाव दिया है। इससे चंद मिनट में दोनों एयरपोर्ट के बीच की दूरी तय हो जाएगी।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आइजीआइ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए राइट्स से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर रिपोर्ट मांगी गई थी। राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है।
-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

'दमकल व फॉरेंसिक विभाग में खाली पदों को जल्द भरें'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ बैजल ने विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा

▶ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में नई तकनीक के प्रयोग पर भी बल दिया

उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने गुरुवार को दिल्ली फायर सर्विस (दमकल विभाग) और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में खाली पदों को भरने के लिए समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागीय प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा। वहीं, उपराज्यपाल ने संघ लोक सेवा आयोग एवं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से समन्वय कर पदों को शीघ्रता से भरने का निर्देश दिया।

इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), सेवा विभाग के सचिव, दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सबसे पहले दिल्ली फायर सर्विस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा विभागों में रिक्तियों की स्थिति और उन्हें भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में उपराज्यपाल को अवगत कराया गया। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक ने बताया कि गत छह महीने में विभाग में 484 स्थायी फायरमैन की नियुक्ति की गई है। संविदा के आधार पर 500 फायरमैन की भर्ती की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं, 25 रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर की भर्ती की जा रही है। जिन पदों पर फीडर कैडर में योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं उन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक ने बताया कि मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी, केमिकल और बायोलॉजिकल विश्लेषण के लिए विशिष्ट शाखाएं स्थापित की जा रही हैं। ताकि उच्च तकनीकी क्षमता का उपयोग किया जा सके। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाली पड़े नियमित पदों को भरने के लिए डीपीसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। उन्होंने सलाह दी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सेना सिग्नल कोर जैसी एजेंसियों के साथ संपर्क रखा जाए। ताकि संभावित आपदा के समय उनकी तकनीक सेवाओं का लाभ लिया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि दमकल विभाग आग बुझाने में प्रयुक्त आधुनिक तकनीक एवं रोबोट के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपराज्यपाल ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी में नई तकनीक के प्रयोग पर भी बल दिया।

पुलिस ने संसद भवन जा रहीं महिलाओं को रोका, झड़प

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद के समर्थन में गुरुवार को समर्थकों ने राजघाट से पैदल मार्च निकाला। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। हालांकि संसद भवन तक जाने की कोशिश कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बहादुर शाह जफर मार्ग पर शहीदी पार्क के सामने रोक दिया। यहां पुलिस से प्रदर्शनकारी महिलाओं की झड़प भी हुई। इसमें एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गया। कुछ महिला व पुरुषों को चोटें भी आईं। बाद में पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर दरियागंज थाना ले गई, जहां से कुछ देर बाद सभी को छोड़ दिया गया।

राजघाट पर स्वाति जयहिंद अनशन पर बैठी हैं। गुरुवार को उनके अनशन का 10वां दिन था। उनके समर्थन में दिल्ली में विभिन्न इलाकों से अनशन स्थल जुटे लोग संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे। रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने के साथ पुलिस की ओर चूड़ियां उछालने लग गए। इस पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में बहस होने लगी। इसके बाद पुलिसकर्मी बैरिकेड्स की दूसरी तरफ कूद आए और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की इस कार्रवाई पर स्वाति जयहिंद ने ट्वीट कर कहा कि एक तो सरकार खुद महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बात नहीं करती है और जब लोग इस पर बात करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें मारपीट कर भगाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस का सारा जोर केवल प्रदर्शनकारियों पर ही दिखता है। इनसे कोई भी दुष्कर्मी, चोर एवं अन्य असामाजिक तत्व डरते नहीं है।

बिगड़ती जा रही स्वाति की हालत : चिकित्सकों ने बताया कि अनशन से स्वाति की हालत बिगड़ती जा रही है। अब तक उनका वजन छह किलो से अधिक कम हो चुका है, जिससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। वहीं, स्वाति ने कहा कि वह अपना अनशन तब तक नहीं तोड़ने वाली हैं जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है।

मीडियाकर्मियों से पुलिस ने की धक्का-मुक्की : प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों की झड़प का शिकार कुछ मीडियाकर्मी भी हुए। पुलिस ने कुछ मीडियाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। इस दौरान कैमरा छीनने और उन्हें हटाने की भी कोशिश की गई। वहीं, मध्य जिला के डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा ने कहा कि उन्होंने किसी का कैमरा नहीं छीना, बल्कि वहां का माहौल देखते हुए फोटोग्राफर को पीछे होने के लिए कहा था।

महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर समता स्थल पर अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद के समर्थन में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती महिलाएं। संजय

पहल

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड एक सौ बेघरों को चालक का प्रशिक्षण दिला रहा है, परिवहन विभाग से लाइसेंस मिलने के बाद करने लगेंगे काम

अब बेघर आपको सुरक्षित पहुंचाएंगे घर

वी.के.शुक्ला, नई दिल्ली

जो लोग सड़क पर रात गुजार रहे हैं हैं उन्हें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) रैन बसेरों में भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब डूसिब इन बेघरों में से एक सौ लोगों को कमाने लायक बनाने जा रहा है। इन्हें चालक का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। सराय काले खां में एक माह से इन लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है जो अगले तीन माह में पूरा होगा। परिवहन विभाग इन्हें चालक का लाइसेंस देगा। ओएनजीसी इनके लिए फंडिंग कर रहा है।

बचाव दलों ने 2206 बेघरों को रैन बसेरों में पहुंचाया : बचाव दलों द्वारा 15 नवंबर से शुरू रेस्क्यू अभियान में अभी तक 2206 बेघरों को रैन बसेरों में भेजा गया है। सरकार इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम लगाई गई है।

वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ बनाए गए रैन बसेरे : दिल्ली में 193 रैन बसेरे स्थायी रूप से बने हैं। इसके अलावा 70 रैन बसेरों को अस्थायी रूप से बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें से 42 बना दिए गए हैं। ये रैन बसेरे यूरोपियन स्टाइल के हैं। वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ रैन बसेरे बनाए गए हैं। बेघरों को बंकर बेड उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें कंबल के साथ साथ गद्दा व तकिया भी उपलब्ध कराया गया है। डूसिब ने इस बार 17 बचाव दल बनाए हैं।

रैन बसेरे में ही करें बेघरों की मदद : डूसिब के सदस्य विपिन राय ने लोगों से फिर अपील की है कि कहीं किसी को सड़क पर कोई बेघर लेटा हुआ मिलता है तो डूसिब के एप पर सूचना दें। एप को गूगल प्ले से लोड कर लें। उन्होंने कहा कि लोग यदि किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो रैन बसेरे में करें। उससे बेघर रैन बसेरों में स्वयं जाना भी शुरू करेंगे। इन्हें सड़क किनारे कंबल न बांटें।

सड़क से बेघर को रैन बसेरा ले जाते बचाव दल के सदस्य। सौजन्य दिल्ली सरकार

आजादपुर बनेगा 2023 में मेट्रो का दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो को आने वाले वक्त में अपना दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन मिलने वाला है। आजादपुर स्टेशन 2023 तक दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन होगा। कश्मीरी गेट स्टेशन दिल्ली मेट्रो का पहला और अब तक का एकमात्र ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन है।

इस समय आजादपुर से येलो लाइन (हुडा सिटी सेंटर-समयपुर बादली) और पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) चल रही हैं। चौथे फेज में जनकपुरी वेस्ट-आरके पुरम मार्ग कॉरिडोर वाली मेट्रो का एक स्टेशन आजादपुर पर भी होगा। यह मेट्रो मजेंटा लाइन (बॉटेनिकल गार्डन-जनकपुरी वेस्ट) का एक्सटेंशन है। ट्रिपल इंटरचेंज बनाए जाने के लिए यहां जो मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, वह एलिवेटेड होगा। इस एलिवेटिड स्टेशन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने काम शुरू कर दिया है।

आजादपुर पर बनने वाला यह ट्रिपल इंटरचेंज ऐसा होगा, जिसके दो स्टेशन एलिवेटेड और एक भूमिगत हैं। नए बनने वाले स्टेशन को पहले से बने दो स्टेशनों को जोड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस फुटओवर ब्रिज की लंबाई 197 मीटर होगी।

मेट्रो के लिए आजादपुर मेट्रो स्टेशन दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज भले ही बन जाए, लेकिन यात्रियों की संख्या के लिहाज से यह कश्मीरी गेट ट्रिपल इंटरचेंज की बराबरी नहीं कर पाएगा। यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन सबसे आगे है। यहां रोजाना ढाई लाख लोग मेट्रो के जरिये पहुंचते हैं। वहीं आजादपुर पर इस समय प्रतिदिन करीब 15 हजार यात्री मेट्रो से आना-जाना करते हैं। फेज-4 के बाद इनकी संख्या तीन गुना होगा जाएगी।

तीर्थयात्रा के लिए ट्रेनों की मांग को लेकर रेलमंत्री से मिले उपमुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन रैक उपलब्ध करने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने रेलमंत्री से शीघ्र ट्रेन रैक उपलब्ध कराने की मांग की। रेलमंत्री ने उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिया है कि बहुत जल्द तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस सकारात्मक मुलाकात से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू होने की उम्मीद जगी है। उपमुख्यमंत्री ने रेलमंत्री से मिले आश्वासन को ट्वीट के माध्यम से भी साझा किया। उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को इस संबंध में कहा था कि तीर्थयात्रा योजना रेलवे के सहयोग से चल रही है। यह यात्रा तब तक स्थगित रहेगी, जब तक रेलवे ट्रेन उपलब्ध नहीं कराता है या फिर दिल्ली सरकार कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है।

15 दिसंबर को 46 कुलपतियों, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों के सम्मेलन का राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उनके साथ सामान्य संवाद का हिस्सा है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए यह सही समय

रखे विचार ▸ राज्यसभा में कानून मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में हो सकती है परीक्षा

न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका में प्रतिभाशाली लोगों को लाने के लिए आइएएस और आइपीएस जैसी केंद्रीय लोक सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने के लिए यह सही समय है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री ने कहा कि न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कुछ-कुछ यूपीएससी की तरह सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में प्रतिभाशाली लोगों को लाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए इसकी सख्त जरूरत है।

प्रसाद ने कहा कि जहां तक प्रतिभाशाली लोगों को लाने पर जोर दिए जाने का संबंध है तो हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसमें अखिल भारतीय तैनाती के अलावा नौकरियों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर तबकों के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान

राज्यसभा में गुरुवार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे पर बोलते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। एएनआइ

किया जा सकता है ताकि न्यायपालिका में भी आखिरकार उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जा सके।

एक पूरक प्रश्न के उत्तर पर कानून मंत्री ने कहा कि सरकार के समक्ष सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्टों और जिला अदालतों में न्यायिक के साथ-साथ प्रशासनिक शाखा में भी नियुक्तियां की गई है।

विधायिका में एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाने को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 10 साल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने गुरुवार को पारित कर दिया। तमाम दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सर्वसम्मति से बिल को पारित किया। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा इसे 10 दिसंबर को पारित कर चुकी है। एससी और एसटी को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 70 साल से मिल रहा आरक्षण अगले साल 25 जनवरी को खत्म हो रहा है। इस विधेयक पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म नहीं करेगी। वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी, जो संविधान की भावना के खिलाफ हो।

महिलाओं–बच्चों से जुड़े मामलों की जल्द करें जांच व सुनवाई : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कानून मंत्री ने मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्टों को पत्र लिखकर किया अनुरोध

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की त्वरित जांच और पैरवी कराने का अनुरोध किया है।

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अलग-अलग लिखे पत्रों में प्रसाद ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ऐसे में इनसे जुड़े सभी आपराधिक मामलों की दो महीने के भीतर जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कानून मंत्री ने हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से भी महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में कराने और छह महीने के भीतर इसका पूरा होना सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि 2018 में पारित आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक में जांच और सुनवाई के लिए समय सीमाएं दी गई हैं।

इस समय देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित 1.66 लाख मुकदमे विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द खत्म करने के लिए सरकार ने देश में 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। अनुमान है कि प्रत्येक फास्ट ट्रैक अदालत में इस प्रकार के 165 मुकदमों की सुनवाई होगी। कुल 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 289 अदालतें केवल 'बाल यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा' यानी 'पोक्सो' एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई करेंगी।

डाटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य नामित

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा ने एक संयुक्त संसदीय समिति के अपने 10 सदस्यों को नामित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। यह समिति व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 की समीक्षा करेगी। विधेयक को लोकसभा ने एक दिन पहले बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जिसे राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी।

समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति में जिन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है, उच्च सदन ने उनके नाम दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार समिति के सदस्यों में भूपेंद्र यादव, सुरेश प्रभु, राजीव चंद्रशेखर, अश्विनी वैष्णव, जयराम रमेश, विवेक के. तनखा, डेरेक ओ ब्रायन, नवनीतकृष्णन, रामगोपाल यादव और अमर पटनायक शामिल हैं। संयुक्त संसदीय समिति बजट सत्र की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। आम तौर पर बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है।

न्यूज गैलरी

'सुरक्षा के तहत पासपोर्ट पर छपी है कमल की तस्वीर'

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष द्वारा नए पासपोर्ट पर कमल की तस्वीर छपे होने का मुद्दा उठाए जाने पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह सुरक्षा फीचर बढ़ाने का हिस्सा है। फर्जी पासपोर्टों की पहचान करने के लिए यह किया गया है और बारी–बारी से अन्य राष्ट्रीय चिह्नों का भी प्रयोग किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस के एमके राघवन ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि एक अखबार ने इसे उजागर किया है। कांग्रेस सांसद ने इसे एक सरकारी प्रतिष्ठान का भगवाकरण करने के प्रयास का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा यह चिह्न हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और फर्जी पासपोर्ट की पहचान करने के लिए सुरक्षा फीचर बढ़ाने का यह हिस्सा है। (प्रेट्र)

रतुल पुरी की जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड डील से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को निचली अदालत से मिली जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। ईडी की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने कहा कि जमानत देते समय निचली अदालत के समक्ष पेश किए रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने 2 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद करने की मांग की। 2 दिसंबर को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए विशेष न्यायधीश अरविंद कुमार ने रतुल पर कई शर्तें लागू की थीं। अदालत ने कहा था कि पुरी न तो दस्तावेज से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे और न ही गवाहों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। (जासं)

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 10 को तय होंगे आरोप

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर के शहीद चौक पर 30 अगस्त, 2013 को हुई सभा के मामले में दर्ज मुकदमे के तहत पूर्व सांसद, विधायकों सहित सभी 10 आरोपितों के कोर्ट में एक साथ पेश न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। अब कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 10 जनवरी की तिथि मुकर्रर करते हुए सभी आरोपितों को साथ पेश होने का आदेश दिया है। 27 अगस्त, 2013 को कवाल में शाहनवाज व मलिकपुरा निवासी ममेरे–फुफुरे भाइयों सचिन व गौरव की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया था। आरोप है कि सचिन व गौरव की अंत्येष्टि से लौट रहे लोगों ने 28 अगस्त को कवाल में घरों में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद 29 अगस्त को पूर्व गृह राज्यमंत्री व सांसद सईदुज्जमां के घर पर मुस्लिम समाज की बैठक हुई। 30 अगस्त, 2013 को खालापार मोहल्ले के शहीद चौक पर जुमा की नमाज के बाद सभा की गई। इन सारे मामलों में शहर कोतवाली में तत्कालीन सांसद व बसपा नेता कादिर राना, बसपा से तत्कालीन चरथावल विधायक नूर सलीम राना, तत्कालीन विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, सलमान सईद, असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी व मुशर्रफ आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। (जासं)

बैंक धोखाधड़ी में ज्वैलर के परिसरों पर सीबीआइ छापे

नई दिल्ली : मुंबई के जाने–माने ज्वैलर 'पी एंड एस ज्वैलरी लिमिटेड' द्वारा 568 .52 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ ने मामला दर्ज करके गुरुवार को मुंबई और लोनावाला में 13 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने कंपनी के साथ–साथ इसके निदेशकों परेश शाह, साहिल परेश शाह, विराज चेतन शाह, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आइपीसी और अन्य संबंधित कानूनों के आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद सीबीआइ ने कंपनी निदेशकों के मुंबई और लोनावाला स्थित 13 परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोप है कि कंपनी ने आठ बैंकों के कंसोर्टियम से जालसाजी के जरिये कर्ज लिया था। (प्रेट्र)

तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विवि बनाने का बिल लोस से पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सभी भारतीय भाषाएं सशक्त बनाने को सरकार प्रतिबद्ध : निशंक

▸ आज राज्यसभा से भी पारित हो सकता है विधेयक

देश के तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने से जुड़ा विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जहां संभवतः यह शुक्रवार को पारित हो सकता है। वहीं लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है, यह हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। साथ ही उन्होंने तमिल सहित दूसरी सभी भारतीय भाषाओं को भी सशक्त बनाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

इस बीच संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के विधेयक पर लोकसभा में करीब पांच घंटे चर्चा हुई। इस चर्चा में दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले सांसदों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही तमिल, असमिया सहित क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को भी मजबूत बनाने की जरूरत बताई। इसका केंद्रीय मंत्री निशंक ने जवाब दिया। वहीं बसपा सांसद दानिश अली के सवाल का भी जवाब दिया। इसमें उन्होंने बीएचयू के संस्कृत विभाग से जुड़े शिक्षक फिरोज खान को लेकर सवाल पूछा था। निशंक ने कहा कि फिरोज खान बीएचयू के संस्कृत विभाग में शिक्षक हैं, और इसी विभाग में वह आगे शिक्षण कार्य करते रहेंगे। इस बीच,

रमेश पोखरियाल निशंक फाइल

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने चर्चा को उस समय रोचक बना दिया, जब उन्होंने अमेरिकी संस्थान में हुए शोध का हवाला देते हुए कहा कि संस्कृत प्रतिदिन पढ़ने से तंत्रिका तंत्र जहां सक्रिय रहती है, वहीं ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर भी सामान्य बना रहता है। फिलहाल जिन तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विवि बनाने का फैसला लिया गया है, उन्हें अभी डीम्ड विवि का दर्जा प्राप्त है। इन संस्थानों में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली का स्थापना 1970 में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली की स्थापना 1962 में और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति की स्थापना 1961 में की गई थी।

अनुच्छेद 370 का मामला सात सदस्यों की पीठ को भेजने पर विचार बाद में

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिए कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद ही वह इस मामले को सात सदस्यीय बड़ी पीठ को भेजने पर विचार कर सकता है।

दरअसल, अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाले कुछ पक्षों ने कहा कि शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ 1959 और 1970 में दो विरोधाभासी फैसले सुना चुकी हैं, लिहाजा इस मामले को सात सदस्यीय पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। इस पर जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, 'हम सभी पक्षों की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद ही मामले को बड़ी पीठ में भेजने के सवाल पर विचार कर सकते हैं।' सुनवाई के दौरान केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि अदालत को पहले अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाले पक्षकारों को सुनना चाहिए और उसके बाद ही उन पक्षकारों के वकीलों को सुनना चाहिए जो मामले को बड़ी पीठ में भेजने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता शाह फैसल, शेहला राशिद और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से पीठ ने बुधवार को कुछ सवाल किए थे, उन्होंने गुरुवार को उनके जवाब दिए।

यूजीसी तय करेगा सरकारी और निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस

नईदुनिया, भोपाल

देश के सरकारी और निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों की फीस अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तय करेगा। किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी फीस होगी यह तय करने के लिए सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों से उनकी आय और व्यय की जानकारी ऑनलाइन मांगी जाएगी।

कोई भी विश्वविद्यालय सालभर में जितनी राशि फैकल्टी के वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा, उससे अधिकतम 15 फीसद अधिक राशि वह फीस के तौर पर वसूल सकेगा। आयोग ने इस संबंध में यूजीसी फीस रेग्युलेशन ड्राफ्ट-2019 के तहत दावे आपत्तियां मंगाई हैं। इसके बाद फीस तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

खर्च रिपोर्ट बनेगी आधार : यूजीसी सचिव रजनीश जैन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खर्च की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस विश्वविद्यालय को छात्र संख्या के हिसाब से कितनी फीस वसूलने का अधिकार होगा। इस फैसले के बाद उन विश्वविद्यालयों पर लगाम लग सकेगी, जो छात्रों से मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं।

देश के 845 विवि पर पड़ेगा असर : यूजीसी के इस फैसले का असर देशभर में

यूजीसी दफ्तर। फाइल

यूजीसी की ओर से निजी विश्वविद्यालयों की फीस निर्धारण के लिए बनने वाली कमेटी से संबंधित पत्र मिल गया है। जल्द ही प्राइवेट विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक बुलाकर इस संबंध में यूजीसी को सुझाव भेजे जाएंगे।
–कमलाकर सिंह, चेयरमैन एएफआरसी

वर्तमान में कई छात्रों की ओर से विश्वविद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूलने की शिकायत आ रही है। इसी मकसद से फीस कमेटी का गठन किया जा रहा है। इससे मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगेगी।'
– डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी

व्यावसायिक और पारंपरिक कोर्स चला रहे करीब 845 विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों की फीस वे अपने स्तर पर ही तय कर लेते हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश में इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन किया है। लेकिन यह आयोग सिर्फ समीक्षा कर पाता है। उसे फीस में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।

10 लाख तक होगा जुर्माना : यूजीसी के ड्राफ्ट के मुताबिक यदि कोई सरकारी या निजी विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग की फीस कमेटी को उस पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उस विश्वविद्यालय की मान्यता भी निरस्त की जा सकेगी। कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का रहेगा। किसी भी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति या कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था का प्रमुख इस कमेटी का अध्यक्ष बन सकेगा। इसकी नियुक्ति यूजीसी की ओर से की जाएगी। शिक्षाविद और प्रोफेसर इसके सदस्य बन सकेंगे।

यह होते हैं डीम्ड विवि : डीम्ड विश्वविद्यालय उन्हें कहा जाता है, जिनकी मान्यता यूजीसी की ओर से दी जाती है। डीम्ड विवि का दर्जा प्राप्त संस्थान न केवल अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त करते हैं, बल्कि प्रवेश नीति, विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क तथा छात्रों के लिए निर्देश बनाने को भी स्वतंत्र होते हैं।

जहरीली हुई आबोहवा को लेकर केंद्र सतर्क, एजेंसियों से मांगा ब्योरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अगले एक–दो दिनों में सुधार की जताई उम्मीद

▸ ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के तहत जरूरी उपाय करने के निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के साथ ही फिर से हो-हल्ला शुरू हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित प्रदूषण की रोकथाम के लिए गठित एजेंसियों से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली है। राहत की बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है जिसके चलते अगले एक-दो दिन में प्रदूषण स्तर में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। पिछले दिनों राज्य सरकारों और इससे जुड़ी एजेंसियों की निष्क्रियता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। लिहाजा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों से उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा मांगने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के तहत जरूरी उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदूषण

नई दिल्ली–लाल किले के सामने प्रदूषण से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए घूमते पर्यटक। ध्रुव कुमार

स्तर में यह बढ़ोतरी तब हुई है जब पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण के पीछे पराली को एक बड़ी वजह बताया जा रहा था। हालांकि इसके जलाए जाने की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी के कारणों को लेकर एजेंसियां भी चुप हैं।

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है जबकि पीएम-2.5 का स्तर 268 के आसपास पहुंच गया है जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी 'सफर इंडिया' ने पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा के खराब होने को लेकर चेतावनी जारी की थी, लेकिन एजेंसियां चुप बैठ रहीं।

हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग : वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले संस्थानों के संगठन 'क्लीन एयर कलेक्टिव' ने प्रधानमंत्री से हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की है। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का मानना है कि अभी हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने जैसे हालात नहीं हैं। एक दिन में इसकी घोषणा नहीं की जाती।

दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदूषण पर रोकथाम के लिए उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं जिससे स्थिति बदतर होती जा रही है।

भारत और मालदीव के संयुक्त आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : अपने सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए भारत और मालदीव के विदेश मंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की यह बैठक चार साल बाद होगी। इससे पहले दोनों देशों के संयुक्त आयोग की पांच बार बैठकें हो चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत वार्ता होगी। शाहिद चार दिन की यात्रा पर मंगलवार को भारत आ चुके हैं। उनके साथ 31 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। बुधवार को विदेश मंत्री शाहिद की भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले से द्विपक्षीय संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। प्रवक्ता ने कहा, दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की वार्ता और आपसी संबंधों की गर्मजोशी बताती है कि हमारे बीच सहयोग का दायरा बढ़ रहा है। पिछले ही सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का खास दोस्त और समुद्री इलाके का दोस्त मालदीव के विकास के लिए भारत वचनबद्ध है।

कोर्ट ने कहा–सच्चाई सामने आना जरूरी

प्रथम पृष्ठ से आगे

गुरुवार को सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। मुठभेड़ की जांच एसआइटी को सौंपी गई है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद कहा कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए घटना की सच्चाई सामने आना जरूरी हो जाता है। चारों आरोपितों की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हुई है। ऐसे में इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करते हुए कहा कि इस आयोग को जांच आयोग कानून के तहत सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग हैदराबाद में बैठेगा और मामले की जांच करके छह महीने में रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग को सारी सुविधाएं तेलंगाना सरकार मुहैया कराएगी और सुरक्षा सीआरपीएफ देगी। कोर्ट ने वकील के. परासरन को आयोग का वकील नियुक्त किया है।

रिपोर्ट आने तक कोई भी कोर्ट या एजेंसी नहीं करेगी जांच : कोर्ट ने कहा है कि जब तक आयोग की जांच चलेगी तब तक कोई भी दूसरी अथॉरिटी या कोर्ट मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। आरोपितों के शव सुरक्षित रखने का हाई कोर्ट का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि घटना की जांच कर रही राज्य द्वारा गठित एएसआइटी अपनी जांच जारी रखेगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने पहले मीडिया का पक्ष सुनने का मन बनाया है और कोर्ट ने इस संबंध में पीटीआइ और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।

निष्पक्ष जांच जरूरी : सुनवाई के दौरान जब तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुठभेड़ मामले में एफआइआर दर्ज हुई है तो कोर्ट का सवाल था कि जब चारों मर गए हैं तो उस केस में जिरह कैसे होगी। कोर्ट ने कहा कि वह अभी यह नहीं कह रहे कि पुलिस दोषी है या गलत है, लेकिन उनका मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि देश की जनता के समक्ष सही जानकारी जा सके। साथ ही अगर पुलिस गलत है तो कार्रवाई हो सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

बदलेगा 'इतिहास'

अब अकबर नहीं, महाराणा प्रताप व चंद्रगुप्त होंगे महान

छठी से 12वीं कक्षा तक का इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बदला, अगले सत्र से प्रदेश के 15 लाख छात्र पढ़ेंगे नए सिरे से इतिहास

बलवान शर्मा, भिवानी

अकबर व सिकंदर दी ग्रेट के दिन लदते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में छठी से 12वीं कक्षा के छात्र अब इतिहास में महाराणा प्रताप व चंद्रगुप्त मौर्य महान को पढ़ेंगे। प्रदेश में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम को बदल दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से नई पुस्तकें तैयार कर दी गई हैं। हालांकि इन पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग का कार्य अभी पेंडिंग है। नए सत्र से प्रदेश के 15 लाख से अधिक छात्रों को नया इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा।

दरअसल, केंद्रीय मानव संशाधन मंत्रालय ने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए 25 अप्रैल 2017 को देशभर के शिक्षा बोर्डों के चेयरमैन व अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। हरियाणा में पाठ्यक्रम को बदलने के लिए एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) और शिक्षा बोर्ड की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही शिक्षा बोर्ड को इतिहास की पुस्तकें प्रकाशित करने का दायित्व भी सौंपा गया था। अब छठी से दसवीं कक्षा तक के इतिहास

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दफ्तर। फाइल

में बदलाव कर पुस्तकें तैयार भी कर ली गई हैं। इनमें त्रुटियों को ठीक करने के लिए दोनों संस्थाओं के दस सदस्यों की एससीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की हुई है। इस कमेटी की 10 दिसंबर को गुरुग्राम में बैठक होनी थी, लेकिन निदेशक के नहीं होने की वजह से स्थगित कर दी गई।

बोर्ड के चेयरमैन डा. जगबीर सिंह ने की पुष्टि : इस संबंध में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. जगबीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि नए पाठ्यक्रम में आमूलचूल बदलाव किया गया है। अब हमारे प्रदेश के छात्र अकबर महान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि महाराणा प्रताप व चंद्रगुप्त महान को पढ़ेंगे। मुगलकाल के चैप्टर भी छोटा कर दिया गया है। अब तक पढ़ाए जा रहे इतिहास में छठी से आठवीं कक्षा तक अलग पाठ्यक्रम था और नौवीं से 12वीं तक अलग। ऐसे में आठवीं से आगे नौवीं में इतिहास की तारतम्यता (सतता) टूट रही थी। अब छात्रों को सिलसिलेवार इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा।

30 नवंबर से रिक्त है निदेशक का पद

एससीईआरटी निदेशक का पद 30 नवंबर से रिक्त पड़ा। इससे पहले यह कार्यभार सुमन नैन के पास था। बताया जा रहा है कि नए निदेशक के आने के बाद दोबारा से कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही निदेशक की नियुक्ति होगी।

शिविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज

जासं, नई दिल्ली : रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज गुलशन कुमार ने कहा कि जमानत देने से वह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि शिविंदर के भाई व फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर मालविंदर सिंह के अलावा सुनील गोधवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना को आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के फंड के गबन में गिरफ्तार किया था।

DR. RAMASWAMY IAS ACADEMY
FREE COACHING
IAS, SSC, JUDICIARY AND GROUP-A, B & C
SC/ST/EWS/OBC DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144, 9958589406
Centre-1 1418, Dr. Mukherjee Nagar, 4th Floor, Main Road, New Delhi-09
Centre-2 4-A/17, Old Rajendra Nagar Main Market, New Delhi-110060

15 विधानसभा सीटों पर 16 दिसंबर को मतदान होना है झारखंड में चौथे चरण में। इसमें 221 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें 75 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनपर किसी न किसी आरोप में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 13 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बनेंगे मदर वेटिंग सेंटर

देहरादून : उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इनके लिए मदर वेटिंग रूम बनाने जा रहा है। इस योजना के तहत इन स्थानों पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पहले भर्ती किया जाएगा। यहां इनके इलाज के लिए सहायकों को भी रखा जाएगा। देहरादून में भी इसी तरह का वेटिंग रूम बनाने की योजना है। यहां के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को बच्चों को जन्म देते समय खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण दूरस्थ इलाकों में महिला अस्पतालों का न होना है। ऐसे में महिलाओं को जिला अस्पताल तक आना पड़ता है। कई बार ऐसे मामले भी आए हैं जब गर्भवती महिलाओं ने रास्ते में ही बच्चों को जन्म दिया है। गर्भवती महिलाओं के जटिल मामलों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मदर वेटिंग रूम बनाने का निर्णय लिया है। अपर सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि जल्द ही इस योजना को शुरू किया जा रहा। इससे गर्भवती महिलाओं की समस्याएं कम होंगी। (जासं)

मप्र भाजपा अध्यक्ष को लेकर असमंजस जारी

भोपाल : मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के निर्वाचन से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राममाधव और प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने रायशुमारी पूरी कर ली है। मप्र कोर ग्रुप के नेताओं से उन्होंने इंदौर, देवास और दिल्ली में अलग-अलग बातचीत की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनकी रायशुमारी लगभग पूरी हो चुकी है। वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और दावेदारों को लेकर असमंजस अब भी बना हुआ है। भाजपा नेताओं का मानना है कि शुक्रवार को संसद सत्र खत्म होने के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राममाधव व अन्य नेताओं से इस मामले में बातचीत कर सकता है। दूसरी खास बात यह है कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रणनीति तय नहीं कर पा रहे हैं। संघ की सिफारिश के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख तय होगी। (नईदुनिया)

भाजपा नेता विनय कटियार को जान से मारने की धमकी

नई दिल्ली : भाजपा के फायर ब्रांड नेता रहे और पूर्व सांसद विनय कटियार को जान से मारने की धमकी मिली है। नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कटियार 11 दिसंबर की रात नॉर्थ एवेन्यू स्थित एमपी फ्लैट में थे। रात सवा आठ बजे किसी अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल फोन पर कॉल आई। यह आश्वस्त होने के बाद की दूसरी तरफ वह (विनय) हैं, कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारे दिन बहुत कम रहे गए हैं, हम तुम्हें मार देंगे। पूछने पर बताया कि वह जंतर-मंतर से बोल रहा है। इसके बाद कटियार ने अपना फोन बंद कर दिया। उनके निजी सुरक्षा कर्मी ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। (जासं)

चुनावी रण ▸ रक्षा मंत्री ने झारखंड के पाकुड़ और गिरिडीह में की सभा

'भाजपा ने मजहब के आधार पर कोई काम नहीं किया'

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

जागरण संवाददाता, पाकुड़

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को झारखंड में चौथे चरण के चुनाव के लिए पाकुड़ और गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि पाकिस्तान में उत्पीड़न के शिकार हो रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही उनकी सरकार यह विधेयक लाई है। भाजपा ने कभी भी मजहब के आधार पर कोई काम नहीं किया है। पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, जैन आदि की आबादी घटी, लेकिन भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, क्योंकि हमने सभी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, मजबूत सरकार के दम पर हमने पाकिस्तान को कई सबक सिखाए हैं। इसका परिणाम है कि अब आंख दिखाने की जुर्रत पड़ोसी नहीं कर रहा है। साथ ही, देश की आजादी के 70 साल से लंबित मामला 370 को भाजपा सरकार ने हटाकर देश में 'एक विधान, एक निशान व एक प्रधान' की व्यवस्था कायम की है।

उन्होंने कहा कि रघुवर दास से आप खुश हों या नहीं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। भाजपा के किसी प्रधानमंत्री और मंत्री पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। राजनाथ ने कहा कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ है, वहां भव्य मंदिर के निर्माण को अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया दिया है। यह सब भाजपा के शासन काल में हुआ। ऐसे में हमारी पार्टी जो कहती है, उसे पूरा करती है।

रक्षा मंत्री ने प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में बंदूक संस्कृति को इजाजत नहीं दी जा सकती है। बंदूक के दम पर दहशत फैलाने के इरादे रखने वाले लोगों से सरकार किसी तरह की बात नहीं करेगी। झारखंड को काफी हद तक इससे मुक्ति मिली है। देश को इस रोग से छुटकारा दिलाया जाएगा।

गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र स्थित देवरी में गुरुवार को आयोजित चुनावी सभा में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते कार्यकर्ता। जागरण

तीसरे चरण में 62.35 फीसद लोगों ने किया मतदान

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1.67 फीसद कम पड़े वोट

झारखंड विधानसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही चुनाव मैदान में खड़े 309 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। गुरुवार को इस चरण की 17 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग में कुल 62.35 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

हालांकि 2014 की तुलना में यह 1.67 फीसद कम है। वोटिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले दो चरणों की ही तरह इस चरण में भी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक मतदान हुआ। सिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 76.98 तथा रांची में सबसे कम 49.10 फीसद वोटिंग हुई। हालांकि विधानसभा चुनाव 2014 की तुलना में रांची में इस बार 0.47 फीसद अधिक मतदान हुआ। कांके में भी मतदान फीसद बढ़ा है, लेकिन हटिया में इसमें कमी आई है। सिल्ली में सबसे अधिक मतदान होने के बाद भी पिछले विस चुनाव की अपेक्षा मतदान फीसद में आंशिक कमी आई है।

हजारीबाग में 13.54 फीसद कम मतदान : मतदाताओं को जागरूक करने की लाख प्रयासों के बावजूद हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ने के बजाय 13.54 फीसद घट गया। विधानसभा चुनाव 2014 में कुल 70.72 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इससे इतर इस बार 57.18 फीसद ही वोटिंग हुई।

रांची में गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक केंद्र पर मतदान करने के बाद बाहर निकलते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी और उनकी पत्नी साक्षी। जागरण

इनामी नक्सली महाराज के माता-पिता ने लोकतंत्र पर जताई आस्था, डाला वोट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में ईचागढ़ विस क्षेत्र में गुरुवार को हुए मतदान में इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक के माता-पिता ने लोकतंत्र में आस्था जताते हुए वोट डाला। ईचागढ़ प्रखंड के दारुदा निवासी महाराज प्रमाणिक के पिता जरासिंधू प्रमाणिक और मां नीलमणि देवी ने आमंद्री गांव स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। दोनों ने कहा कि हर नागरिक को सरकार चुनने के लिए मतदान का अधिकार है। मतदाताओं को चाहिए कि वे सजग होकर निश्चित रूप से मतदान कर अपनी पसंद की सरकार चुनें। राज्य में सरकार लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ क्षेत्र की जनता के विकास का खयाल रखें इन्हीं आशाओं के साथ हमने मतदान किया।

पति का शव घर पर छोड़ वृद्धा ने पहले किया मतदान : लोकतंत्र में मताधिकार का क्या महत्व है यह गुरुवार को बोकारो में कारो बस्ती की वृद्धा रेणु देवी ने लोगों को समझाया। दरअसल, रेणु देवी के पति ईश्वर करमाली (63) की मौत बुधवार की रात ठंड लगने से हो गई थी। इस कारण उसका पूरा परिवार शोक में डूबा था। इसके बावजूद गुरुवार की अहले सुबह रेणु ने सबसे पहले लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान किया। इसके बाद वह घर लौट आई। बाद में उसके पति के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान रेणु ने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते, उन्हें सरकार को भला-बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

'सरकार बनी तो तीन दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे'

जागरण संवाददाता, साहिबगंज

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई की आड़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को साहिबगंज के राजमहल में उनकी जनसभा पुराने मुद्दों के इर्दगिर्द ही रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने लगातार तंज कसा। इतना तक कहा कि उन्हें महंगाई की फिक्र नहीं है और वह दूसरी दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो दो से तीन दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून सख्ती से लागू होगा। उनके भाषण में भावुकता का भी पुट दिखा। कहा, झारखंड के लोग गरीब हैं झारखंड नहीं। गठबंधन की सरकार बनी तो आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप माल खरीदना शुरू कर देंगे। यहां की भी अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ जैसी हो जाएगी।

सभा में लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नागरिकता संशोधन विधेयक पर कुछ बोलेंगे क्योंकि यह इलाका घुसपैठ प्रभावित है। लेकिन राहुल ने इसे छुआ तक नहीं। अपना संबोधन महंगाई व भूमि अधिग्रहण बिल के इर्दगिर्द ही रखा। कहा, कांग्रेस सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लाई तो भाजपा ने विरोध किया था। यह बिल किसानों के हित में है। पहले गरीबों की जमीन छीन ली जाती थी। नए भूमि अधिग्रहण कानून में गरीबों से पूछे बिना उनकी जमीन नहीं ली जा सकती है। जमीन लेने पर बाजार दर का चार गुना भुगतान करना होगा। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां यह कानून सख्ती से लागू है। इसमें यह भी प्रावधान है कि पांच साल तक जमीन का उपयोग न होने पर मालिक को वापस कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसानों की जमीन वापस की गई है।

झारखंड के राजमहल में गुरुवार को कांग्रेस की चुनावी जनसभा के दौरान दैनिक जागरण पढ़ते पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। जागरण

महाविकास अघाड़ी सरकार में विभागों का बंटवारा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के पंद्रहवें दिन गुरुवार को अपने छोटे से मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। माना जा रहा है कि वह 23 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। पिछले माह 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के दो-दो मंत्रियों ने भी शपथ ली थी।

इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे को तथा उद्योग, उच्च शिक्षा, रोजगार एवं कृषि शिवसेना के ही दूसरे मंत्री सुभाष देसाई को दिया गया है। कांग्रेस के बालासाहब थोरात को राजस्व एवं ऊर्जा तथा डॉ. नितिन राऊत को सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया है। राकांपा के छगन भुजबल को ग्रामीण विकास एवं जल संपदा तथा जयंत पाटिल को वित्त, योजना तथा आवास निर्माण विभाग दिए गए हैं। इन सभी मंत्रियों को इन विभागों के अलावा भी कई विभाग दिए गए हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद 23 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों में फेरबदल करेंगे।

महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा की गठबंधन सरकार बनी है। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद स्पष्ट हो गया है कि उद्धव ठाकरे अपने पास कम से कम विभाग रखते हुए सरकार पर वर्चस्व प्रदर्शित करना चाहते हैं ताकि उनके मतदाताओं में कांग्रेस-राकांपा के दबाव में काम करने का संकेत न जाए। इसके लिए ही उन्होंने गृह विभाग शिवसेना के मंत्री के पास रखा है। महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्याओं के लिए बदनाम रहा है। इस बार हुई बेमौसम बरसात के कारण किसानों का संकट और बढ़ गया है। अब तक शहरी क्षेत्रों में ही प्रभावी रही शिवसेना के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिए उद्धव किसानों से सीधे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कृषि मंत्रालय भी शिवसेना के ही पास रखा है। माना जा रहा है वह जल्द ही किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर उनके बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

मुंबई में गुरुवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार (बाएं) को उनके 79वें जन्मदिन पर बधाई देते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

राकांपा ने धूमधाम से मनाया शरद पवार का जन्मदिन

राज्य ब्यूरो, मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का 79वां जन्मदिन गुरुवार को मुंबई में पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार का गाइड बताते हुए बधाई दी। मराठा क्षत्रप के नाम से जाने जाने वाले शरद पवार का जन्मदिन इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में बनी शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन की महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार का शिल्पकार उन्हें ही माना जा रहा है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान 79 वर्षीय शरद पवार ने पांव में चोट के बावजूद न सिर्फ जमकर चुनाव प्रचार किया, बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना के नेतृत्व में बनी नई सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। केक काटकर और पवार के सिर पर साफा बांधकर उनका जन्मदिन मनाया गया। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार भले ही 80 वर्ष के होने जा रहे हों, लेकिन उनकी सक्रियता से युवाओं को सबक लेने की जरूरत है।

सीबीआइ 'कर' के नाम पर उद्योगपतियों को किया जा रहा भयभीत : ममता

जागरण टीम, कोलकाता

▸ केंद्र पर साधा निशाना, कहा, इस परिस्थिति में संभव नहीं कारोबार करना

▸ आयकर, सीमा शुल्क के अलावा भी है उद्योगपतियों के समक्ष समस्याएं

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में उद्योगपति को नियमित कर के अलावा सीबीआइ कर भुगतान करने को लेकर भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ कर से उनका मतलब केंद्रीय जांच एजेंसी से मंजूरी मिलने से है। पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत पर्यटननगरी दीघा में आयोजित बिजनेस समिट 2019 के दूसरे व आखिरी दिन उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि मुझे उद्योग जगत के अपने मित्रों से पता चला कि वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको कई तरह के कर देने होते हैं। आयकर, सीमाशुल्क, सीबीआइ कर आदि, हर कोई व्यापार करने को लेकर भयभीत है। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि आज उद्योगपतियों के समक्ष बहुत से मानसिक तनाव हैं और अगर यह जारी रहा तो उनके लिए व्यापार करना संभव नहीं होगा।

24 महीने में शुरू होगा देवचा पचामी कोयला ब्लॉक में उत्पादन : ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बीरभूम जिले में देवचा पचामी कोयला ब्लॉक में 24 महीने के भीतर उत्पादन शुरू करना है। उन्होंने कहा कि देवचा पचामी कोयला ब्लॉक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है और इसमें अनुमानित कोयला भंडार 2.1 अरब टन है। उन्होंने कहा कि परियोजना पर काम तुरंत शुरू कराने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं। लेकिन कुछ इलाके में जमीन को लेकर कुछ समस्याएं हैं जिसमें कुछ समय लगेगा। बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ भूखंड पर हमलोग अगले सात दिन में काम शुरू कर देंगे और 24 महीने के भीतर कोयला ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने बीरभूम के दक्षिण-पश्चिम भाग में देवचा-पचामी ब्लॉक और जिले के पश्चिमी छोर पर दीवानगंज हरिनसिंघा ब्लॉक आवंटित किया है।

मनोहर लाल ने कहा, बगैर चुनाव के नेहरू का पीएम बनना थी अक्षम्य चूक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के बंटवारे के बाद पं. जवाहर लाल नेहरू को बगैर चुनाव के ही पहला प्रधानमंत्री बनाए जाने को अक्षम्य चूक बताया है। उन्होंने कहा कि देश के आजाद होते ही सत्ता का स्वाद चखने की जल्दबाजी में गलत फैसले लिए गए, जिसका खामियाजा लंबे समय तक देशवासियों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल की कश्मीर समस्या पर आधारित किताब 'नेहरूस हिमालयन ब्लंडर्स द एक्सेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' का विमोचन करते हुए यह बात कही। किताब में कश्मीर की समस्या के लिए जवाहर लाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया है।

किताब में कश्मीर के मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं और पंडित नेहरू की कथित गलतियों का जिक्र किया गया है। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का वेब पोर्टल लांच करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल बाद यह मौका आया है जब यह किताब विमोचित हुई। अगली पुस्तक 70 साल बाद आएगी जिसका टाइटल होगा 'नेहरूस हिमालयन ब्लंडर्स अपडन बाइ मोदी एंड शाह'। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय हर रियासत अपना- अपना झंडा, अपना-अपना संविधान बना सकते थे, परंतु सरदार पटेल ने आवाज बुलंद की और तीन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी को एक झंडे और एक संविधान के लिए मना लिया। सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर के शासकों ने विरोध किया जिसके बाद सरदार पटेल ने अंगुली टेढ़ी की तो जूनागढ़ और हैदराबाद भी मान गए।

मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का कोई इतिहास लिखित में नहीं है। तब ऐसी स्थिति बनी कि उसे भारत में मिला नहीं पाए। 26 अक्टूबर, 1947 को विलय के लिए महाराजा हरि सिंह ने लिख दिया था। 27 अक्टूबर को हमारी सेना भी चली गई थी, लेकिन नेहरू, हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने बंद कमरे में जम्मू-कश्मीर को अलग रियासत का दर्जा देने की गलती कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगातार इसका विरोध किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश धर्म के नाम पर विभाजित हुआ जिसके लिए नेहरू और मुहम्मद अली जिन्ना के साथ ही दूसरे कई लोग जिम्मेदार हैं। आज नागरिकता संशोधन बिल भी इसी वजह से लाना पड़ा है। देश के बंटवारे के समय जो स्टैंड अच्छे नेताओं को लेना चहिए था, वह सत्ता को चखने की जल्दबाजी में नहीं लिया गया। महात्मा गांधी के सुझाव को दरकिनार कर बगैर चुनाव के जवाहर लाल नेहरू का पीएम बनना सबसे बड़ा ब्लंडर था।

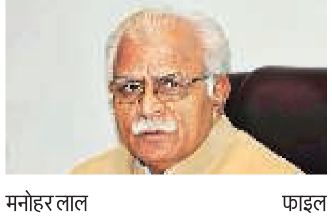
मनोहर लाल फाइल

पिता की जयंती पर आर-पार के मूड में दिखीं पंकजा मुंडे

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र भाजपा में पैदा हुई फूट गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के सामने ही खुलकर सामने आ गई। अपनी हार का ठीकरा भाजपा के ही कुछ बड़े नेताओं पर फोड़ती आ रहीं पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने यह कहकर आर-पार की लड़ाई के संकेत दे दिए कि वह पार्टी नहीं छोड़ने जा रहीं। पार्टी चाहे तो उन्हें छोड़ दे। इसी मंच पर दूसरे असंतुष्ट नेता एकनाथ खडसे भी आज अपने साथ हुए अन्याय पर जमकर बरसे।

अवसर था भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की जयंती का। उनकी पुत्री पंकजा मुंडे ने इस अवसर को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हुए पिता की समाधि परली स्थित 'गोपीनाथ गढ़' पर बड़ा जमावड़ा किया और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सवाल किया कि मेरे पार्टी छोड़ने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है, इस पर शोध कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में हूं, लेकिन पार्टी को मुझे रखना है या नहीं, यह विचार वही करे।

भविष्य की योजना का खुलासा करते हुए पंकजा ने कहा कि मैं महिला, किसान, मजदूर और पिछड़ों-वंचितों जैसे बहुजनों का संगठन तैयार करनेवाली हूं। 27 जनवरी को मराठवाड़ा के केंद्र औरंगाबाद में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखूंगी और फिर पूरे महाराष्ट्र में मशाल यात्रा निकालूंगी। पंकजा ने गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान नामक संगठन बनाकर गरीबों-वंचितों को इकट्ठा करने की घोषणा भी की। माना जा रहा है कि पंकजा अपने पिता के नाम पर प्रतिष्ठान बनाकर भाजपा के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बनाकर पार्टी नेतृत्व को अपनी ताकत का अहसास कराएंगी। इस अवसर पर खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करते आ रहे वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे भी जमकर पार्टी पर बरसे। भाजपा ने इस बार उनका टिकट काटकर अंतिम समय में उनकी पुत्री रोहिणी खडसे को टिकट दिया था, लेकिन वह हार गईं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी और पंकजा की हार के पीछे साजिश है।

असंतोष

कहा, महावत के हाथ कमान देने से काम नहीं चलेगा, जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं व विधायकों में बढ़ रही बेचैनी, कांग्रेस विधायकों की शिकायत, अपनी सरकार में ही उनकी सुनवाई नहीं

जाखड़ की नसीहत, कैप्टन खुद संभालें कमान

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब में आम लोगों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों में बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सरकार की कमान खुद संभालने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वह जमीन पर हो भी रहे हैं या नहीं, यह तो कैप्टन को ही देखना है। इसके लिए मुख्यमंत्री क्या तरीका अपनाते हैं, यह उन पर निर्भर है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक ही बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी इस तरह हावी है कि उनकी भी नहीं सुनती है।

जाखड़ ने पानीपत की लड़ाई का उदाहरण देते हुए बताया कि बाबर ने जब पहली बार हाथी की सवारी की तो पूछा कि इसकी कमान कहां है? तो उसके संतरियों ने बताया कि कमान तो महावत के हाथ है। इस पर बाबर ने कहा कि जिस चीज की कमान उनके हाथ में नहीं, वह ऐसी किसी भी चीज की सवारी नहीं करेंगे। जाखड़ ने कहा कि अब मौका आ गया है कि सरकार की कमान महावत के हाथ न देकर कैप्टन खुद संभालें।

जाखड़ ने कहा कि कैप्टन की इमेज बहुत बड़ी है और उनके कंधों पर इस इमेज का ही बोझ है। चुनाव में कैप्टन ने जो वादे किए उसे देखकर जनता ने उम्मीद से ज्यादा 77 सीटें कांग्रेस को दीं। मुझे लगता है कि इससे लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत बढ़ गईं और हम उतनी डिलीवरी नहीं कर पाए। इसलिए लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के महकमों को बदलना है, ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर बदलाव करना है, यह तो वह खुद ही जानते हैं।

एक सवाल के जवाब में जाखड़ ने कहा कि सरकार में विजन की कोई कमी नहीं है। कर्ज माफी जैसी योजनाएं हमने आते ही लागू कर दीं। अगर हम चाहते तो इसे अकालियों की तरह यह कहकर टाल सकते थे कि हमें पांच साल का जनादेश मिला है, अंतिम साल में कर देंगे।

हम सब कुछ केंद्र पर नहीं डाल सकते : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय संकट भी आड़े आ रहा है, लेकिन हम सारा कुछ केंद्र पर नहीं डाल सकते। केंद्रीय योजनाओं को लाना, उसे लागू करवाना आदि तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को ही करना है।

सुनील जाखड़ फाइल

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

हलका इंचार्ज सिस्टम नहीं लागू होगा

जाखड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हलका इंचार्ज का सिस्टम हम लागू नहीं करेंगे। यह अकाली दल का मॉडल है। हमारा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी आम लोगों के काम सही तरीके से करे ताकि जनता को विधायकों के पास न जाना पड़े। काम न होने के कारण ही विधायकों की परेशानी बढ़ती है। आखिर उनकी तो जनता के प्रति जवाबदेही है।

हाई कोर्ट ने मुकुल को अपनी आवाज का नमूना देने को कहा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल महानगर के बड़ाबाजार इलाके से 90 लाख रुपये की जब्ती के मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय को अपनी आवाज का नमूना दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें 31 जुलाई, 2018 को बड़ाबाजार इलाके से 90 लाख रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर और भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं। गिरफ्तार लोगों में से एक के मोबाइल फोन की कॉल लिस्ट में मुकुल रॉय का नंबर पाया गया था।

कोर्ट ने उक्त मामले में मुकुल की आवाज का नमूना जमा करने को कहा था, जिसके खिलाफ मुकुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मुकुल की याचिका खारिज कर दी, हालांकि साथ में यह भी कहा कि उनकी आवाज के नमूने का सिर्फ इस मामले में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुकुल के अधिवक्ता एस दासगुप्ता ने दलील पेश करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल मामले में गवाह हैं, न कि आरोपित इसलिए उन्हें आवाज का नमूना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसपर सरकारी अधिवक्ता शाश्वत मुखर्जी ने कहा कि गवाह को भी आवाज का नमूना देने को कहा जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मुकुल की याचिका खारिज कर दी।

मुकुल रॉय फाइल

31,313 लोग भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं इस समय तीन पड़ोसी देशों के। कैब से इन्हें तुरंत फायदा होगा। इसमें 25,000 से अधिक हिंदू, 5800 सिख, 55 ईसाई, दो बौद्ध और दो पारसी नागरिक शामिल हैं।

असम में मचे बवाल की हकीकत

पूर्वोत्तर के एक बड़े दायरे में नागरिकता संशोधन विधेयक प्रभावी नहीं होगा। यहां के कई राज्यों को इससे छूट दी गई है। हालांकि असम के कुछ हिस्से इसकी जद में हैं। यही वजह है कि इस विधेयक के खिलाफ यहां आंदोलन शुरू हो चुका है। आइए, इस आंदोलन की वजह की हकीकत से आपको रूबरू करते हैं :

नागरिकता संशोधन विधेयक का असम में भारी विरोध हो रहा है। लेखक, कलाकार और तमाम संगठनों से लेकर आम जन तक विधेयक के खिलाफ सड़कों पर हैं। गुरुवार को गुवाहाटी में विशाल प्रदर्शन किया गया ● प्रेट्र

नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से बाहर वाले क्षेत्र

दो श्रेणियां हैं जिन्हें इस विधेयक से दूर रखा गया है, इनर लाइन' द्वारा संरक्षित राज्य और संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र।

इनर लाइन परमिट (आइएलपी) : यह एक विशेष परमिट है, जो भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों को आइएलपी द्वारा संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आइएलपी परमिट के बिना किसी भी अन्य राज्य का भारतीय आइएलपी के अधीन आने वाले राज्य में जा नहीं सकता है।

छठी अनुसूची : छठी अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। यह इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। एडीसी के पास विभिन्न विषयों पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनों को लागू करने की शक्तियां हैं, इसका एक उद्देश्य आदिवासी समुदायों द्वारा स्व-शासन को बढ़ावा देना है।

कैब : किस राज्य में कितना प्रभावी

असम : राज्य में तीन स्वायत्त जिला परिषद हैं, जिनमें से दो भौगोलिक रूप से मिले हुए हैं। छठी अनुसूची के अंदर यह तीनों आते हैं। इनको छोड़कर कैब बाकी हिस्से में प्रभावी होगा।

मेघालय : इस राज्य में भी तीन एडीसी हैं। असम के विपरीत, मेघालय में एडीसी लगभग पूरे राज्य को कवर करते हैं। केवल शिलांग का एक छोटा हिस्सा इसके दायरे में नहीं आता है। शिलांग के उस हिस्से में कैब प्रभावी होगा।

अरुणाचल प्रदेश : पूरा राज्य आइएलपी के तहत कैब के दायरे से दूर होगा।

नगालैंड : राज्य में लाइन ऑफ परमिट की व्यवस्था है। इसलिए यह कैब के दायरे से दूर होगा।

मिजोरम : इस राज्य में भी आइएलपी की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य में तीन एडीसी हैं, जो छठी अनुसूची के तहत संरक्षित हैं।

त्रिपुरा : राज्य में एक एडीसी है, जो 70 फीसद क्षेत्र को कवर करता है। हालांकि, कुल आबादी की दो तिहाई आबादी शेष 30 फीसद हिस्से में रहती है। इसका मतलब है कैब छोटे और अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रभावी होगा।

मणिपुर : संपूर्ण राज्य को भी आइएलपी का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि, पहले यह संरक्षित नहीं था, लेकिन संसद में नागरिकता बिल पेश किए जाने के बाद सरकार ने यहां भी आइएलपी की व्यवस्था लागू कर दी।

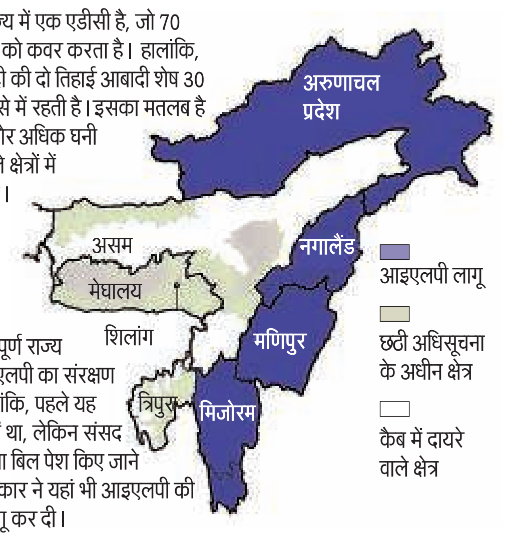

गुवाहाटी में ही होगी मोदी और एबी की बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : असम में नागरिकता कानून में संशोधन के विरोध में हो रही हिंसा के बावजूद भारत और जापान के बीच होने वाली सालाना शीर्षस्तरीय बैठक गुवाहाटी में ही होगी। गृह मंत्रालय ने बैठक की जगह में बदलाव की संभावना को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम एबी शिंजो के बीच होने वाली बैठक को लेकर दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में हैं। दोनों नेताओं के बीच सालाना बैठक 15 से 17 दिसंबर, 2019 के बीच गुवाहाटी में होनी है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बैठक की जगह में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है और असम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंसा और उपद्रव को रोकने के लिए असम सरकार को पर्याप्त केंद्रीय बल की सहायता दे दी गई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में असम के हालात सामान्य हो जाएंगे। उनके अनुसार नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। इन अफवाहों की काट और आम लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

नागरिकता विधेयक सिक्किम के मूलवासियों के खिलाफ : भूटिया

गंगटोक, प्रेट्र : फुटबॉलर से राजनेता बने बाईचुंग भूटिया ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) सिक्किम के मूलवासियों के हितों व अनुच्छेद 371 (एफ) के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 371 (एफ) राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। हमरो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) के कार्यकारी अध्यक्ष भूटिया ने विधेयक के मुद्दे पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) व विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चिंता जताई थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अब उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां भाजपा नीत एनडीए में शामिल हैं। पूर्व फुटबॉलर ने कहा कि विधेयक के अमल में आने के बाद हिमालयी प्रदेशों में विदेशी व अन्य लोगों की बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने लोगों से इस विधेयक की खिलाफत की भी अपील की है।

अभिनेता जतिन बोरा ने भाजपा से दिया इस्तीफा

एएनआइ (गुवाहाटी) के अनुसार, अभिनेता व असम भाजपा के नेता जतिन बोरा ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इसके पीछे के कारणों को नहीं बताया गया है।

असम के हालात से दुखी गायक पापोन ने दिल्ली का शो रद किया

मुंबई, प्रेट्र : 'मोह मोह के धागे' और 'जियें क्यूं' गानों को आवाज देकर मशहूर हुए गायक पापोन ने शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने एक शो को रद कर दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर उनका प्रदेश जल रहा है और वहां कर्फ्यू लागू है। ऐसे में वह अपने प्रशंसकों का मनोरंजन नहीं कर पाएंगे। पापोन ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए शो को रद किए जाने की जानकारी दी और प्रशंसकों से माफी भी मांगी। पापोन का असली नाम अंगराग महंता है।

हर हाल में रखेंगे पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान : मोदी

दिलाया भरोसा ▶ प्रधानमंत्री बोले, अपने सेवक पर भरोसा रखें, कांग्रेस के किसी झूठ के बहकावे में नहीं आएं

पड़ोसी राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को झांसे में रखा गया, हमने उन्हें इज्जत दी

राज्य ब्यूरो, रांची

देश के लोगों, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों को नागरिकता संशोधन विधेयक से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर का एक भी राज्य इससे प्रभावित नहीं है। हर हाल में पूर्वोत्तर के हितों का ध्यान रखा जाएगा। घुसपैठियों की राजनीति करती रही कांग्रेस इस मुद्दे पर मुस्लिमों से छल कर रही है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यह बात कही। मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद में रैली को संबोधित कर रहे थे।

बिल के विरोध पर मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस आग लगाने की कोशिश में है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी। मोदी ने खासतौर पर असम के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, 'आपकी परंपरा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दूंगा। आपके भविष्य को संवारने का काम होगा। अपने सेवक मोदी पर विश्वास रखिए। कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएं। किसी तरह के झूठ के झांसे में न फंसें। हम सभी को असम की संस्कृति पर गर्व है। कांग्रेस की डिक्शनरी में जनहित नहीं बल्कि स्वहित और परिवार हित है। उनकी राजनीति रही है - लूटो और लटकाओ।' प्रधानमंत्री ने विधेयक पर राज्यसभा में हुए मत विभाजन पर भी चुटकी ली। इस मामले में विपक्षी खेमे को 99 वोट मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि जहां सरकार को शुभ अंक सवा सौ मिले, वहीं विपक्ष 99 के फेर में फंस गया। पूर्वोत्तर पर भाजपा की नीति पर पीएम ने कहा, 'हम एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहे हैं। आज तक देश के जितने प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर गए हैं, उससे कहीं अधिक बार मैं गया हूं। केंद्र सरकार के दो मंत्री हर महीने पूर्वोत्तर जाते हैं।'

झारखंड के धनबाद में गुरुवार को भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण

सही है सरकार का कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को शामिल करने के निर्णय को सही ठहराया। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश की दो भुजाएं अलग-अलग समय पर काट दी गईं। इसका सर्वाधिक प्रभाव पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों पर पड़ा। इसके बाद मोदी ने लोगों से पूछा, 'इन देशों में अल्पसंख्यक कौन-कौन हैं?' रैली में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में हिंदू-हिंदू कहा। इसके बाद मोदी बोले, 'अफगानिस्तान में तालिबानियों ने ईसाई समुदाय के लोगों से मारकाट शुरू की तो सैकड़ों की संख्या में लोग भागकर भारत आए। उन्हें आश्वासन के बावजूद नागरिकता नहीं दी जा रही थी। यही कारण है कि हमने पड़ोसी राष्ट्रों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया। वहां उनके खिलाफ अमानवीय बर्ताव हो रहा था बहू-बेटियों के साथ अत्याचार भी आम बात थी।'

असम समझौते का होगा सम्मान

इससे पहले मोदी ने अंग्रेजी और असमिया में ट्वीट करके भी असम के लोगों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें इस विधेयक से कोई परेशानी नहीं होगी। असम में हिंसा और प्रदर्शन रोकने की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से असम समझौते की धारा-6 की भावनाओं के अनुरूप ही असम के लोगों के संवैधानिक, राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। असम समझौते की धारा-6 में स्थानीय अधिकारों, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

> बाबा धाम की धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति का मान-सम्मान रखा जाएगा। यह भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है।
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आरएसएस ने सराहा कैब पर सरकार का साहसिक कदम

- सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने मोदी और शाह को बधाई दी
- कहा-सभी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर बिल का स्वागत करें

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। साथ ही इसे एक साहसिक कदम बताया है। जोशी ने कहा कि सभी को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए।

संघ के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमेशा से ही यह कहता आया है कि किसी और देश में प्रताड़ित होकर भारत आया एक हिंदू घुसपैठिया नहीं, बल्कि एक शरणार्थी है। उन्होंने इसे एक साहसिक कदम बताते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया।

जोशी ने कहा कि धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा किया गया था। हालांकि भारत का कभी भी कोई धर्म आधारित देश बनाने का विचार नहीं रहा। लेकिन देश का बंटवारा इसी मुद्दे पर हुआ था और तब के नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। संघ के सरकार्यवाह ने कहा कि अगर धार्मिक आधार पर भारत को बांटा नहीं गया होता तो उसके बाद हुई बहुत सारी घटनाएं होती ही नहीं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। समझौते में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने की बात के बावजूद तब भी इस बात का डर था कि इन देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों का क्या होगा। दुर्भाग्यवश समझौते का पालन नहीं हुआ और वहां बड़ी तादाद में रह रहे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनगणना को देखें तो वहां पर हिंदुओं की आबादी में भारी कमी आई है। अब सवाल उठता है कि वह लोग कहां चले गए? और फिर बात सामने आई कि उनमें से बहुत से वापस भारत आ गए।

उन्होंने कहा कि इन देशों में प्रताड़ित किए गए हिंदुओं के पास जाने के लिए भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। चूंकि यहीं उन्हें आदर, सुरक्षित जीवन मिल सकता है, इसलिए वह समय-समय पर भारत आते रहे। जोशी ने बताया कि कोई कानूनी प्रविधान न होने के चलते यह लोग भारत की नागरिकता से कई सालों तक वंचित रहे। इस बात की भी खासी जरूरत थी कि इन प्रताड़ित लोगों को 'घुसपैठिया' न कहा जाए बल्कि शरणार्थी बोला जाए। इन शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत समय निकल गया और इन शरणार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन मौजूदा सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानजनक जीवन स्थान मिलेगा। नागरिक (संशोधन) विधेयक के तहत इस्लामिक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसको सोमवार को लोकसभा में और बुधवार को राज्यसभा में पारित किया गया है।

नागरिकता विधेयक पर अमेरिकी सांसदों को समझाने की कोशिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अमेरिकी एजेंसियों और वहां के कुछ सांसदों की तरफ से बेहद कड़ी टिप्पणी को लेकर भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। जिस दिन लोकसभा में तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने संबंधी विधेयक पारित हुआ, उसी दिन विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संसद के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से संपर्क किया और उन्हें इस विधेयक की सही स्थिति के बारे में बताया।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में अपने सभी मिशनों को सतर्क किया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि विधेयक को लेकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अभियान शुरू करें। इस बारे में अगर नई दिल्ली स्थित कोई विदेशी मिशन या उच्चायोग या दूतावास समझना चाहेगा तो उसे भी पूरी जानकारी दी जाएगी। यह कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले के बाद दूसरा संसद से पारित विधेयक है, जिसके बारे में भारत को दूसरे देशों को अवगत कराना पड़ रहा है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी कड़ी आलोचना की गई थी। आयोग ने यहां तक कहा था कि अगर राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित हो जाता है, तो वह इसे तैयार करने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा सरकार से करेगा। भारत ने इस प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि आयोग की टिप्पणी वस्तुस्थिति से परे और पक्षपातपूर्ण है।

कैब पर भड़के इमरान खान को भारत ने दिखाया आईना

- पाक पीएम ने नागरिकता बिल को कश्मीर, उन्मादी भीड़ की हिंसा से जोड़ा
- विदेश मंत्रालय ने दी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने की सीख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी आदत के मुताबिक नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं छोड़ा है। गुरुवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक के बाद एक तीन तल्खी भरे संदेश पीएम खान की तरफ से डाले गए। पाक पीएम ने कैब को कश्मीर, उन्मादी भीड़ की हिंसा से जोड़ते हुए भारत सरकार की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से की है। उन्होंने एक बार फिर दक्षिण एशिया में बदलते हालात को परमाणु युद्ध में तब्दील होने का भय दिखाया है और विश्व बिरादरी को कहा है कि इसके पहले कि देर हो जाए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने इमरान खान की टिप्पणी को खास तवज्जो नहीं दी है लेकिन उन्होंने अपने घर में अल्पसंख्यकों की स्थिति का ख्याल करने और दूसरे देशों के आंतरिक हालात में हस्तक्षेप नहीं करने की सीख भी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इमरान खान को यह याद दिलाया कि पाकिस्तान के कानून में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का प्रविधान है। वहां का कानून अल्पसंख्यकों की रक्षा करने या लड़कियों के अगवा होने, उनका धर्मांतरण किए जाने या उनके दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा है।

इमरान खान। फाइल

असम-त्रिपुरा में आंदोलन से विमान और ट्रेन सेवाएं ठप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पारित होने के खिलाफ असम और त्रिपुरा में चल रहे हिंसक आंदोलन के कारण गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट और अगरतला की ओर जाने वाली तमाम उड़ानें रद हो गई हैं। जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों को सिर्फ गुवाहाटी तक चलाया जा रहा है। असम और त्रिपुरा के भीतर भी फिलहाल अनेक ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। विमान और ट्रेन सेवाएं बंद होने से हजारों यात्री दोनों राज्यों के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए हैं।

गुरुवार को इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया समेत सभी एयरलाइनों ने गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ समेत असम के विभिन्न शहरों से संबंधित उड़ानों को रद कर दिया। इंडिगो के प्रवक्ता के अनुसार इंडिगो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए कम किराये पर राहत उड़ानें संचालित कर रही है।

इंडिगो ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की यात्रा करने वाले यात्रियों से 13 दिसंबर तक बुकिंग रद करने, तारीख बदलने का शुल्क नहीं लेने का एलान किया है। दूसरी ओर विस्तारा ने कहा है कि उसने सरकार की सलाह पर असम की अपनी उड़ानें रविवार 15 दिसंबर तक रद कर दी हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, सरकारी एयरलाइन केवल कोलकाता और डिब्रूगढ़ के बीच उड़ानों का संचालन कर रही है। गो एयर ने 13 दिसंबर तक गुवाहाटी से होने वाली उड़ानों के टिकट रद कराने या तारीख बदलवाने का कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। जबकि एयर एशिया ने भी कहा है कि असम में अशांति के कारण वो अगरतला और गुवाहाटी की उड़ानों पर 13 तारीख तक कोई कैंसिलेशन या डेट चेंज फीस नहीं लेगी। यात्रियों को केवल किराये में अंतर देना होगा।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों का असर बस सेवाओं पर भी पड़ा है। इन प्रदर्शनों के चलते गुरुवार को बसें खड़ी रहीं। प्रेट्र

ट्रेन परिचालन बाधित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रहे आंदोलन का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। इस कारण कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं, तो कुछ ट्रेनों का सफर निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त करने का फैसला किया गया है।

रद की गईं ट्रेनें : डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस शुक्रवार को रद रहेंगी। डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस बुधवार को रद कर दी गई थीं, इसलिए 14 दिसंबर को यह वापसी दिशा (लालगढ़ से डिब्रूगढ़) में भी रद रहेगी।

आंशिक रूप से रद रहने वाली ट्रेनें : 11 व 12 दिसंबर को रवाना हुई नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी से आगे रद रहेगी। वापसी दिशा में डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 13 और 14 दिसंबर को डिब्रूगढ़ के बजाय गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए चलेगी। 11 दिसंबर को रवाना हुई पुरानी दिल्ली-डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस गुवाहाटी से आगे रद रहेगी।

पंजाब भी लागू करने को तैयार नहीं

राब्यू, चंडीगढ़ : बंगाल के बाद अब पंजाब ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह भारत के धर्म निरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला है। उनकी सरकार इस कानून को लागू करने की इजाजत नहीं देगी। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कांग्रेस के पास विधानसभा में बहुमत है और वह इस विधेयक को रोक देगी।

रणनीति

एनडीए में चुनाव के पहले किसी भी मसले पर विवाद नहीं चाहती पार्टी, विवाद को प्रेरित करने वालों पर हो सकती कार्रवाई भी

बिहार में हर मुद्दे पर जदयू अब सीधे-सीधे भाजपा के साथ

- सीएबी के साथ-साथ एनआरसी पर पूर्व में जदयू की कुछ अलग राय थी
- अब संभावना जताई जा रही है कि पार्टी की राय अलग होगी

राज्य ब्यूरो, पटना

किस्म-किस्म के राजनीतिक कयासों के बीच संसद में नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) को जदयू से मिले समर्थन के बाद यह साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख वह किसी भी तरह की मतभिन्नता से अपने को दूर रखना चाहता है। बिहार में एनडीए को एकजुट रखने में उसकी भूमिका पर कोई सवाल नहीं करे, इसका पूरा ध्यान रख वह भाजपा के साथ चल रही है। जदयू की ओर से इस मामले में यह एहतियात भी बरती जा रही है कि पूर्व में जिन विवादित मसलों पर उसकी राय अलग थी उस पर समर्थन के नए स्टैंड का स्पष्टीकरण भी मौके पर ही दे दिया जाए।

नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) के साथ-साथ एनआरसी पर पूर्व में जदयू की कुछ अलग राय थी। उच्च स्तर पर यह कहा गया था कि असम में इस मसले पर जो विरोध है उसे भी ध्यान में रखा जाए। जदयू के नेता इस सिलसिले में असम भी गए थे। असम से एक शिष्टमंडल पटना भी तब आया था। इसलिए अंदेशा इस बात का था कि नागरिकता संशोधन बिल पर जदयू की राय कुछ अलग हो सकती है। पर जब संसद में यह बिल पेश हुआ और बहस के दौरान जदयू को अपना पक्ष रखने का समय मिला तो सदन में जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यह साफ-साफ कहा कि उत्तर-पूर्व राज्यों के मामले में पूर्व में उनके दल द्वारा जो सवाल उठाए गए थे, उन्हें सुलझा लिया गया है। जदयू ने सीधे-सीधे इस बिल का समर्थन किया। जदयू की ओर से पहली बार धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर यह कहा गया कि कुछ लोग अपने मतलब के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझा देते हैं। नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) किसी खास के लिए नहीं है। राज्यसभा में भी जदयू का यही स्टैंड है।

विरोध में भी सुर कम नहीं

जदयू का यह स्टैंड जैसे ही सार्वजनिक हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इसका विरोध कर दिया। पार्टी के नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा ने भी आपत्ति कर दी। पूर्व में विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी भी विरोध में बोल चुके थे। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का वक्तव्य कोई गलतफहमी पैदा नहीं करे इसका भी जदयू ने तुरंत ख्याल किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने तुरंत कहा कि प्रशांत किशोर का वक्तव्य निजी है। पार्टी की जो नीति थी उसे संसद में रखा जा चुका है। पवन वर्मा ने इस मसले पर बयान देने के पहले उच्च स्तर पर अपनी बात रखी थी तब तक पार्टी की ओर से संसद में अपना स्टैंड रखा जा चुका था। पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी के स्टैंड के खिलाफ निरंतर सक्रिय लोगों पर कार्रवाई संभव है।

नहीं मान रहे पीके, फिर किया पार्टी स्टैंड से अलग ट्वीट

राज्य ब्यूरो, पटना : नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) पर अपने ही दल में अलग-थलग पड़ चुके जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (पीके) ने पुन: गुरुवार को जदयू के स्टैंड के खिलाफ ट्वीट किया। संसद में जदयू के स्टैंड के खिलाफ दो दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था। इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर को यह परामर्श दिया था कि इस तरह के मुद्दों पर पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से पार्टी के स्टैंड के खिलाफ नहीं बोलें। प्रशांत किशोर ने इस परामर्श को खारिज करते हुए गुरुवार को पुन: ट्वीट कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह बिल सरकार के लिए सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच धर्म के आधार पर विभेद करने और यहां तक कि सजा दिलाने में भी कारगर होगा। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ हैशटैग में यह लिखा है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर के अंदाज से यह तय माना जा रहा है कि पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। उन्होंने गुरुवार को अपने ट्वीट में साफ कहा कि यह कहा जा रहा कि नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता प्रदान करने के लिए है पर सचाई यह है कि यह एनआरसी के साथ है।

सरकार के हाथ में यह एक घातक हथियार है। प्रशांत किशोर के गुस्से का अंदाजा उनके एक ट्वीट से लगाया जा सकता है कि संसद में नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) का जदयू ने समर्थन किया तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह पार्टी की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है। इस क्रम में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और गांधी जी के सिद्धांतों को ले जदयू की प्रतिबद्धता का विशेष रूप से जिक्र किया था। हालांकि, इस मुद्दे पर उनसे जदयू के अन्य नेताओं ने अलग राय व्यक्त की थी।

जनमत
मुद्दा

क्या विपक्षी राजनीतिक दलों की यह मांग सही है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे में तीनों पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक भी आने चाहिए?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश से कांपी दिल्ली, बर्फबारी से ठिठुरे पहाड़

बदला मौसम ▸ हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में हुआ सीजन का पहला हिमपात

हिमाचल में 10 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान

न्यूज गैलरी

केदारनाथ में तापमान माइनस12 डि.से. बर्फ ने थामी निर्माण कार्यों की रफ्तार

लखनऊ में उन्नाव कांड दोहराने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बवाल करने वाले 250 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा

असम विस अध्यक्ष ने विधेयक पर उठाए सवाल

सीएए पर पार्टी लाइन निर्धारित करने को बैठक करेंगी ममता

बदल रही तस्वीर

नक्सलियों के आधार क्षेत्रों तक बढ़ रही है सुरक्षा बलों की पहुंच

नक्सली लीडर रमन्ना की मौत की पुष्टि

60 एकड़ भूमि की मांग की गई है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उत्तराखंड सरकार से। गत दिवस निरंजनी अखाड़े में कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक हुई।

तैयारी ▶ केंद्र सरकार के सामने संघ और विहिप ने कुछ नाम आगे बढ़ाए, अभी ट्रस्ट में सदस्यों की संख्या तय नहीं

इस माह गठित हो सकता है मंदिर निर्माण ट्रस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में ट्रस्ट बनाने का दिया था आदेश

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण की आखिरी बाधा भी पार हो गई है। अब केंद्र सरकार मंदिर निर्माण पर ट्रस्ट बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर के फैसले में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन माह में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। केंद्र का इसके गठन को लेकर कई संगठनों से विचार-विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो माह के अंत तक ट्रस्ट का गठन हो जाएगा।

बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) भी सरकार से संपर्क में हैं। संघ परिवार अपनी तरह से कुछ नामों को आगे बढ़ाया है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का एक-एक प्रतिनिधि होने के साथ ही निर्मोही अखाड़े का एक प्रतिनिधि भी हो सकता है। मंदिर आंदोलन की अगुआ विहिप से भी किसी को ट्रस्ट में जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी यह सामने नहीं आया है कि ट्रस्ट में कितने सदस्य होंगे।

राम मंदिर मॉडल। फाइल

ट्रस्ट में जगह पाने को लेकर साधु-संतों और अन्य धार्मिक संगठनों की ओर से पैरोकारी हो रही है। संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, 'ट्रस्ट के गठन को लेकर वह केंद्र सरकार से संपर्क में हैं। उनकी ओर से भी कुछ नाम प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार भी कुछ नामों पर गंभीरता से विमर्श कर रही है। कुछ नाम तो समान ही हैं। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक ट्रस्ट का स्वरूप सामने आ जाएगा।'

वैसे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही ट्रस्ट में दिलचस्पी रखने वालों की सक्रियता बढ़ गई है। लोग अपनी-अपनी तरह से सरकार तक नाम पहुंचा रहे हैं। कुछ साधु-संत तो खुलकर ट्रस्ट में शामिल किए जाने की बात कर रहे हैं। इनमें कई नाम बहुत ही प्रभावी हैं, जिसकी वजह से केंद्र के सामने धर्म संकट बढ़ रहा है।

क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने पर ली जाएगी राय : जिलानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार ही नहीं किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलानी ने कहा, 'अभी हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जहां तक क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की बात है तो इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से बात करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का कोई फायदा मिलेगा या नहीं। यदि हम इसे दाखिल कर सकते हैं तो इस बारे में पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय ली जाएगी।'

वसीम रिजवी ने फैसले को बताया सही : शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अयोध्या मामले पर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि नफरत पैदा करने वालों की दुकानें एक बार फिर बंद हो गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने पर कहा कि मंदिर निर्माण में बाधा पैदा करने वाली ताकतें एक बार फिर बेनकाब हुई हैं।

याचिका खारिज होने से झूमी रामनगरी

अब भी समय है कि गुमराह लोग सच्चाई स्वीकार कर लें कि जहां रामलला विराजमान हैं, वह रामजन्मभूमि थी। राम किसी संप्रदाय विशेष के न होकर संपूर्ण मानवता के हैं।
– नृत्यगोपाल दास, रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत

रामलला के हक में फैसला जय-पराजय का सवाल न होकर सत्य स्वीकार करने का विषय है। इसको स्वीकार कर राममंदिर के साथ सभी वर्ग एवं संप्रदाय के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना होगा।
–पीठाधीश्वर महंत देवेंद्रप्रसादाचार्य, दशरथमहल बड़ास्थान

भगवान राम हिंदुओं के ही नहीं, मुस्लिमों के भी पूर्वज हैं। अब हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि सभी भगवान राम के आदर्शों और उनकी प्रेरणा से स्वर्णिम दिन देख सकें।
– महंत रामदास, नाका हनुमानगढ़ी

पुनर्विचार याचिका खारिज होने के साथ इस सच्चाई पर अंतिम रूप से मुहर लग गई है।
– महंत जन्मेजयशरण, रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष

पांच सदस्यीय पीठ का एकमत से आए फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका का औचित्य ही नहीं था।
–जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य

मुट्ठीभर लोगों को छोड़कर देश ने पहले ही कोर्ट का फैसला स्वीकार कर लिया था पर कुछ लोग अपनी दुकान जिंदा रखना चाहते थे। ऐसे लोगों को अपना कुत्सित विचार त्याग देना चाहिए।
–मो. इकबाल, मस्जिद के पैरोकार रहे

कुछ ताकतें देश में अलगाव की आग जलाकर रखना चाहती हैं पर ऐसी ताकतों को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सबक सीखना चाहिए।
– शरद शर्मा, विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता

कोर्ट ने जो किया, वह ठीक ही किया। अब हम यह देखेंगे कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप हमें मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि कहां दी जानी है।
–हाजी महबूब, पुनर्विचार याचिका दाखिलकर्ता

दस दिन में चार्जशीट दाखिल करेगी एसआइटी

उन्नाव कांड

- दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में तय की गई समयावधि
- उन्नाव के साथ रायबरेली, लखनऊ व दिल्ली से तथ्य जुटा रहे अधिकारी

जागरण संवाददाता, उन्नाव

दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) को दस दिन में चार्जशीट दाखिल करनी है। दो दिन पहले ही यह निर्देश मिलने के बाद टीम ने जांच तेज कर दी है। टीम ने 20 दिसंबर तक जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य तैयार किया है। पीड़िता को बीते गुरुवार को जिंदा जलाया गया था। उसके बयान के आधार पर आरोपित शिवम त्रिवेदी व उसके पिता रामकिशोर, प्रधान पति हरिशंकर त्रिवेदी, उसके पुत्र शुभम और पंचायत मित्र उमेश बाजपेयी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद एसपी विक्रांत वीर ने एएसपी विनोद कुमार पांडेय की अगुवाई में जांच के लिए एसआइटी गठित की थी। इसमें सर्विलांस, फोरेंसिक व क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी थे।

अधिकारियों ने जांच जल्द पूरी कर दस दिन में चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। एएसपी व टीम प्रभारी विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि जांच में हर पहलू पर काम किया जा रहा है। मामले से जुड़े लोगों, ग्रामीणों व गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक व सर्विलांस टीमें भी लोगों से बयान लेने को उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ और दिल्ली तक जा रही हैं। तय समय में जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी।

पीड़िता के घर वाले धरने पर डटे : दुष्कर्म पीड़िता की कब्र के पास गुरुवार को भी पीड़िता के भाई बहन व घर वाले धरने पर डटे रहे। वह नौकरी, आवास व शस्त्र लाइसेंस की मांग जल्द पूरी कराने, दोषियों को फांसी की सजा देने व मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। गुरुवार को कोई भी अधिकारी ने उनसे मिलने नहीं पहुंचा।

'ट्रेन निरस्त होने पर स्टेशन जा रही थी पीड़िता, सीबीआइ जांच हो'

आरोपित हरिशंकर त्रिवेदी की पत्नी और शुभम की मां ग्राम प्रधान सावित्री देवी ने पीड़िता के स्टेशन जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ट्रेन निरस्त होने और शिवम से शादी का मामला उठाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सीबीआइ जांच की मांग की। उनका कहना है कि दोषियों को सजा मिले पर निर्दोष न सताए जाएं। आशंका जताई कि पुलिस व सहयोगी टीमें वर्तमान माहौल, नेताओं व अधिकारियों के दबाव में सही जांच नहीं कर पा रही हैं। इससे बेगुनाह फंस सकते हैं।

न्यूज गैलरी

उत्तराखंड में विधायक चैंपियन पर एससी-एसटी का केस दर्ज

रुड़की : उत्तराखंड में विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के खिलाफ भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने, नस्लीय टिप्पणी करने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। कर्णवाल ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस को शिकायती पत्र सौंपा था। आरोप है कि विधायक चैंपियन ने पूर्व में अपने समर्थक पहल सिंह, फुरकान और पप्पू सिंह के साथ षड्यंत्र रचकर उनके और उनकी पत्नी वैजयंती माला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी पत्नी ने सिविल लाइंस कोतवाली में चैंपियन के तीनों समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इससे बौखला कर विधायक चैंपियन ने इसी साल 12 और 16 अप्रैल को प्रेस वार्ता कर उनके और उनकी पत्नी के बारे में जाति सूचक और नस्लीय टिप्पणी की। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी उन पर इस तरह की टिप्पणी और धमकी भरे पोस्ट डाले। (जासं)

त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखेंगे देशभर के विस अध्यक्ष

ऋषिकेश : देहरादून में 17 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान 19 दिसंबर को देशभर के विधानसभा अध्यक्ष ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में गंगा महासभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार को बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में गंगा महासभा के अध्यक्ष शेखर शर्मा ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का भव्य आयोजन भव्य होता है। लेकिन, देशभर से इतनी अधिक संख्या में अतिथियों के गंगा आरती में शामिल होने के लिए इसे और भी भव्य एवं आकर्षक बनाया जाएगा। (जासं)

हरक, यशपाल समेत 25 नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा कर घेराव कर हंगामा करने के 10 साल पुराने मामले में आरोपित कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल समेत 25 नेताओं को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने इन सभी के खिलाफ दायर वाद वापस ले लिया है। 2009 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी। 21 दिसंबर 2009 को कांग्रेस से बतौर नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत सहित तमाम कांग्रेसियों ने जन समस्याओं और सरकारी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए विधानसभा कूच किया था। (जासं)

जेबीटी घोटाले के दोषी नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रोकी : हाई कोर्ट

- दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने के मामले में सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने पर सरकार से नाखुशी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले के दोषी नेताओं की सरकार ने पेंशन क्यों नहीं रोकी, जबकि दोषी अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ व पेंशन रोकी जा रही है। हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों की पेंशन व लाभ रोकने के संबंध में अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी को सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

याचिका घोटाले में दोषी पूर्व ब्लाक शिक्षा अधिकारी राम कुमार व अन्य ने दायर की है। याची के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि याची समेत 56 अधिकारी जेबीटी भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के साथ दोषी करार दिए गए थे।

सन 2013 में इन सब को सजा मिली थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने 2015 में सभी अधिकारियों को पेंशन व सेवानिवृति लाभ देने पर रोक के आदेश जारी कर दिए। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि किसी भी कर्मचारी को उसकी पेंशन व सेवानिवृति लाभ से नही रोका जा सकता। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने कहा कि जिन नेताओं को सजा हों चुकी है सरकार उनको पेंशन व सुविधा जेल तक देकर आती है तो इन अधिकारियों की पेंशन व अन्य लाभ क्यों रोक रही है? इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार सभी को नोटिस जारी कर उनकी पेंशन व सुविधा रिकवर करने जा रही है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

एपी मिश्र व दो अन्य आरोपितों का जुटाया जा रहा आय से अधिक संपत्ति का ब्योरा

उप्र पीएफ घोटाला

- विजिलेंस ने लिए ईओडब्ल्यू से घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज
- सामने आ सकती हैं तीनों आरोपितों की बेनामी संपत्तियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बिजली कर्मियों के करोड़ों के भविष्य निधि घोटाले के मामले में आरोपित उप्र पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता के खिलाफ विजिलेंस भी जांच कर रही है। तीनों आरोपितों की आय से अधिक संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विजिलेंस ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) से पीएफ घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी लिए हैं।

उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले में तीन आरोपित अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। ईओडब्ल्यू प्रकरण में मनी लांड्रिंग के तथ्य सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली स्थित मुख्यालय से भी संपर्क कर चुकी है। डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह ने ईडी के निदेशक से वार्ता की थी और ईडी को एफआइआर व कई अहम दस्तावेज भेजे गए थे। पीएफ घोटाले के आरोपितों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस की जांच में एपी मिश्र, सुधांशु द्विवेदी व पीके गुप्ता की बेनामी संपत्तियां सामने आ सकती हैं।

एपी मिश्र। फाइल

ईओडब्ल्यू की पड़ताल में तीन आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कई अहम साक्ष्य जुटाए जाने का दावा किया गया है। सूत्रों का कहना है कि निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश कराने के बदले दिए गए करोड़ों के कमीशन के बारे में पहले ही अहम जानकारियां जुटा चुकी हैं। कमीशन के खेल में सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता के बेटे अभिनव की अहम भूमिका रही है। ईओडब्ल्यू ब्रोकर फर्मों के खातों की भी गहनता से जांच कर रही है। कमीशन की रकम जिन-जिन खातों में ट्रांसफर की गई है, उनके जरिए आरोपितों के खिलाफ सीधे साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में ईओडब्ल्यू अब तक कुल 12 आरोपितों की गिरफ्तारी कर चुकी है।

ध्यान रहे, 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले में हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। शासन ने इस मामले की विवेचना ईओडब्ल्यू को सौंप दी थी। प्रकरण की सीबीआइ जांच कराए जाने की सिफारिश भी की गई थी।

मंगू मठ की स्थिति जानने के लिए एसजीपीसी ने बनाई सब कमेटी

जागरण संवाददाता, अमृतसर : उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित ऐतिहासिक मंगू मठ की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए एसजीपीसी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने एक सब कमेटी गठित की है। सब कमेटी का प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लेगा। कमेटी में एसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजिंदर सिंह मेहता और एसजीपीसी सदस्य सुरजीत सिंह भिट्टेवड्ड को शामिल किया गया है।

लोंगोवाल ने बताया कि पहले भी सिख ऐतिहासिक गुरुधामों और जगन्नाथ पुरी स्थित गुरु साहिब से संबंधित गुरुद्वारों को लेकर उड़ीसा सरकार के पास एसजीपीसी पहुंच कर चुकी है। इनको गिराने की खबरें मिल रही हैं। इस सच्चाई की जानकारी लेने के लिए ही सब कमेटी गठित की गई है। वहीं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी गुरुद्वारा जगन्नाथ पुरी मंगू मठ और सिक्किम स्थित गुरुद्वारा डांग मार की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए अलग-अलग सिख जत्थेबंदियों की बैठक 19 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में बुलाई है।

पानीपत फिल्म निर्माता पर केस दर्ज करवाएंगे महाराजा सूरजमल के वंशज

जागरण संवाददाता, कैथल

पानीपत फिल्म में जिस राजा सूरजमल के चरित्र को लेकर जाट समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, उनके वंशज कैथल के गांव शेरगढ़ में रहते हैं। इन वंशजों ने अब एलान किया है कि वे पानीपत फिल्म के निर्माताओं पर उनके ऐतिहासिक चरित्र के साथ छेड़छाड़ के आरोप में केस करेंगे।

गांव शेरगढ़ के पूर्व सरपंच एवं जाट कॉलेज कार्यकारिणी के सदस्य सत्यवान शेरगढ़, सूरजभान, ओमप्रकाश, जगदीश, बलिंद्र सिंह, देवा नंबरदार ने बताया कि उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया था। इसके लिए सभी परिवार एकत्रित हुए और पिंडदान करवाने के लिए पिहोवा में गए थे। वहां उन्हें परिवार के पुरोहित काका शर्मा से मिले। उन्होंने पुराहित से परिवार के बारे में जानकारी मांगी।

इसके बाद पुरोहित ने पुरानी पौथियां संभाली और बताया कि वे महाराजा सूरजमल के वंशज हैं और उनके वंशज गुमानी मल राजस्थान के भरतपुर रियासत से कैथल में आए थे। महाराज सूरजमल भी पिहोवा तीर्थ पर आए थे।

पहले भी सुनते थे, लेकिन अब जाकर हुई पुष्टि : गांव के नंबरदार देवा सिंह व सत्यवान ने बताया कि पहले भी वे सुनते थे कि वे महाराजा के वंशज हैं। लेकिन पुराहित ने अब पुष्टि की है। उनके गांव की जमीन की फर्द निकलवाने में प्रारंभ में गुमानी मल का नाम आता है। उन्होंने ही गांव का खेड़ा शुरू किया था।

मल से बने मैहला : महाराजा सूरजमल अपने नाम के साथ मल जोड़ते थे, उनकी कई पीढ़ियां भी इसी प्रकार से नाम के आगे मल लगाती थीं। बाद में यह मल से बदलकर धीरे-धीरे मैहला बन गया। सत्यवान शेरगढ़ ने बताया कि पूरे प्रदेश में मैहला गोत्र केवल शेरगढ़ में है। कुछेक घर सौंगल व कुछेक रेवाड़ चीका में हैं।

पहलवान बजरंग ने भी उठाए पानीपत पर सवाल

सोनीपत : फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल के चित्रण को लेकर शुरू हुए विवाद में अब राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पहलवान बजरंग पूनिया भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर फिल्म में महाराजा सूरजमल के गलत चित्रण पर नाराजगी जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतिहास के तथ्यों से विपरीत जाकर फिल्मों में महापुरुषों की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करना बेहद अनुचित है।

फिल्म में चरित्र के साथ छेड़छाड़ से रोष

सत्यवान शेरगढ़ ने कहा कि फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल के चरित्र के साथ जो छेड़छाड़ की गई है। वह निंदनीय है। वे अपने महाराजा के चरित्र को लेकर यह लापरवाही कतई सहन नहीं करेंगे। उनके परिवारों ने फैसला लिया है कि वे अब इस फिल्म निर्माता के खिलाफ न्यायालय में केस दायर करेंगे। साथ ही अब वे भरतपुर में महाराजा सूरजमल की रियासत में भी जाएंगे और वहां रह रहे उनके वंशजों से मिलेंगे।

बेटा न होने पर दो बेटियों की मां की हत्या

जागरण संवाददाता, हाथरस : सरकार भले ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान पर जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर जनजागरण अभियान चला रही है, मगर समाज में अभी भी बेटे-बेटियों को लेकर भेदभावपूर्ण रूढ़िवादी सोच नहीं थमी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव देवर पनाखर में बेटा पैदा न होने पर दो बेटियों की मां की हत्या कर ससुराली फरार हो गए। महिला के भाई ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उप्र के कासगंज जिले के गांव हरनामपुर निवासी हरेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने अपनी बहन चंद्रवती देवी उर्फ भूरी का विवाह आठ वर्ष पूर्व क्षेत्र के गांव देवर पनाखर निवासी दिनेश कुमार के साथ किया था। चंद्रवती ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। बेटा न होने पर ससुरालीजन उसका उत्पीड़न करने लगे और दहेज में रुपयों की मांग भी करने लगे। ससुरालीजन पुत्र न होने पर चंद्रवती को आए दिन पीटते थे एवं ताने मारते थे। बुधवार शाम चंद्रवती ने ससुरालीजनों द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात अपने भाई को फोन से बताई थी, ससुरालीजनों ने उसे बुधवार रात ही मौत के घाट उतार दिया और शव कमरे में बेड पर छोड़कर भाग गए। गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की।

रांची में दो बच्चियों की हत्या लोगों का फूटा गुस्सा, बवाल

- दुष्कर्म की आशंका, थाना घेरकर तीन घंटे हंगामा, पुलिस पर पथराव

जागरण संवाददाता, रांची

झारखंड के चतरा जिले से बुधवार को लापता हुए तीन बच्चों में दस वर्ष की दो बच्चियों की हत्या कर दी गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि हत्या से पहले दुष्कर्म भी किया गया है। जंगल से एक बच्ची की लाश बरामद की गई, जबकि दूसरी बच्ची और एक आठ वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेजा गया। रिम्स में दूसरी बच्ची को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हैवानियत के साथ हत्या की घटना के बाद गुरुवार की दोपहर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा।

ग्रामीणों ने पिपरवार थाने का घेराव कर जमकर बवाल काटा। पुलिस पर पथराव किया। थाने में भी पत्थर फेंके गए। भीड़ का उपद्रव देख पुलिस को तीन बार लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि, उग्र भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दोपहर तीन बजे के बाद से ही ग्रामीण लगातार हंगामा करते रहे। बचरा बाजार की दुकानें बंद करा दी गईं। देर रात तक लोगों की भीड़ जमी थी। मामले में पुलिस ने तीनों बच्चों को अपहरण करने के मुख्य आरोपित सोनू मोची को गिरफ्तार कर लिया है। वह बच्चों का परिचित है।

भीड़ की मांग, एनकाउंटर करें या हमें सौंप दें

बच्चियों की हत्या के मामले में पिपरवार पुलिस ने एक गिरफ्तारी सहित छह को हिरासत में लिया है। ग्रामीण उन्हें हैदराबाद की तर्ज पर एनकाउंटर करने या अपने हवाले करने की मांग पर अड़े थे। आक्रोशित ग्रामीण पहले थाना घेरकर हंगामा कर रहे थे। बाद में थाना में घुस गए और जमकर बवाल काटा। बाद में बैकअप के तौर पर आइटीबीपी के जवानों को बुलाया गया। अतिरिक्त बल पहुंचने और तीसरी बार की लाठीचार्ज के बाद भीड़-तितर बितर हुई।

फैसले के बाद

पांच दर्जन से अधिक दृष्टिबाधितों ने किए रामलला के दर्शन, राम से मिल भाव विह्वल हुए दर्शनार्थी

'मन' की आंखों से मिले दिल में बसे राम

जागरण संवाददाता, अयोध्या

दृष्टिबाधित हैं तो क्या हुआ, मन की आंखों से देखने का हुनर उन्हें आता है। यह हकीकत इक्का-दुक्का नहीं, पांच दर्जन से अधिक दृष्टिबाधितों ने साक्षात बयां की। वह भी उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समक्ष जो सबके दिल और रोम-रोम में बसे थे। दरअसल, 20-25 महिलाओं समेत श्रद्धालुओं का यह जत्था उन दृष्टिबाधितों का था, जो रामलला के दर्शन करने दूर-दूर से आए थे। बेशक देख कुछ नहीं सके मगर अयोध्या के कण-कण में बसे राम की धरा के स्पर्श मात्र से भाव विह्वल होकर लौटे।

दृष्टिबाधितों का यह जत्था नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड (एनएवीएच) के संयोजन में गुरुवार को पहुंचा। एनएवीएच हर वर्ष दृष्टिबाधितों को देश के किसी न किसी पर्यटन स्थल की सैर कराता है। इसी क्रम में यह दल गत कुछ वर्षों में दिल्ली, आगरा, सोमनाथ, केरल, कन्याकुमारी आदि पर्यटन स्थलों की यात्रा कर चुका है। सुप्रीम फैसला आने के उपलक्ष्य में इस बार जत्था रामलला के दर पर पहुंचा। सायं

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार को रामलला का आशीर्वाद पहुंचे नेत्रहीन श्रद्धालु। जागरण

रामलला के दर्शन से पूर्व नेत्रहीनों ने हनुमानगढ़ी में विराजे बजरंगबली का दर्शन और सरयू पूजन किया। रामघाट स्थित रामचरितमान सभवन ट्रस्ट की ओर से दोपहर के भोजन के साथ दृष्टिबाधित रामभक्तों की मेजबानी की गई। सरयूतट से लगे नयाघाट बंधा तिराहा पर विधायक वेदप्रकाश गुप्त ने श्रद्धालुओं के इस समूह का स्वागत किया। स्वयं की दृष्टिबाधिता को पीछे छोड़ इस समूह का नेतृत्व कर रहे बसंत हेंगड़े ने स्पष्ट किया कि हम रामलला को भले ही नहीं देख सकते पर वह तो देख सकते हैं। हम उन्हें आंखों में नहीं मन में बसाने आए हैं।

अयोध्या में श्रद्धालुओं को नहीं अखरेगी छत की कमी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को अब छत की कमी नहीं अखरेगी। श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उनके लिए विश्रामालय बनाने की योजना है, जिसमें कम से कम 10 हजार श्रद्धालु रह सकेंगे। विश्रामालयों के लिए अभी स्थान चयन नहीं हुआ है लेकिन नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। दावा है कि तीन वर्षों में इतने विश्रामालय बन जाएंगे कि श्रद्धालुओं को रुकने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा समय में श्रद्धालुओं को अयोध्या के मठ-मंदिरों में रुकना पड़ता है। यहां होटल भी सीमित है।

पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा, कार्तिक, अन्य मेलों में कई बार श्रद्धालुओं को रामकीपैड़ी व अन्य स्थानों पर मजबूरी में खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ती है। भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में अयोध्या सबसे बड़े पर्यटन हब के रूप में स्थापित होगी। इसके गवाह यहां लगातार बढ़ रहे विदेशी सैलानी भी हैं। अक्टूबर में देशी-विदेशी मिलाकर 42 लाख 27 हजार 782 पर्यटक अयोध्या आए। फैसला आने के बाद नवंबर माह में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 57 लाख 34 हजार से अधिक पहुंच गई। इनमें अक्टूबर में विदेशी पर्यटक जहां 2859 थे, वहीं नवंबर में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा बढ़कर 6760 हो गया। नगर आयुक्त नीरज शुक्ल ने बताया कि योजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

अलग-अलग कैटेगरी के विश्रामालय : प्रस्तावित विश्रामालय अलग-अलग कैटेगरी के होंगे। इनमें कुछ निशुल्क होंगे। शुल्क वाले विश्रामालयों की दर सुविधा के हिसाब से तय की जाएगी।

शिवपुरी में खनन माफिया का हमला, डिप्टी रेंजर व वनरक्षक घायल

नईदुनिया, शिवपुरी : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पत्थर का अवैध परिवहन रोकने गई टीम पर माफिया ने लाठी और बका से हमला कर दिया। हमले में डिप्टी रेंजर और वनरक्षक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी रेंजर की जीप में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

घटना बुधवार-गुरवार देर रात शिवपुरी जिले के खोड़ चौकी के अंतर्गत ग्राम नावली में हुई। डिप्टी रेंजर मोहन स्वरूप गुप्ता के अनुसार हें बुधवार रात सूचना मिली थी कि करमई के जंगल से माफिया पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहा है। इस पर वह वनरक्षक नीरज राजौरिया सहित टीम को लेकर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। माफिया ने अपने लोगों के साथ टीम पर हमला कर दिया, जिसमें डिप्टी रेंजर और वनरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपित जाते-जाते शासकीय वाहन में भी तोड़फोड़ कर गए।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

लोगों में शक्ति की नहीं, इच्छाशक्ति की कमी होती है

निरर्थक याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करके उन लोगों को हतोत्साहित करने का ही काम किया है जो निहित स्वार्थों अथवा संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस संवेदनशील मसले को जीवित रखना चाह रहे थे। इस इरादे का संकेत इससे मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करते समय यह पाया कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पुनर्विचार याचिका दायर करने का काम उन लोगों ने भी किया जो मूल मामले में याची ही नहीं थे। यदि किसी मामले में मूल वादकारियों की तुलना में पुनर्विचार याचिकाएं कहीं अधिक लोगों द्वारा दाखिल की जाएं तो इससे यही पता चलता है कि इस देश में किस तरह कुछ लोग अदालतों के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते रहते हैं। मुश्किल यह है कि इस प्रवृत्ति पर लगाम लगने के कोई आसार नहीं हैं। हैरत नहीं कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने वाले चुप बैठने के बजाय अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए नजर आएं। निःसंदेह ऐसा करना उनका अधिकार है, लेकिन किसी भी अधिकार का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इस पर कोई रोक-टोक नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छी-खासी संख्या में गैरजरूरी याचिकाएं दाखिल होती रहती हैं। इस सिलसिले पर विराम लगाने की जरूरत है।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला केवल सदियों पुराने विवाद का पटाक्षेप करने वाला ही नहीं, बल्कि दोनों ही पक्षों को न्याय की अनुभूति कराने वाला भी रहा। इसी कारण इस फैसले को उन फैसलों में गिना गया जिनमें न्याय केवल होता ही नहीं है, बल्कि होते हुए दिखता भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि संविधान पीठ के सभी पांचों न्यायाधीशों ने एकमत से अपना फैसला सुनाया। इसके बावजूद कुछ लोगों ने सर्वसम्मति से दिए गए इस फैसले को लेकर यह रेखांकित करना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला सुना दिया। इस दुष्प्रचार का मकसद राजनीतिक रोटियां सेंकना और लोगों की भावनाओं को भड़काना ही अधिक था। यह दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने इसकी अनदेखी करना ही पसंद किया कि देश ने इस फैसले को न केवल गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार किया, बल्कि शांति और सद्भाव का भी परिचय दिया। सार्वजनिक तौर पर न तो उत्साह का प्रदर्शन हुआ और न ही मायूसी का। ऐसी परिपक्वता कम ही देखने को मिलती है। बेहतर होता कि इसी परिपक्वता का परिचय वे भी देते जो बिना ज्यादा कुछ सोच-विचार किए पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने को तैयार हो गए।

ब्लड बैंक

उत्तराखंड में छह माह से 20 साल तक लाइसेंस नवीनीकरण न करने वाले ब्लड बैंकों का संचालित होना बेहद गंभीर मसला है। निश्चित तौर पर यह मरीजों के साथ ही रक्तदाताओं के जीवन से खिलवाड़ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यानी कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश के ब्लड बैंकों को लेकर जो जानकारियां दी हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति महकमे की लचर कार्यशैली प्रदर्शित हो रही है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के सरकार के दावों को भी आईना दिखा रही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल यानी एबीटीसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रदेश में सौ प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। इसकी गवर्निंग बॉडी ने साल में होने वाली निर्धारित बैठकें भी नहीं की। ब्लड बैंकों के लाइसेंस नवीनीकरण के मामले में विभाग ने घोर लापरवाही बरती। ब्लड बैंक के लाइसेंस पांच वर्षों के लिए दिए जाते हैं, इसके बाद इनका नवीनीकरण किया जाता है। प्रदेश में हालात ये पाए गए कि 35 में से 13 ब्लड बैंक ऐसे थे, जिनके लाइसेंस छह माह से लेकर 20 साल पहले समाप्त हो चुके थे। बावजूद इसके वे धड़ल्ले से कार्य कर रहे थे। यहां तक कि संबंधित विभाग ने इनका निरीक्षण भी नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्लड बैंक में मोमबत्तियों से दान किए गए रक्त की थैलियां तक बंद करने के प्रकरण सामने आए। रक्त के मिलान के लिए समय पूरा कर चुके किट का इस्तेमाल हुआ। बिना पूरे टेस्ट किए यह रक्त मरीजों को वितरित किया गया। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गंभीर मामला है, क्योंकि असुरक्षित रक्त की आपूर्ति बेहद जोखिम भरी हो सकती है। इससे मरीज की जान तक जा सकती है। लाइसेंस जारी करने वाले विभाग की लापरवाही का आलम यह रहा कि उसने कैग द्वारा पूर्व में इंगित किए गए किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया। ऐसा होता तो यहां निश्चित रूप से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती थीं। जाहिर है कि विभाग इस ओर गंभीर लापरवाही बरत रहा है। अगर इस ओर पहले से ध्यान दिया गया होता तो कैग ब्लड बैंकों को लेकर इस तरह के गंभीर सवाल नहीं उठाता। सरकार को चाहिए कि वह कैग रिपोर्ट में ब्लड बैंकों के संबंध में उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरता से मंथन करे। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

ब्लड बैंकों को लेकर कैग रिपोर्ट में किए गए खुलासे स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं

अयोध्या प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप

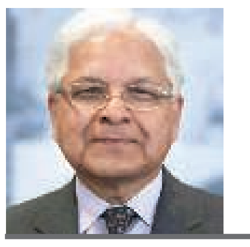

अश्विनी कुमार

यदि किसी राष्ट्रीय चुनौती के समाधान के लिए हम सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भरोसा रखते हैं तो फिर उसकी न्यायिक दक्षता एवं बुद्धिमता को भी स्वीकार करना होगा

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब याचिकाकर्ताओं के पास क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प बचा है। पता नहीं इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं? जो भी हो भारत जैसे देश में जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चरम पर होने के साथ ही धार्मिक गतिविधियों का बोलबाला हो और जहां इनसे जुड़ी भावनाओं को भुनाकर एक खास किस्म की राजनीति खूब पनप रही हो, वहां अयोध्या मामले में आया फैसला निश्चित रूप से एक बड़ी राहत कहा जा सकता है। अदालत ने बहुत खास पहलुओं के साथ इस मामले में फैसला सुनाया। उसने इतिहास के चश्मे से प्राचीन भारत में आए यात्रियों के ब्योरे के साथ-साथ पुरातत्व और विधिक बिंदुओं का संज्ञान लिया। आमतौर पर इसे संतुलित निर्णय बताते हुए कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से अदालत ने इंसाफ किया। वहीं आलोचकों की दलील है कि इस फैसले में विधि के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। वे मानते हैं कि अदालत ने समान नागरिकता के संवैधानिक संकल्प को पूरा नहीं किया। उनके मुताबिक यह निर्णय 'उचित क्षतिपूर्ति' के पैमाने पर भी खरा नहीं उतरता और यह किसी धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलतावादी राजव्यवस्था में किसी राजनीतिक संघर्ष का स्थाई समाधान नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक भावनाओं के आगे न्यायिक कसौटी को तिलांजलि दे दी गई।

अधिकांश न्यायिक फैसलों की व्यापक समीक्षा होती है। उन पर तमाम सवाल उठते हैं। इस लिहाज से यह कोई अपवाद नहीं कि इस मामले में भी कोई प्रश्न न उठाया जाए। भले ही दावा किया गया हो कि निर्णय 'तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार' पर हुआ, फिर भी यह आलोचकों के गले नहीं उतर रहा। दोनों पक्षों को न्याय देने के लिहाज से संतुलन साधने में अदालत ने फैसला किया कि विवादित स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष को 1934 और 1939 में मस्जिद को हुए नुकसान एवं 1992 में उसके विध्वंस की क्षतिपूर्ति के रूप में अयोध्या में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली स्वविवेक के अधिकार की शक्ति का उपयोग किया। अदालत ने विवादित जमीन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह पाया कि मुस्लिम पक्ष 1857 से पहले आंतरिक चबूतरे पर अपने नियंत्रण के पक्ष में ठोस दलील पेश नहीं कर सका, जिस पर सोलहवीं शताब्दी में निर्माण हुआ था।

सदियों से लंबित मामले पर फैसले की व्यापक पड़ताल समीचीन लगती है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया विशेषकर अदालत की निर्णायक भूमिका का आकलन करना होगा। हमें एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि इस मामले से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों और भावनाओं को देखते हुए क्या अदालत न्याय के निर्णायक माध्यम की भूमिका में खरी उतरी है? विधि, समानता एवं भली मंशा वाले फैसले को लेकर अदालत ने अपने निष्कर्ष के पक्ष में तमाम विस्तृत कारण गिनाए हैं। मालिकाना हक पर निर्णय को लेकर उसकी राय है कि इससे सामाजिक जुड़ाव एवं धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा। अदालत इस तथ्य से भलीभांति परिचित थी कि इस निर्णय की व्यापक समीक्षा होगी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने कहा, 'न्याय ही वह बुनियाद है जो किसी भी न्यायिक कवायद की कड़ी को जोड़ती है और उसी पर विधि व्यवस्था की वैधानिकता टिकी होती है।' उसका कहना है कि, 'भारत में तमाम क्षेत्रीय एवं धार्मिक पहचानों के संगम से बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक स्वरों का कोलाहल है। भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत रूप में एवं भारत को एक राष्ट्र के तौर पर इनके भीतर शांति के भाव को अवश्य महसूस करना चाहिए। ऐसे समाज के लिए पूर्ण संतुलन साधने की दिशा में हमें न्याय, समानता एवं भली मंशा का समावेश करना होगा।' (पैरा 674)

इसमें संदेह नहीं कि व्यावहारिक एवं न्यायोचित समाधान तलाशने को लेकर अदालत की उत्कंठा प्रत्यक्ष दिखती है। ऐसे में न्यायिक यथार्थवाद की जिस बुनियाद पर अदालत ने जो ठोस निष्कर्ष निकाला उसकी आधारभूत संकल्पना में खोट निकालना मुश्किल है। ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए उसने समानता के सिद्धांत का सहारा लिया। इसमें उसे 'न्याय के संवैधानिक मूल्य, भाईचारा, मानवीय गरिमा और धार्मिक मान्यताओं की समानता' की राह में संभावनाएं और तार्किकता दिखी (पैरा 788)। इस फैसले के एक खास पहलू ने इसे और मजबूती प्रदान की। वह था सभी न्यायाधीशों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय करना। ऐसी आम सहमति विरले ही देखने को मिलती है। इसमें अदालत यथार्थता एवं प्रयोगधर्मिता, स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता और तर्क एवं भावनाओं के बीच सही संतुलन स्थापित करती है। इजरायली विधिवेत्ता अहरोन बराक ने इन पहलुओं का उल्लेख 'द जज इन डेमोक्रेसी' में किया है।

किसी राष्ट्रीय चुनौती के समाधान के लिए यदि हम सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भरोसा रखते हैं तो फिर उसकी न्यायिक दक्षता एवं बुद्धिमता को भी स्वीकार करना होगा, भले ही उसका निर्णय आदर्श न हो। यही आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायाधीश भी आम इंसान हैं। वे स्वयं को इतिहास या समाज से अलग नहीं कर सकते। वे सामयिक धाराओं से भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते जो वक्त-वक्त पर अपनी करवटें बदलती रहती हैं। इन धाराओं के हिसाब से अक्सर सत्य और न्याय के मायने भी तय होते हैं। न्याय की सामान्य स्वीकार्य अवधारणा के अनुसार न्यायाधीश कानून को जीवंत बनाए रखते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य को आबद्ध रखते हैं। ऐसे में अपने कर्तव्यों के दायरे में सही संतुलन साधने के लिए वे सामाजिक संवेदनाओं एवं आस्था के ज्वार से जुड़े दावे को लोकतांत्रिक सिद्धांतों से आवरणबद्ध करते हैं। यहां शांति एवं सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करने की मंशा के साथ अदालत ने सही लक्ष्य संधान किया है।

यह निर्णय 'अनियमित भावनाओं' का परिणाम नहीं, बल्कि 'सामाजिक ढांचे को दुरुस्त रखने की मौलिक आवश्यकता' की ओर उन्मुख है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का निर्णायक पड़ाव उसकी अचूकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कानून पर उसके बाध्यकारी प्रवर्तन को लेकर केवल संवैधानिक अराजकता की कीमत पर ही सवाल उठाए जा सकते हैं। राष्ट्र की चेतना के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर कुछ सवाल भले ही उठते हों, लेकिन एक मजबूत फैसले से जुड़े मामले को दोबारा खोलने की व्यर्थ कोशिश उन दरारों को चौड़ा करने का ही काम करती जिन्होंने हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को आहत किया। पहले ही बोझ तले दबी अदालत पर भी इससे और अनावश्यक बोझ बढ़ता।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रामकथा

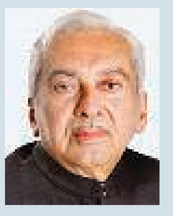

जगमोहन सिंह राजपूत

राम का व्यक्तित्व चरित्र निर्माण का प्रेरणास्रोत बनकर उभरता है। इससे समाज में सौहार्द की भावना भी बढ़ेगी

भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में अब मंदिर बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। दोनों समुदाय इसमें एक-दूसरे का तथा अन्य का भी सहयोग लेंगे। यह प्राचीन भारत की 'स्वीकार्यता की संस्कृति' का ही परिणाम था कि अयोध्या प्रकरण में पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आने के पहले ही उसे स्वीकार करने को तैयार थे और उन्होंने ऐसा किया भी। मुस्लिम समाज के कुछ जाने-पहचाने बुद्धिजीवियों, कलाकारों तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों ने पुनः इसे न्यायालय ले जाने के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। देखा जाए तो देश की प्राथमिकताएं वे ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका समाधान हर वर्ग के सक्रिय सहयोग के बिना असंभव है। इनमें शिक्षा, कौशल विकास, जनसंख्या, रोजगार के अवसर, गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा शामिल हैं। गरीबी, भुखमरी और कुपोषण ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण का उत्तरदायित्व हर समर्थ व्यक्ति, संस्था तथा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हर पंथ-मजहब मनुष्य के इस कर्तव्य को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसे प्रेरित भी करता है कि सामर्थ्यवान व्यक्तियों को अन्य के कष्ट निवारण में शामिल होना ही चाहिए। एक तरफ हम अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी सफलता पर उचित गर्व करते हैं, मगर जब विश्व पटल पर हंगर इंडेक्स या कुपोषित बच्चों के आंकड़े सामने आते हैं तो हमारी आंखें शर्म से नीची हो जाती हैं। यदि सभी संस्कृति और पंथ भाईचारे, शांति, सहयोग तथा सेवा पर जोर देते हैं तो फिर पूजा पद्धति की विविधता को लेकर विवाद में समय नष्ट करने की क्या जरूरत है?

बहुधर्मी देश भारत में मत-मतांतर को लेकर समस्याएं आती रहती हैं। बावजूद इसके हमारे दैनंदिन सरोकारों में पंथिक भाईचारा भी बखूबी देखने को मिल जाएगा। भारत की प्राचीन संस्कृति में 'एकं सत विप्रः बहुधा वदंतिः' एक अत्यंत गहन दर्शन का प्रकटीकरण है। यह हर प्रकार की पंथिक विविधता को पूर्णरूपेण स्वीकार करता है। यह उन्हें भी त्याज्य नहीं मनाता है जो ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति की मजबूत जड़ें अपनी वैश्विकता के लिए जानी जाती रही हैं। इसी कारण धीरे-धीरे भारत की बहुलवादी संस्कृति विकसित हुई जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। अपवादों को छोड़कर यहां हर व्यक्ति दूसरे के धर्म-पंथ को भगवान तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग मानता है। देश में ऐसे अनगिनत श्रद्धा केंद्र हैं जहां हर पंथ या मजहब के मानने वाले लोग अपनी आस्था प्रकट करने पहुंचते हैं। ऐसी सशक्त सामाजिक परंपराएं सभी वर्गों और समुदायों को आपस में बांधे रखती रही हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत की जीवनशैली में अनवरत प्रवाहित पंथनिरपेक्षता की धारा का सम्मान करते हुए ही संविधान में 'सेक्युलर' शब्द को शामिल करना आवश्यक नहीं माना। यह संविधान में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किन परिस्थितियों में और किनके द्वारा तथा क्यों लाया गया, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सर्व-धर्म समादर, सर्व-धर्म समभाव भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।

स्वतंत्रता के बाद पंथिक समस्याएं तब उत्पन्न हुईं जब 'सेक्युलर' शब्द का राजनीतिक उपयोग प्रारंभ हुआ, और भारत में 'सिद्धांतविहीन राजनीति' ने अपने पैर पसारे। यदि कुछ नेताओं ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते सेक्युलर शब्द को जबरन हथियाया न होता तो अयोध्या विवाद इतना लंबा नहीं खिंचता। 'प्रश्न-प्रतिप्रश्न-परिप्रश्न' की ज्ञानार्जन परंपरा वाला यह देश संवाद द्वारा इसका निर्णय बहुत पहले कर चुका होता।

सेक्युलरिज्म के नाम पर शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया और नई पीढ़ी को प्राचीन भारत की सभ्यता, दर्शन और साहित्य से पूरी तरह अपरिचित रखा गया। सभी मानते हैं कि भारत को समझने में सबसे अधिक सहायक रामायण और महाभारत ही होते हैं। वामपंथियों ने अपने विदेशी आकाओं का अंधानुकरण करते हुए रामायण और महाभारत को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से ही बाहर कर दिया। गीता के नीति-श्लोक निकाल दिए जो कुछ चरित्र निर्माण में सहायक हो सकता था, सर्व-धर्म समादर बढ़ा सकता था, पर वह क्षुद्र राजनीति का शिकार बन गया। नतीजतन आज हर कोई मूल्यों के क्षरण की चिंता कर रहा है। राजनीति में नीति ढूंढ पाना लगभग असंभव हो गया है। रामकथा में चरित्र निर्माण के सभी तत्व उपस्थित हैं। आज मुख्य चर्चा इस बिंदु के आसपास ही होनी चाहिए कि भारत की संस्कृति के स्रोत से देश की भावी पीढ़ियों को दूर रखना न केवल इस देश के लिए हानिकारक होगा, बल्कि विश्व शांति और समेकित प्रगति के लिए भी घातक ही होगा।

भारत ही नहीं, पूर्व की संस्कृति और सभ्यता की प्रगति और विकास में वाल्मीकि रामायण और रामकथा का योगदान असीम रहा है। भारत की हर एक भाषा में तथा अनेक विदेशी भाषाओं में रामकथा लिखी-पढ़ी गई, कथा वाचक परंपरा फली-फूली। उसमें कितने परिवर्तन हुए, मगर मूल धारा गंगा की तरह ही स्वीकार्य रही। उसका वैचारिक प्रवाह जीवन की व्यावहारिकता में अपना स्थान बना ही लेता था। तुलसीदास की रामचरित मानस ने उस समय के संपूर्ण परिदृश्य को प्रभावित किया। इसी परंपरा में रामकथा हर उस क्षेत्र, हर उस देश में लोगों की भाषाओं में वर्णित की गई। वह उच्चतम स्तर के साहित्य से चलकर लोक प्रवाह में अपने अनेकानेक स्वरूपों में अवतरित होती गई, मन-मानस में बसती गई, प्रेरणा देती गई और मानवीय सोच तथा क्षितिज को विस्तार देती गई। इस विस्तार को व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व आज भी शिक्षा व्यवस्था का ही है। ज्ञान का ग्रहण, नव ज्ञान के सृजन, उसके उपयोग की संभावनाओं का निर्देशन और उसे अगली पीढ़ी तक समर्पित करने का कार्य शिक्षा व्यवस्था से ही होगा।

कुल मिलाकर राम का संपूर्ण व्यक्तित्व चरित्र निर्माण का प्रेरणा स्रोत बनकर उभरता है। इसे समझने वाला न केवल अपना व्यक्तित्व निखारेगा, बल्कि वह पंथिक सद्भाव को अपना कर्तव्य भी मानने लगेगा। राममय मन सच्चे अर्थ में सर्व-धर्म-समादर को पहचानेगा। वर्तमान दौर में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

(लेखक शिक्षा और सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर की कृपा

परमात्मा महान परोपकारी एवं दाता है। उसने जीव रचे और जीवन योग्य सभी प्रबंध भी किए। आधार देने के लिए धरती बनाई। जीवित रहने के लिए वायु, जल, वनस्पतियां और अग्नि की उत्पत्ति की। यह प्रबंध जीवन को सरल और उपयोगी बनाने के लिए था, किंतु मनुष्य ने अपने स्वभाव से इन्हें विषमताओं एवं दुख के स्रोत में बदल दिया। धरती का स्वामी ईश्वर है, किंतु मनुष्य ने उसके अधिकार को भंग करते हुए धरती पर अपना स्वामित्व जमा लिया। एक ओर मनुष्य मानता है कि ईश्वर सृष्टि का सृजक है, दूसरी ओर उसकी धरती पर अपना अधिकार स्थापित करता है। यह ईश्वर से द्रोह नहीं तो और क्या है। जब मनुष्य का अपने जीवन पर भी कोई अधिकार नहीं तब धरती पर कैसा दावा। मनुष्य ने धरती पर अनधिकृत स्वामित्व ही नहीं स्थापित किया, उसका भरपूर दोहन भी किया है। मनुष्य ने धरती की गुणवत्ता को नष्ट करने का अपराध भी किया है। धरती की ही तरह वायु और जल की ईश्वर प्रदत्त गुणवत्ता को भी नष्ट किया जा रहा है।

मनुष्य पहले मूर्खताएं करता है और बाद में उन्हें सुधारने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि का अपव्यय करता है। न मूर्खताएं बंद हो रही हैं न बुद्धि का अपव्यय। जल और वायु को मनुष्य ही दूषित कर रहा है, फिर उन्हें शुद्ध करने के लिए शोध करता है। कितने ही रोग जल और वायु से पैदा हो रहे हैं। संसार के अधिकांश विवाद धरती से संबंधित हैं जिसने करोड़ों लोगों की जानें ले ली हैं। जिस तरह मनुष्य सारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बावजूद अपने जीवन के लिए अंततः ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित होता है, उसी भावना से उसे सृष्टि के साथ व्यवहार करना चाहिए। धरती, वायु और जल का महत्व मनुष्य के जीवन काल में उपयोग के लिए होना चाहिए, न कि इसे स्वामित्व की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मनुष्य धरती, जल, वायु का उपभोक्ता और संरक्षक तो हो सकता है, किंतु स्वामी नहीं। यही मनुष्य की बहुत ही समस्याओं का हल है और इससे ईश्वर के दरबार में स्थान भी मिल सकेगा।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

नैहर और मायके की बातें!

फिर से

अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय... गीत में नैहर शब्द को साहित्य में अमर कर दिया

नैहर शब्द अब सुनने को कम ही मिलता है। पहले लोकगीतों से लेकर फिल्मी गीतों तक इस शब्द का खूब प्रयोग होता था। देहात में यह अब भी बोला जाता है, मगर भाषा के शहरी संस्कार से यह दूर हो चुका है, क्योंकि अब फिल्मी गीतों में भी इसका प्रयोग बंद सा हो गया है। नैहर का मतलब होता है पिता का घर या मायका। किसी जमाने में पति से अपनी बातें मनवाने के लिए महिलाएं मायके जाने की धमकी का प्रयोग एक कारगर हथियार की तरह करती थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। मानें या न मानें, बदलती मान्यताओं और संचार क्रांति की बदौलत अब विवाहिता के लिए मायका पड़ोस ही हो गया है। सो मायके की धमकी का उपयोग शायद ही होता है।

नैहर शब्द संस्कृत के ज्ञातिगृह से बना है। ज्ञातिगृह बना है ज्ञाति+गृह से। ज्ञाति का अर्थ होता है संबंधी, पितृपक्ष, नाते-रिश्तेदार आदि। ज्ञाति बना है ज्ञा धातु में क्तिन प्रत्यय लगने से। ज्ञा धातु में जान, पहचान, परिचय, अनुभव, समझ आदि भाव समाहित हैं। इससे ही बना है ज्ञान शब्द। जानना और जान जैसे शब्दों के मूल में ज्ञान ही है। जिसे सब चीजों का ज्ञान होता है उसे ही जानकार कहते हैं। विज्ञान भी इससे ही बना है। स्पष्ट है कि ज्ञा में निहित जानने के भाव से ही ज्ञात शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है जिसे जाना जा चुका है। इसमें वस्तु से लेकर अनुभूति और स्थान से लेकर व्यक्ति तक आ जाते हैं। इसी तरह ज्ञाति में भी जिसे जाना जा चुका है का ही भाव है, मगर इसमें विशेषकर व्यक्ति प्रमुख हैं, इसीलिए इसका मतलब संबंधी, रिश्तेदार आदि होता है। नाता, नातेदार, नातेदारी जैसे शब्दों के मूल में ही ज्ञाति झांक रहा है। ज्ञातिगृह में यह भाव पितृपक्ष यानी पिता के घर, उनके संबंधियों-नातेदारों से जुड़ता है। रिश्तेदार वही है जिसे आप भली-भांति जानते हैं। इस तरह ज्ञातिगृह का अर्थ हुआ पिता का घर या मायका। ज्ञातिगृह के नैहर में बदलने का क्रम कुछ यूं रहा-ज्ञातिगृह, णातिघर, णाईहर, नाईहर, नैहर।

अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय... गीत में नैहर शब्द को साहित्य में अमर कर दिया।

नैहर में अगर पिता के घर की बात है तो मायका शब्द में मां के घर की बात उभर रही है। यह शब्द बना है मातृका+कः से। संस्कृत में मातृका का अर्थ होता है लक्ष्मी, दुर्गा, देवी, माता आदि। मातृका शब्द में जन्म स्थान या मूलस्थान का भाव भी निहित है। मां को जननी इसीलिए कहते हैं। मातृका में पोषण का भाव भी है। कन्या का पालन पोषण उसकी मां ही करती है। वहीं उसे जन्म देती है और बड़ा करती है। मातृका से ही बना है माइया जिसके प्रचलित रूप है मइया, माई या मैया। विवाहोपरांत पति का घर ही स्त्री का घर होता है, मगर इसके लिए कोई विशेष शब्द नहीं है। माता-पिता की तरह ही पति के पिता का घर ही स्त्री का असली घर कहलाता है जिसे ससुराल कहते है। हिंदी का ससुर शब्द संस्कृत के श्वसुर से बना है। श्वसुर+आलय मिलकर हुआ श्वसुरालय यानी ससुर का घर। इस तरह श्वसुरालय से बन गया ससुराल जिसे कई जगह सुसराल भी कहते हैं।

(शब्दों का सफर ब्लॉग में अजित वडनेरकर)

मेलबाक्स

मोदी सरकार की बढ़ती विश्वसनीयता

'नया इतिहास रचते मोदी-शाह' शीर्षक से युक्त अपने लेख में प्रदीप सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के करिश्माई व्यक्तित्व के विषय में जो कुछ लिखा है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ जनमानस की देश के प्रति बदलती अवधारणा का परिणाम है। आज मोदी शासन की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता के पीछे यही कारक काम कर रहा है। अभी तक एक वर्ग विशेष को बंधुआ वोटबैंक बनाने की नियत से परोसी जाने वाली छद्म धर्मनिरपेक्षता की ओट में देश के मानस को छलने का जो कुचक्र चलाया जाता रहा, उस पर अब धूल पड़ने लगी है। तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाला देशव्यापी कानून और कश्मीर के अनुच्छेद-370 और 35-ए के खात्मे के प्रति शांतिप्रिय मुस्लिम वर्ग द्वारा प्रदर्शित मूक समर्थन इसका सूचक है। अभी हाल में संसद से पारित मोदी सरकार का 'नागरिकता संशोधन विधेयक' न तो किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात पूर्ण है और न ही विरोधी, बल्कि यह विशुद्ध रूप से वर्षों से उपेक्षित पड़ोसी मुस्लिम देशों द्वारा धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किए गए शरणार्थियों को उनके नागरिक अधिकार देने का दस्तावेज है, जो अब कानून का रूप लेने जा रहा है। इस विधेयक पर अभी तक जो विरोधी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनका एजेंडा न केवल हिंदू विरोधी है, अपितु देश के संसाधनों का दोहन करने वाले अवैध घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके ये अपने मुफ्त में मिले वोटबैंक को बचाने का असफल प्रयास भी कर रहे हैं। एक राष्ट्रहितैषी विधेयक का विरोध करने वाले लोगों की इसी दुर्नियत का ही दुष्परिणाम है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठियों द्वारा मोदी सरकार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। इस नरात्मकता का फायदा उठाने में पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश पीछे नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की इस विधेयक के विषय में की गई नकारात्मक टिप्पणी इसका प्रमाण है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

बिना दोष दंड

दैनिक जागरण के 10 दिसंबर के अंक में प्रकाशित प्रकाश सिंह का लेख, समस्या की जड़ में जाने से इन्कार, में उन्होंने महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार प्रवृत्ति का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। कायदे में ऐसे जघन्य अपराध में संलिप्त आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत का ये दुरुपयोग करते हैं और न्याय में देरी भी होती है। ऐसी घटनाओं में कम से कम समय में मामले की सुनवाई कर फैसला होना चाहिए। अन्यथा अपराधी के साथ पीड़ित के परिजन बिना किसी दोष के ही दंड सहने को विवश होते हैं।

शैलेंद्र सक्सेना, नई दिल्ली

समर्थन की दरकार

कुछ राजनीतिक पार्टियों लंबे समय तक सत्ता में रहीं, लेकिन देश की कई बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करती रहीं। अब जब वर्तमान सरकार एक-एक कर सभी समस्याओं का निराकरण कर रही है तो वे इसके विरोध में खड़ी हैं। जब सत्ता में रहते हुए खुद कुछ नहीं कर पाए तो अब जो सरकार कर रही है, कम से कम उसका समर्थन तो करें। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह फैसलों के बारे में जनता को सही जानकारी दे, ताकि आम नागरिक किसी झूठ का शिकार न हों।

सतीश त्यागी काकड़ा, गाजियाबाद

घुसपैठ को रोकना जरूरी

नागरिकता संशोधन विधेयक का कुछ वर्ग द्वारा विरोध किया जाना कहीं से उचित नहीं है। यह बिल किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हर भारतीय को एक पहचान देने वाला है। क्या सिर्फ एक बिल पास होने से किसी को गैर भारतीय घोषित कर दिया जाएगा? कदापि नहीं। जो लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं, भले ही वे किसी देश से आए हों उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बिल में समय सीमा तय की गई है। इसका मकसद केवल अवैध घुसपैठ को रोकना है। इसमें गलत क्या है? कौन देश चाहेगा कि उसके यहां दूसरे देशों से आकर लोग बसते रहें। अमेरिका तक अपने यहां आसानी से नागरिकता नहीं देता है तो फिर भारत में हर समय दूसरे देशों से आकर बसने का सिलसिला क्यों? इसे तो रोकना ही चाहिए। निश्चित रूप से यह केंद्र सरकार सही दिशा में काम कर रही है। इसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए।

अनुराग शुक्ला, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

79 सर्वश्रेष्ठ थानों (देश भर) के इलाके में रहने वाले 5,641 लोगों से पुलिस के कामकाज के बारे में की गई बातचीत का निष्कर्ष यह निकला है कि इनमें से आधे से अधिक नागरिक पुलिस के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं।

अभिषेक कुमार सिंह
एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

आजकल

मामूली चिंगारियों को हवा देती लापरवाही

यह एक विडंबना ही है कि आग के मामले में प्राकृतिक जंगल और कंक्रीट के जंगलों यानी शहरों में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। बल्कि शहरों में लगने वाली आग कई मामलों में प्राकृतिक जंगलों से भी भयावह हो गई है। यहां यह बेहद मामूली कारणों से जब-तब भड़क उठती है और हर बार लाखों-करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के साथ दर्जनों जिंदगियों को स्वाहा कर डालती है। ऐसे में सवाल हमारे शहरीकरण की नीति और संबंधित सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं

दिल्ली के अनाजमंडी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग के बाद राहत व बचाव कार्य में जुटे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी। फाइल फोटो

देश की राजधानी दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में स्थित अनाजमंडी में बैग और खिलौना आदि बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के दर्जनों मजदूरों के परिवार बेशक ये सवाल सरकार और संबंधित एजेंसियों से पूछेंगे कि इस हादसे में जान गंवाने वाले उनके परिजनों का आखिर कसूर क्या था? पर तय है कि ये जवाब तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि सरकारें और योजनाकार अनियोजित विकास और आग को साधने वाले उपायों की अनदेखी जैसे मुद्दों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाएंगे। इन मामलों पर बरती जा रही सतत लापरवाही का ही परिणाम है कि कभी बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्रियां धू-धूकर जलने लगती हैं तो कभी, मायापुरी, नारायणा, पीरागढ़ी या नोएडा के औद्योगिक इलाके में अग्निकांड दर्जनों मौतों की वजह बन जाते हैं।

दिल्ली की अनाजमंडी के इस भीषण अग्निकांड के पीछे ऐसा कोई नया कारण नहीं था, जो पहले के हादसों में नजर नहीं आया था और अगर उनसे सबक लिया गया होता, तो उसकी रोकथाम नहीं हो सकती थी। संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों से मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी किया जाना, राजनीतिक फायदे के लिए अनियोजित विकास की तरफ से आंखें मूंदें रखना और हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा बांटकर निश्चिंत हो जाना- ये ऐसे कारण हैं जो अगर आगे भी अनुत्तरित रहे तो तय है कि रोजगार देने वाले शहरों में ऐसे अग्निकांडों की रोकथाम शायद ही कभी होगी। वरना ऐसी क्या वजह है कि आग लगने के पीछे जो कारण अनवरत हादसों में साफ हो चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है।

अनाजमंडी में हुए हादसे की मूल वजह भले ही शॉर्ट सर्किट होना बताई जा रही है, पर दर्जनों मौतें साबित कर रही हैं कि शॉर्ट सर्किट से ज्यादा बड़ी वजह यह है कि यह अवैध फैक्ट्री ऐसी तंग गलियों में है, जहां फायर ब्रिगेड का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। एक रिहाइशी इलाके की संकरी गली में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामानों से घिरी चार मंजिला अवैध फैक्ट्री में आग लगना भले ही एक दुर्योग हो, पर इससे बड़ा दुर्योग यह है कि प्रशासन और सरकारी अमले को इस रिहाइशी इलाके में ऐसी फैक्ट्री का मौजूद होना नजर नहीं आया। अगर मान लें कि इस फैक्ट्री की जानकारी प्रशासन को थी, तो दूसरे कई सवाल उठते हैं। जैसे आखिर इसके संचालन का कोई लाइसेंस इसे कैसे मिला होगा और क्या इस फैक्ट्री के पास आग से बचाव के उपायों से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) था? अतीत में कई ऐसे हादसों ने ऐसे ही कई उदाहरण हमारे सामने रखे हैं।

पिछले ही वर्ष यानी 2018 की शुरुआत में दिल्ली के बवाना इलाके में जिस पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, उसे पटाखे बनाने का लाइसेंस मिलना लंबे समय तक रहस्य बना रहा। मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उसके अलॉटमेंट के समय बताया गया था कि वहां 100 मीटर के इलाके में प्लास्टिक के सामान का काम किया जाएगा। हालांकि आग लगने का मुख्य कारण वे पटाखे थे, जिन्हें वहां बनाया जा रहा था। यानी फैक्ट्री में पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री को लाइसेंस देने का मामला हादसे के बाद तब उलझ गया था, जब एमसीडी ने कहा कि लाइसेंस उसकी ओर से जारी नहीं किया गया था। इसी तरह दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआइआइडीसी) ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि उसके पास तो फैक्ट्रियों के लाइसेंस जारी करने की शक्ति (पावर) ही नहीं है। डीएसआइआइडीसी ने बवाना हादसे पर जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी थी, उसमें साफ कहा गया कि डीएसआइआइडीसी के पास किसी भी तरह की रेगुलेटरी पावर नहीं है। उसे फैक्ट्री बिल्डिंग्स या उनके कंस्ट्रक्शन के लिए लाइसेंस या परमिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। लाइसेंसिंग के नियम का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने का अधिकार डीएमसी एक्ट के तहत एमसीडी के पास है। इस एक्ट के तहत स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार एमसीडी किसी भी बिल्डिंग के निर्माण की जांच कर सकती है और अगर कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो एमसीडी उस परिसर को खाली भी करवा सकती है। यही नहीं, अगर किसी फैक्ट्री में आग लगने की आशंका है, तो एमसीडी कमिश्नर लिखित आदेश जारी कर उस फैक्ट्री को खाली या बंद करवा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लाइसेंसिंग पॉलिसी 2017 में लिखा है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 416 और 417 के तहत एमसीडी ही फैक्ट्री लाइसेंस जारी करती है। बिल्डिंग के उन सभी फ्लोर्स के लिए एमसीडी से लाइसेंस लेना जरूरी है, जहां वाणिज्यिक गतिविधि की जानी है। इससे लगता है कि एमसीडी की ओर से बवाना ही नहीं, अनाजमंडी और तमाम अन्य मामले में हमेशा अनदेखी की जाती रही है।

ध्यान रहे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई फैक्ट्री अग्निशमन विभाग की तरफ से मिले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) के बिना नहीं चल सकती। यह एनसीओ भी उन्हें सीधे नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर दिल्ली में अग्निशमन विभाग को जब एमसीडी, एनडीएमसी या अन्य संबंधित एजेंसियों से इसका आवदेन मिलता है, तो वे उन फैक्ट्रियों या संस्थानों की इमारतों में जाते हैं और जांच करने के बाद संतुष्ट होने पर एनओसी जारी करते हैं। लेकिन इस प्राविधान की खुलेआम अनदेखी होती है। आरोप है कि इन संबंधित विभागों के कर्मचारियों को पता भी रहता है कि किस फैक्ट्री में कौन सा काम हो रहा है, लेकिन मिलीभगत कर सारी धांधलेबाजी की ओर से आंखें मूंद ली जाती हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके बवाना और नरेला में 18 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियों को ढाई-तीन वर्ष पहले अग्निशमन विभाग की ओर से फायर सेफ्टी नोटिस मिले थे, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी और कर्मचारियों-अधिकारियों की साठ-गांठ से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद फरवरी 2017 में नरेला और बवाना की लगभग सभी फैक्ट्रियों को एकतरफा फायर सेफ्टी नोटिस जारी किए गए थे। तब उद्योग मंत्री की मध्यस्थता में फैक्ट्री मालिकों को तीन महीने की मोहलत भी दिलाई गई थी, तब भी शुरुआत में सिर्फ 20 फीसद फैक्ट्री मालिक ही एनओसी ले पाए थे।

साफ है कि जब तक आग की भयावहता को इस कदर ठंडे रुख से लैस लापरवाही के साथ देखा जाता रहेगा, तब तक रोजगार देने वाले शहरों के रिहाइशी और औद्योगिक इलाकों में भी यदा-कदा भड़कने वाली आग पर कोई अंकुश नहीं लग पाएगा। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ऐसे ज्यादातर अग्निकांडों में जान गंवाने वाले लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के गरीब और वंचित तबकों से होता है। जब उनकी सुनवाई इन कारणों पर ही नहीं हो रही है कि रोजगार के लिए उन्हें इस तरह पलायन कर सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर अनजान शहरों में क्यों जाना पड़ रहा है, तो हादसों में मुआवजा पाने के सिवा उनके परिवार और क्या आवाज उठा पाएंगे।

आग से लड़ाई में कमजोर शहरीकरण

आधुनिक वक्त के निर्माण का जो सबसे चिंताजनक पहलू इधर कुछ वर्षों में सामने आया है, वह यह है कि शहरों में जो इमारतें बाहर से लक-दक दिखाई देती हैं, वे भी भीतर से आग से लड़ने के मामले में बेहद कमजोर साबित होती हैं। वहां छोटी सी आग को भीषण अग्निकांडों में बदल देने वाली इतनी चीजें मौजूद रहती हैं कि एक बार कहीं कोई बिजली का तार भी सुलगता है तो वह मामूली घटना भी भयानक हादसे में बदल जाती है। शॉर्ट सर्किट से हुए अनाजमंडी के ताजा हादसे से पहले इसी वर्ष करोल बाग के होटल अर्पित में लगी आग की शुरुआत इसके एक कमरे में ब्लोअर को शुरू करने और उसमें हुए शॉर्ट सर्किट से बताई गई थी। ज्यादातर मामलों में आग किसी बेहद छोटे कारण से ही शुरू होती है। जैसे मामूली शॉर्ट सर्किट या बिजली के किसी खराब उपकरण का आग पकड़ लेना। यह बात दशकों पहले समझ में आ गई थी, लेकिन अफसोस है कि ऐसी मामूली वजहों की असरदार रोकथाम अब तक नहीं हो सकी।

आज की आधुनिक रसोइयों में रखे फ्रिज-माइक्रोवेव से लेकर एसी, कंप्यूटर जैसे उपकरण और फाल्स सीलिंग के भीतर की जाने वाली वायरिंग महज एक शॉर्ट सर्किट के बाद काबू नहीं किए जा सकने वाले आग के शोले पैदा कर रही है। दिक्कत यह है कि आधुनिक शहरीकरण की जो मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है, उसमें सावधानियों और आग से बचाव के उपायों पर ज्यादा काम नहीं किया गया है। आज प्रायः हम भवनों का निर्माण ऐसी सामग्रियों से कर रहे हैं जिसमें आग को बढ़ावा देने वाली तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है। आंतरिक साज-सज्जा के नाम पर फर्श और दीवारों पर लगाई जाने वाली सूखी लकड़ी, आग के प्रति बेहद संवेदनशील रसायनों से युक्त पेंट, रेफ्रिजरेटर, इनवर्टर, माइक्रोवेव, गैस का चूल्हा, इलेक्ट्रिक चिमनी, एयर कंडीशनर, टीवी और सबसे प्रमुख पूरी इमारत की दीवारों के भीतर बिजली के तारों का संजाल (इंटर्नल वायरिंग) है जो किसी शॉर्ट सर्किट की सूरत में छोटी सी आग को भी बड़े हादसे में बदल डालते हैं। इस सभी चीजों को आग से बचाने के इंतजाम भी प्रायः या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे एमसीवी आदि के हवाले होते हैं या फिर फायर अलार्म के सहारे जो अक्सर ऐसी सूरत में काम करते नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी समय-समय पर जांच नहीं होती। लिहाजा इन चीजों पर भी नियमित ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरा बड़ा संकट तंग रास्तों के किनारे पर ऊंची इमारतें बनाने के ट्रेंड ने पैदा किया है। ऐसी अधिकांश इमारतों में शायद ही इसकी गंभीरता से जांच होती हो कि यदि कभी अचानक आग लग जाए तो क्या बचाव के साधन आसपास मौजूद हैं। कोई आपात स्थिति पैदा हो तो वहां निकासी का रास्ता क्या है, क्या वहां मौजूद लोगों को समय पर अलर्ट करने का सिस्टम काम कर रहा है। कुछ और अहम बातें भी हैं जो शहरों में आग को विनाशकारी ताकत दे रही हैं। जैसे हर बड़े शहर में बिना यह जाने ऊंची इमारतों के निर्माण की इजाजत दे दी गई है कि क्या उन शहरों के दमकल विभाग के पास जरूरत पड़ने पर उन इमारतों की छत तक पहुंचने वाली सीढ़ियां (स्काइ लिफ्ट) मौजूद है या नहीं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में दमकल विभाग के पास अधिकतम 40 मीटर ऊंची स्काइ लिफ्टें हैं, पर यहां इमारतों की ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच चुकी है। नोएडा में भी अधिकतम 42 मीटर ऊंची स्काइ लिफ्ट उपलब्ध है, पर यहां जो करीब दो हजार गगनचुंबी इमारतें हैं या जिनका निर्माण चल रहा है, उनमें से कुछ की ऊंचाई 300 मीटर तक है। लगभग यही हाल देश के दूसरे बड़े शहरों में भी है।

खरी-खरी

स्वार्थ की धारा में नहाए बुद्धिजीवी!

अतुल कनक

वे चंद्रमा को शांत करने के लिए हाथों में अंगूठी पहनते हैं, लेकिन ज्योतिष को बकवास बताते हैं। उन्होंने राहू की कृपा पाने के लिए लंबे समय तक बहते पानी में कोयला डाला, लेकिन अपने लेखों में ऐसे उपायों को अंधविश्वास बताते हैं। वे अच्छी प्रेम कविताएं शायद इसलिए लिख पाते हैं, क्योंकि पत्नी से बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने जिस समारोह में भाषण दिया था कि आदमी को हर कीमत पर स्वाभिमान से रहना चाहिए, उसी समारोह के तुरंत बाद अपना तबादला रुकवाने के लिए विधायक के पांव छू लिए थे। मैंने उन्हें देख लिया तो खिसिया कर बोले- विधायक के नहीं, लोकतंत्र के पांव छू रहा था।

वे दूसरों की गलती पकड़े जाने पर ठहाके लगाते हैं और खुद रंगे हाथों पकड़े जाने पर खींसे निपोर देते हैं। उनकी नजर में वो हर आदमी गलत है, जो उनके स्वार्थ को पूरा करने की राह में बाधक है। दोस्ती को वे स्वार्थ पूरा करने की सबसे जरूरी कड़ी मानते हैं। जिससे मतलब होता है, उसे सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर देते हैं। मसलन जब उन्हें सस्ते में दुकान लेनी थी, तब अमुक उनका अच्छा दोस्त था। जब उन्हें अदालत से जमानत चाहिए थी, शमुक उनका सबसे अच्छा दोस्त हो गया। जब उन्हें अपनी संस्था की स्मारिका के लिए विज्ञापन चाहिए था, तब लमुक उनका सबसे अच्छा साथी निकला और जब उन्हें चंदा चाहिए था, तब नमुक उनका अच्छा दोस्त घोषित हुआ। उनके दोस्त बदलते रहते हैं, बस स्वार्थ अपनी जगह पूरी ठसक के साथ कायम रहता है।

उन्होंने एक पुरस्कार जुगाड़ किया, लेकिन वे साहित्यिक पुरस्कारों में गुटबाजी के खिलाफ हैं। ईमानदारी के सिद्धांत से उनका इतना प्रेम है कि वे पूरी ईमानदारी से उसका अंत कर देते हैं। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन रिश्वत देकर कुछ जमीन हथिया रखी है।

एक दिन मैंने पूछ लिया- आपकी विचारधारा क्या है? बोले- जिस धारा में अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, वही अपनी विचारधारा। फिर खींसे निपोर दीं।

कल तक वे जिसे अपना सच्चा दोस्त बताते थे, आजकल उसके दोस्तों को घर बुलाकर उसी के खिलाफ भड़का रहे हैं। दरअसल, वे एक बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी की परिभाषा तो आपको पता ही है, कि जिसकी बुद्धि में छोटे-छोटे जीव पड़ जाएं, वही बुद्धिजीवी!

ट्वीट-ट्वीट

इंटरनेट बंद करने से असम में कैब का विरोध नहीं रुकेगा। आज जब तमाम सुविधाएं इंटरनेट पर निर्भर हैं तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि अपवादस्वरूप लगाना भी पड़े तो केवल टकराव टालने के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए। चेतन भगत@chetan_bhagat

कैब का विरोध करने के बावजूद मैं पाकिस्तान सरकार और वहां के समाज से अपील करना चाहता हूं कि वे वहां हालात सुधारने के लिए हरसंभव उपाय करें। मसलन हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगे। गैर-मुस्लिमों को भी मुस्लिमों के बराबर अधिकार सुनिश्चित करें। साथ ही पाक की हिंदू-सिख-बौद्ध-ईसाई विरासत को सहेजें।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

महंगाई बढ़ रही है। उद्योग-धंधों पर गाज गिरने से बेरोजगारी चरम पर है। अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता एनआरसी और कैब जैसे मुद्दे हैं।
महेश लांगा@LangaMahesh

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द ही चुनाव प्रचार

विभिन्न मुद्दों को लेकर देश की संसद गरम है। जाहिर है उसकी आंच अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी पहुंच रही है, लेकिन यहां उसकी तपिश कुछ ज्यादा ही महसूस की जा रही है। कारण भी स्पष्ट है राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव। सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है तो पहले चरण तक प्रचार अभियान से दूर रहे राहुल गांधी भी अब विपक्षी गठबंधन की धुरी बन गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कांग्रेस को निशाने पर रखे हुए हैं, वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर हैं। प्रधानमंत्री झारखंड को भरोसा दे रहे हैं, 'भाजपा जो कहती है वह करती है। और मोदी है तो उन्हें किसी और के बारे में क्या सोचना।' ठीक इसके उलट, राहुल गांधी उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ताल ठोककर सुर्खियां बटोरने वाले उन्हीं की कैबिनेट के तेज-तर्रार नेता सरयू राय का 'ड्रामा' जारी है।

गुरुवार को तीसरे चरण की 17 सीटों पर मतदान के साथ अब तक 50 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य इवीएम में कैद हो चुका है। 16 और 20 दिसंबर को चौथे तथा पांचवें चरण में कुल 31 और सीटों पर अभी वोट पड़ना है। प्रधानमंत्री अब तक चार दौरों में सात चुनावी रैलियां संबोधित कर चुके हैं तो राहुल गांधी भी तीन दौरे कर पांच जनसभाओं के जरिये मतदाताओं को साध गए हैं। बेशक, यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है जिसका कांग्रेस हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री के निशाने पर लगातार कांग्रेस ही है। कांग्रेस को लटकाने, अटकाने और वोट के लिए विभाजित करने वाला करार देते हुए वह मतदाताओं को सचेत कर रहे हैं। उदाहरण सहित बता रहे हैं कैसे अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में अनुच्छेद 370, तीन तलाक, पिछड़ों के लिए आयोग का गठन, नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का रवैया शुतुरमुर्गी रहा है और इन सबके चलते देश ने कितना कुछ भुगता है। भगवान राम का यहां के आदिवासियों-वनवासियों से नाता जोड़ने में भी नहीं चूकते। डबल इंजन का फायदा गिनाते हैं और रैलियों में उमड़ रही भीड़ से मुहर लगवा रहे हैं मोदी है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा जो कहती है वह करती है। मतदाताओं को उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। झारखंड का विकास डबल इंजन की सरकार से ही हो सकता है। रघुवर दास की स्थाई और सशक्त सरकार ने पांच साल में झारखंड को सही रास्ते पर डाल दिया है, बस अब इसे अगले पांच साल में समृद्ध राज्य बना देना है।

धनबाद में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जागरण

इधर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि छह महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने नोटबंदी, जीएसटी, दस-पंद्रह उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपये दे देने जैसे प्रधानमंत्री पर उनके आरोप झारखंड ही नहीं देश की जनता नकार चुकी है, लेकिन वह इन्हीं के सहारे विपक्षी गठबंधन की नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके मुद्दों की तरह अंदाज भी नहीं बदला है। हां, अपनी रैलियों में बीच-बीच में प्याज, महंगाई का तड़का जरूर लगा रहे हैं जिसे जनता पसंद भी कर रही है। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर हमलावर हैं। पहले भाजपा इस मुद्दे पर रक्षात्मक थी, लेकिन दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और झामुमो को सीधा निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की नजर झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर है और वह किसी भी सूरत में इनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास लोकसभा चुनाव से ही झामुमो नेता हेमंत सोरेन पर आदिवासियों की जमीन छीनने के गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। झामुमो नेता हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर ज्यादा न बोलकर रघुवर की डबल इंजन सरकार को फेल करार दे रहे हैं।

सरयू के इस्तीफे पर विवाद : मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय ताल ठोक रहे कैबिनेट मंत्री सरयू राय का 'ड्रामा' भी जारी है। दूसरे चरण में यहां मतदान हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे का मसला हल नहीं हुआ है। वह दावा कर रहे हैं कि 17 नवंबर को ही उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया था, लेकिन अब राजभवन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरयू का इस्तीफा मिला ही नहीं है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है वह 'पूरे ड्रामे' का फायदा ले चुके हैं। उनका इस्तीफा भले ही स्वीकार न हुआ हो, भाजपा ने जरूर छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में कई और नेताओं पर भी गाज गिरी है, इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भी करीबी हैं। इस गुटबाजी में अभी कई और के निपटने की उम्मीद है। तय होगा 23 दिसंबर के बाद, यह देखकर कि आखिरी परिणाम क्या रहा?

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या नागरिकता संशोधन विधेयक से देश में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी?

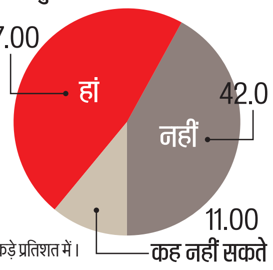

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या डाटा प्रोटेक्शन कानून से लोगों की निजी सूचनाओं में सेंधमारी पर अंकुश लगेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पंचायत ने कर दिया साफ-साफ इंकार,
जन्मभूमि पर अब नहीं होगा पुनर्विचार।
होगा पुनर्विचार बनेगा अब तो मंदिर,
पाएंगे प्रभु राम एक घर सुंदर-स्थिर।
भ्रमित लोग अब बात समझ जाएंगे शायद,
समझाकर दो बार कह चुकी जो पंचायत।
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रसंगवश

पुलिस का चेहरा बदलने की चुनौती

देश भर में पुलिस को अपने कामकाज और रवैये में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। आज के भारत में पुलिसिंग की मौजूदा सूरत से अधिकांश लोग असहमत हैं

ब्रजेंद्र प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए भारत की परिकल्पना की है, उसमें पुलिस का चेहरा बदलना बड़ी चुनौती है। समूचा देश इस वक्त महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए आंदोलित है। खासकर दुष्कर्म और हत्या के बढ़ते अपराध पुलिस के रवैये की व्यापक आलोचना का आधार बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पुणे में आयोजित देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 55वें वार्षिक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव जगाने वाली पुलिसिंग होनी चाहिए।

यह एक संयोग ही है कि जिस वक्त हैदराबाद से उन्नाव तक कि पुलिस कठघरे में खड़ी है, उसी वक्त पुणे में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने पुलिस सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत की सिविल सोसाइटी अब अपराध के खिलाफ सामूहिक तौर पर सड़क पर उतरने लगी है। वह भयमुक्त माहौल और त्वरित न्याय की उम्मीद रखती है। उसे संविधान में यह सब गारंटियां दी गई हैं। ऐसे में न सिर्फ देश के राजनीतिक तंत्र को ही संवेदनशील होना पड़ेगा, वरन अदालतों के भी सचेत होने का यही सही वक्त है।

पीड़ित का पहला वास्ता पुलिस से है, और यदि पहले ही कदम पर उसे मदद की जगह दुत्कार और अपमान मिलेगा तो मुश्किलें बढ़ना तय है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पुलिस की छवि कैसी है? यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने पुणे में पुलिस में सुधार की नसीहत दी, ठीक उसी दिन भारत के गृह मंत्रालय की एक सर्वे रिपोर्ट ने पुलिस को आइना दिखाया है। यह सर्वे रिपोर्ट पुलिस को समग्रता के साथ सोचने के लिए अवश्य विवश करेगी। गृह मंत्रालय ने देश के 15,469 पुलिस थानों में से उन 79 पुलिस थानों के कामकाज पर जनता की राय जानी है जो देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल हैं। इन 79 सर्वश्रेष्ठ थानों के इलाके में रहने वाली महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं से पुलिस के कामकाज के बारे में पूछा गया। इस दौरान 5,641 लोगों से बातचीत की गई। उसका निचोड़ सामने आया है कि आधे से अधिक नागरिक पुलिस के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। न रिपोर्ट दर्ज करने में, न ईमानदारी में और न ही त्वरित कार्रवाई में। पुलिस का यह रवैया सामान्य थानों में कैसा होता है? क्या यह किसी से छिपा है। महिलाओं के मामलों की पड़ताल के लिए बने महिला थानों की भी ऐसी ही हालत है। यानी समग्र रूप से पुलिस के कामकाज सवालिया घेरे में हैं।

पीड़ितों के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा है? इसे अधिकांश लोगों ने महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के जिस उन्नाव जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, उसे पुलिस ने थाने से भगा दिया था। उस पीड़िता की मौत और हैदराबाद के महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद पैदा हुए हालात के बाद इन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर थाने के प्रभारी और कुछ सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। क्या एक लड़की को जिंदा जला दिए जाने के इस मामले में पुलिसकर्मियों को मिली यह सजा पर्याप्त है? इस पर भी विमर्श की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता वाजिब है कि पुलिस सुधार होना चाहिए। परंतु सिर्फ चिंता जाहिर करने भर से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय को पुलिस सुधार के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। पुलिस की छवि इस सर्वे से पहले भी आम लोगों के मन में है और वह नकारात्मक ही है। गृह मंत्रालय को यह सर्वे करा लेना चाहिए कि थानों में कितने फीसद एफआइआर जिला अदालतों के आदेश के बाद दर्ज होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो इस मामले में दो कदम आगे है। दो माह पहले कानपुर के एक थाने में एक बुजुर्ग को पीटकर मार डाला गया। उसका गुनाह यह था कि उसके बेटे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज था और पुलिस उस बुजुर्ग से जानना चाहती थी कि उसका आरोपी बेटा कहां भागा हुआ है? थानों में मनमानी, बल प्रयोग और रिपोर्ट न दर्ज किए जाने की बढ़ती प्रवत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। इस छवि के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है।

भारत में जैसा मान-सम्मान और भरोसा देश की सेनाओं के प्रति है, वैसा ही रोजमर्रा की जिंदगी में साथ खड़े होने का दावा करने वाली पुलिस के लिए क्यों नहीं है? इसका जवाब पुलिसकर्मियों को भी खोजना चाहिए।

प्रतीकात्मक

किसी की छवि एक दिन में न गढ़ी जा सकती है और न बिगाड़ी। यह एक सतत प्रक्रिया है। मोहल्ले में गश्त से लेकर थाने के अंदर किसी अपराध की रिपोर्ट लिखे जाने से लेकर अपराधियों पर कार्रवाई तक, पुलिस को मित्र की तरह नजर आना चाहिए। लेकिन एक सामान्य एफआइआर तक के लिए आम लोगों को किसी नेता, वकील या फिर जिला अदालत का सहारा लेना पड़ता है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक सर्वे करा लेना चाहिए कि थानों में कितने फीसद एफआइआर जिला अदालतों के आदेश के बाद दर्ज होती है। हालिया बहुचर्चित मामलों की पृष्ठभूमि पर ही गौर करें तो पाएंगे कि एफआइआर दर्ज कराने में ही कितनी मुश्किल आई थी।

वैसे प्रयागराज में इसी वर्ष आयोजित कुंभ मेला में पुलिसिंग की एक बेहतर छवि दुनिया देख चुकी है। इन्हीं सीमित संसाधनों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने यह सब कर दिखाया था। मगर मुश्किल ये है कि पुलिस के चेहरे के अधिकांश हिस्से में दाग ही दाग हैं। पुलिस को आइना देखना चाहिए, यह उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अनिवार्य है। आम लोग उसकी छवि से रोज दोचार होते हैं। थाने से बाहर पुलिस की एक रोजमर्रा की छवि चौराहों पर लगे कैमरों में कैद है। किसी बड़ी वारदात के बाद अपनी सुविधानुसार ही पुलिस इन कैमरों को देखती है। कभी इस कैमरों में रिकॉर्ड गतिविधियां जनता के सामने दिखाई जाएं तो पुलिस अपने इस रूप को देखकर गर्व से सीना नहीं तान पाएगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

2025 से यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) अंतरिक्ष में खराब पड़े सेटेलाइट के मलबे को उठाने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। यह दुनिया का पहले स्पेस जंक कलेक्टर अभियान होगा, जिसे क्लीयर स्पेस-1 नाम दिया गया है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 13 दिसंबर 2019

दिल का मर्ज दूर करेगा नींबू और संतरे का छिलका

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गवर्नमेंट प्रेस के पास संतरा खरीदता ग्राहक। जागरण

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज

- इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग के शोध में सामने आए परिणाम
- मोटापे से होने वालीं समस्याओं को भी रोकेंगे ये फल

नींबू और संतरे का रस (जूस) निकालकर जिस छिलके को आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बड़ा गुणकारी है। यह दिल के मर्ज के लिए कारगर दवा है। यह बात इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) के जैव रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एसआइ रिजवी के एक शोध में सामने आई है।

प्रोफेसर रिजवी का कहना है कि इन दिनों फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ा है। यह भले ही आपको स्वादिष्ट लगता होगा, लेकिन इससे लोगों में कोलेस्ट्राल की समस्या बढ़ी है। कोलेस्ट्राल बढ़ने से दिल की समस्याएं बढ़ जाती हैं।

दरअसल, होता यह है कि खून की नली पतली हो जाती है और दिल के अंदर खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे में हार्टअटैक और हार्ट फेल्योर की आशंका बढ़ जाती है, जो जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा भी फास्ट फूड का अधिक सेवन कई बीमारियों की वजह बनता है।

स्वस्थ समाज

इस तरह किया अध्ययन : दिल की बीमारी को रोकने के लिए प्रो. रिजवी ने दो शोध छात्रों रोशन कुमार और फरहान अख्तर के साथ मिलकर 15 चूहों पर डेढ़ साल तक शोध कार्य किया। पहले कुछ चूहों को उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ दिया गया। इसमें कोलेस्ट्राल, नारियल का तेल और कुलिक एसिड दिया गया, जिससे वे काफी मोटे हो गए। चूहों का भार 30 फीसद और ग्लूकोज लेवल 40 फीसद बढ़ गया। साथ ही इंसुलिन लेवल 1.2 से 9.6 हो गया। मोटापा बढ़ने से उनके दिल में खून का प्रवाह थम गया। दिल की मांसपेशियां कमजोर हो गईं और वह रक्त को प्रभावी तरीके से पंप नहीं कर पाईं। इस कारण दिल तक ऑक्सीजन और जरूरी

गवर्नमेंट प्रेस के करीब ठेले पर नींबू बेचता किशोर। जागरण

पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने चूहों को नींबू और संतरे में पाया जाने वाला हेस्पेरेडिन रोजाना एक एमएल लगातार 30 दिन पिलाया। इससे चूहों में उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ का असर कम हो गया। यह केमिकल नींबू और संतरे के छिलके में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि उनका यह शोध जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के जर्नल क्लीनिकल एक्सपेरिमेंटल फॉर्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में प्रकाशित होगा।

2020 में बढ़ जाएगी दिल के मरीजों की तादात : एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में 2020 तक दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। यह दावा पिछले दिनों कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआइ) की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में किया गया है। ऐसे में इविवि के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन इस बीमारी से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। इससे इस तरह की दवाएं तैयार की जा सकेंगी, जो दिल के मरीजों के उपचार के लिए उपयोगी साबित होंगी।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

चाकू वाला रामपुर अब लकड़ी के लिए मशहूर

जागरण विशेष

मुस्लेमीन, रामपुर

- दस हजार से अधिक लोगों को लकड़ी कारोबार के जरिये मिल रहा रोजगार
- दस साल में बनाई पहचान, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरा और विनियर मशीनें रामपुर में

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित एक प्लाइवुड फैक्ट्री। (सभी फोटो जागरण)

नदीम खान

फैसल लाला

अश्विनी अग्रवाल

चाकू का जिक्र आते ही जेहन में रामपुर का नाम आ ही जाता है, लेकिन अब शहर को एक नई पहचान मिल रही है। यह पहचान लकड़ी कारोबार के रूप में है। इस समय रामपुर उत्तर प्रदेश में लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी है। इससे यहां के करीब दस हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहले यहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जो धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से बंद होती चली गईं। रजा टेक्सटाइल्स, रजा शुगर मिल, मक्का मिल, दाल मिल, खेतान फर्टिलाइजर, साइकिल बनाने की हंसा फैक्ट्री, शिवा पेपर मिल और राइस मिलों के बंद होने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, लेकिन लकड़ी कारोबार ने यहां के लोगों को एक नई राह दी।

लकड़ी कारोबारी फैसल लाला रामपुर में लकड़ी कारोबार बढ़ने की वजह बताते हैं कि रामपुर तराई क्षेत्र है। पहले यहां गन्ना बहुत पैदा होता था। सरकारी चीनी मिलें बंद हो गईं और निजी मिलें मनमानी करने लगीं। किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर नहीं मिलता था। ऐसे में किसानों ने गन्ने की खेती बंद कर खेतों में पापुलर और यूकेलिप्टिस के पौधे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद से लकड़ी कारोबार शुरू हो गया। 2009 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आरा मशीनों, विनियर और प्लाइवुड के लाइसेंस जारी किए तो रामपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा लिए। इसके बाद रामपुर में लकड़ी के कारोबार ने तेजी पकड़ी।

दूसरे प्रदेशों में आपूर्ति

किट प्लाई गणपति प्लाइवुड के निदेशक अश्विनी अग्रवाल बताते हैं कि उनके यहां करीब 250 लोग काम करते हैं। उनकी फैक्ट्री में छह एमएम से 18 एमएम तक के प्लाई बोर्ड तैयार होते हैं, जो कोलकाता, बेंगलुरु, सूरत, चेन्नई आदि स्थानों पर सप्लाई होते हैं। रामपुर में करीब 700 करोड़ का सालाना लकड़ी कारोबार है। किट प्लाई का नाम देशभर में जाना जाता है।

प्रदेश की नंबर वन लकड़ी मंडी

आज रामपुर उत्तर प्रदेश की नंबर वन लकड़ी मंडी है। एक प्लाइवुड फैक्ट्री में 200 से 250, विनियर मशीन पर 50 से 60 और आरा मशीन पर आठ से 10 लोग काम करते हैं। इनके अलावा लकड़ी खरीदने और बेचने में भी सैकड़ों लोग लगे हैं। उनकी भी विनियर मशीन है और करीब दो करोड़ का सालाना कारोबार है। नैनीताल रोड पर बिलासपुर गेट के पास और दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पनवड़िया के आसपास रोज सुबह लकड़ी की मंडी लगती है। यहां लोग लकड़ी बेचते और खरीदते हैं। दूसरे जिलों से भी यहां लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक आते हैं। जिला वन अधिकारी एके कश्यप बताते हैं कि रामपुर में 12 प्लाइवुड फैक्ट्रियों के साथ ही 73 विनियर मशीनें और 211 आरा मशीनें हैं। इतनी संख्या प्रदेश के अन्य किसी जिले में नहीं है।

बाहर से आते हैं लकड़ी बेचने

गुलनाज ट्रेडिंग कंपनी के मालिक और लकड़ी के सप्लायर मुहम्मद नदीम खान बताते हैं कि वह लकड़ी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। रामपुर में लकड़ी का पत्ता (विनियर) तैयार होता है, जो देश के कोने-कोने में जाता है। रामपुर में पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सितारगंज, अमरोहा, संभल, गजरौला के लोग भी लकड़ी बेचने आते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

वॉच की तरह स्मार्ट होंगे आपके कपड़े

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

- आविष्कार-आइआइटी प्रोफेसर व छात्रों ने बनाई फ्लेक्सिबल लीथियम आयन बैट्री
- स्मार्ट कपड़ों में सेंसर व डिवाइस को ऊर्जा देने के लिए की जाएगी इस्तेमाल

स्मार्ट वॉच आपने देखी होगी। कलाई पर बंधने वाली यह घड़ी आपकी पल्स रेट के साथ-साथ हृदय की धड़कन के बारे में भी बताती है। आप कितना चले, कितनी कैलोरी बर्न की इसकी जानकारी के साथ-साथ आने वाले फोन कॉल, मैसेज आदि की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। वॉच की तरह ही अब आपके कपड़े भी स्मार्ट होंगे। सेना के साथ-साथ मेडिकल के क्षेत्र में यह अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा। अब तक यह समस्या थी स्मार्ट कपड़ों में लगे सेंसर और डिवाइस को ऊर्जा कैसे दी जाए। आइआइटी कानपुर ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। अब फ्लेक्सिबल लीथियम बैट्री के जरिये पर्याप्त ऊर्जा दी जा सकती है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. कमल कृष्णाकर, प्रो. जे रामकुमार व पीएचडी के छात्र किरणकुमार सुरथी ने देश में ऐसी बैट्री तैयार कर ली जिसका स्मार्ट क्लॉथ पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। प्रो. कमल कृष्णाकर ने बताया कि बैट्री से स्मार्ट कपड़ों में लगे सेंसर व डिवाइस संचालित किए जा सकते हैं। मसलन मेडिकल के क्षेत्र में स्मार्ट कपड़ों में लगी बैट्री से संचालित सेंसर के जरिये शरीर की जांचें की जा सकती हैं।

सेना के काम भी आएगी बैट्री : स्मार्ट कपड़ों में लगने के साथ-साथ ये बैट्री सेना के काम भी आएगी। दरअसल, मिशन के दौरान सैनिकों को जंगल व पहाड़ों के बीच लंबे समय तक रहना पड़ता है। ऐसे स्थान पर बिजली नहीं होती इसलिए उन्हें बैट्री का सहारा लेना पड़ता है। वहां तक भारी वजन की बैट्री ले जाने में सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं। आइआइटी में ईजाद की गई बैट्री का वजन अन्य के मुकाबले में 80 फीसद तक कम है। ये वो सभी उपकरण चलाने में सक्षम हैं, जिनकी सैनिकों को जरूरत होती है।

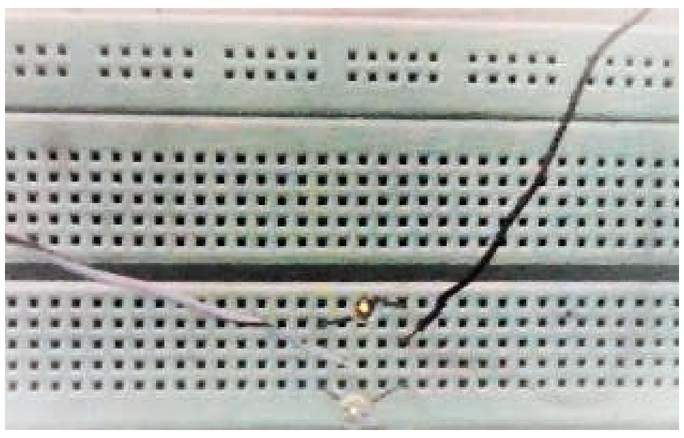

आइआइटी कानपुर में विकसित की गई फ्लेक्सिबल लीथियम आयन बैट्री। आइआइटी कानपुर

ऑटोमोबाइल से एयरोस्पेस तक में इस्तेमाल

प्रो. जे रामकुमार ने बताया कि कैथोड, एनोड व इलेक्ट्रोड की सहायता से बनी इस बैटरी को पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, पावर ग्रिड व रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पेटेंट हो चुका है। अब अन्य उत्पाद बनाने की तैयारी चल रही है।

आज से सजेगा संवाद का मंच

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- भारतेंदु नाट्य अकादमी में 15 दिसंबर तक होगा आयोजन
- तीन दिन तक साहित्यरस, बतरस और काव्यरस का लें आनंद

तीन दिन, बीस सत्र और संवाद की अथाह संभावनाएं समेटे फिर हाजिर है आपका संवादी। जी हां, भारतेंदु नाट्य अकादमी के मंच पर जब 13 दिसंबर को छठे संस्करण का पर्दा उठेगा, तो मंच से दर्शकदीर्घा तक सिर्फ एक ही गूंज होगी, अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति के इस उत्सव में श्रोता वक्ता होते हैं और मेहमान ही मेजबान। रंगमंच, सिनेमा, साहित्य सहित तमाम क्षेत्रों के दिग्गजों से साक्षात्कार कराने वाले संवादी का शुभारंभ शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे पहले सत्र दैनिक जागरण सृजन से होगा। हर बार की तरह यह संस्करण भी इस वादे के साथ पेश है कि साहित्यिक क्षुधापूर्ति के साथ इसकी यादें आपके जेहन में अमिट रहेंगी।

लखनऊ के लोगों के लिए एक यह ऐसा साहित्यिक उत्सव है जहां मुद्दे उठते हैं, मसले मंचासीन होते हैं और मंथन के साथ मार्गदर्शन लेकर संपूर्ण होते हैं। नए लेखक वर्जनाएं तोड़ने को आतुर दिखते हैं तो पुराने जड़ों से दूर न होने की नसीहत देते नजर आते हैं। अदब की दहलीज पर ठिठकती वक्ताओं की भाषा होती है तो आक्रोश को आवाज देते श्रोताओं के सवाल। मंच से जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है तो दीर्घा में बैठकर सवाल करने की स्वतंत्रता भी तो मिलती है। हर अनुभव अद्भुत और अनूठा होता है। दलित और स्त्री साहित्य पर चर्चा जब जोर पकड़ेगी तो जनता उसे हौसले के हिमालय बिठाएगी। सुनहले पर्दे का ख्वाब दिखाने के साथ ही आपको क्षेत्रीय राजनीति के भविष्य से रूबरू कराया जाएगा। धर्म की भाषा पढ़ाने के बाद ही मेहमान संघ का भविष्य आपके सामने रखेंगे। इतने गंभीर चिंतन के बाद साहित्य और सिनेमा के रंग आपको हास्य और गीत से भी रूबरू करेंगे। लखनऊ एक ऐसी सरजमीं है जहां संस्कृतियां आती गईं और यह उन्हें आत्मसात करता गया। इस सब संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करने की चुनौती भी संवादी के समक्ष है तो आप लोगों का संबल भी। ...तो फिर रंग जाइए मेरे रंग में क्योंकि ये मौका फिर एक साल बाद ही आएगा। तो आइए...मंच तैयार है।

कानपुर का मलाल खत्म, गंगा आचमन योग्य : योगी

जागरण संवाददाता, कानपुर

- प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को सीएम ने दिया अंतिम रूप
- सीसामऊ नाले पर ली सेल्फी, अच्छी मेहमाननवाजी की नसीहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर में गंगाजल अब आचमन योग्य हो गया है। अब तक कानपुर वासियों को बड़ा मलाल था कि उनके शहर से मां गंगा प्रदूषित होती हैं। अब यह मलाल खत्म हो गया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जिन्होंने नमामि गंगे के तहत मिशन मोड में यह काम कराया। कानपुर में उतरने से पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से हवा में 19 मिनट तक तीन चक्कर लगाए और गंगा व नालों का हवाई सर्वेक्षण किया।

मुख्यमंत्री गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हेलीपैड पर उतरते ही अटल घाट रवाना हो गए। स्टीमर पर सवार होकर जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरुण, महापौर प्रमिला पांडेय व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार के साथ सीसामऊ नाले तक पहुंचे। इस दौरान रास्ते में जगह-जगह नालों की स्थिति देखी, अधिकारियों को सुझाव भी देते रहे। सीसामऊ नाले पर उन्होंने मंत्रियों व मेयर के साथ सेल्फी भी ली। इसके बाद मीडिया से कहा कि जो नाला गंगा में सबसे ज्यादा गंदगी डालता था, अब वह सेल्फी प्वाइंट बन गया है। नमामि गंगे के तहत कानपुर में इस कार्य से सभी राज्य और शहर प्रेरणा लेंगे। प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने घाट पर किए जा रहे अस्थायी इंतजाम को भी देखा। सीएसए में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री बोले, प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसलिए कहीं भी गंदगी न दिखे। वे कानपुर की अच्छी तस्वीर के साथ यहां से लौटें। मेहमाननवाजी में कोई कमी न रहे। कहा कि मौसम खराब हुआ तो प्रधानमंत्री चकेरी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से आ सकते हैं। इसके लिए सुरक्षा समेत सभी पहलुओं पर वैकल्पिक इंतजाम कर लिए जाएं। जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने अच्छी मेहमाननवाजी में सहयोग के लिए कहा। नमामि गंगे की प्रदर्शनी की तैयारियां, पेंटिंग और पुताई कार्यों को देखकर उन्होंने फर्श पर जमे रंग को साफ कराने का निर्देश दिया।

योगी की सेल्फी... : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे के मद्देनजर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में तैयारियों का जायजा लिया। नमामि गंगे योजना के तहत सीसामऊ नाले को बंद कर बनाए गए सेल्फी प्वाइंट पर उन्होंने सेल्फी भी ली। इस मौके पर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार (दाएं), प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरुण (मध्य में) और शहर की महापौर प्रमिला पांडेय भी मौजूद रहीं। जागरण

गंगा भी नहीं खत्म कर पाई ममता के मन की खटास

जागरण संवाददाता, कानपुर : युगों से भारत भूमि को पवित्र करने वाली गंगा धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषाई भेद से बहुत ऊपर हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कई धाराओं की मिलन केंद्र के लिए राजनीतिक विचारधाराएं एक होने को तैयार नहीं। कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में यह नजर आ रहा है। गंगा के बेहद अहम तीर्थ गंगासागर वाले बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में नहीं होता दिख रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सहमति नहीं आई है। हालांकि, बंगाल की सरकार ने आना खारिज भी नहीं किया है, लेकिन बैठक दिवस के 24 घंटे पहले तक सहमति न आने से माना जा रहा है कि भाजपा से राजनीतिक टकराव के चलते ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगी।

नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की ओर से कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की समीक्षा बैठक हो रही है। राजनीति से दूर, इसका उद्देश्य गंगा की स्वच्छता, निर्मलता, अविरलता पर हुए काम व आगे की कार्ययोजना पर विचार करना है। इसीलिए गंगा के प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। उप्र, उत्तराखंड और बिहार के सीएम की सहमति आ गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कार्यक्रम में लाने के प्रयास में जुटे अफसर मान चुके हैं कि वह नहीं आएंगी।

बिहार के वीटीआर में कर्नाटक के हाथी सीख रहे हिंदी

बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कर्नाटक से लाए गए हाथियों को अब भोजपुरी और हिंदी में कमांड देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वह यहां के महावत की बात का अनुसरण करें। जागरण

रमण शुक्ला, पं. चपारण

बिहार में बाघों की रिहाइश के लिए मशहूर जल, जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित पश्चिम चंपारण का वीटीआर (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) कई मायनों में अद्भुत है। हजारों तरह के पेड़-पौधे वाले खूबसूरत वन क्षेत्र में हाथियों का दीदार और संवाद रोमांच पैदा करता है। नारायणी, सोनभद्र और तमसा की त्रिवेणी और खूबसूरत वादियों के बीच हाथी शेड में रोज द्रोण, मणिकंटा, राजा और बालाजी की पाठशाला लगती है। दरअसल द्रोण, मणिकंटा, राजा और बालाजी ये चार हाथी हैं। चारों कर्नाटक से आए हैं। सिर्फ कन्नड़ जानते हैं। अब हिंदी सीख रहे हैं। ताकि हिंदी भाषी वन कर्मियों द्वारा फारेस्ट ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले आदेशों पर ये अमल कर सकें। वीटीआर के उप निदेशक गौरव ओझा बताते हैं कि फिलहाल इन्हें पेट्रोलिंग का प्रशिक्षण दिया रहा हैं।

भाषा में आवाज और स्वर एक जैसे

कन्नड़ में हाथी को चारों तरफ घूमने के लिए 'सारद' बोला जाता है, जबकि अपने यहां हिन्दी में इन्हें इसके लिए 'चाइघुम' कहा जाता है। इसी तरह पीछे मुड़ने के लिए हिंदी में 'हट' पीछे बोला जाता है, तो कन्नड़ में इसके लिए 'धक पीछे' कहा जाता है। दोनों राज्यों की भाषा में आवाज या स्वर तकरीबन एक जैसी है। कुछ कमांड, तो दोनों जगहों पर समान हैं। जैसे लेटने के लिए दोनों जगहों पर 'टायर' ही कहा जाता है।

बाघ से हो चुका है सामना

वीटीआर के महावत रमेश और जीतेंद्र बताते हैं कि 10 वर्ष का राजा सबसे छोटा है और 14 वर्ष का द्रोण से सबसे बड़ा है। अहम यह है राजा तेजी से हिंदी और भोजपुरी कमांड सीख रहा हैं। हाथियों को हिंदी भाषा से परिचित कराने के लिए हिंदी के साथ-साथ कन्नड़ भाषा में कमांड बोले जाते हैं, ताकि वे कन्नड़ के साथ ही हिंदी और भोजपुरी के कमांड भी समझ सकें। गश्त के दौरान चारों हाथियों का बाघ से सामना हो चुका है। जब वे हिंदी समझने लगते हैं, तो कन्नड़ भाषा में निर्देश बंद कर दिया जाता है। शुरू में कर्नाटक के महावतों ने वीटीआर में रहकर हिंदी और भोजपुरी भाषी महावतों को द्विभाषीय प्रशिक्षण दिया था। हालांकि वे कुछ दिनों बाद ही वापस लौट गए। हाथियों को प्रशिक्षण दिए जाने का कोई तयशुदा फार्मूला नहीं होता है। इन्हें बेसिक कमांड सिखाया जाता है।

उपलब्धि

देश का ऐसा पहला 18 दिवसीय सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट, थर्ड पार्टी से करवाया सत्यापन, जल्द जारी होगा प्रमाण पत्र

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को मिलेगा प्लास्टिक फ्री इवेंट का दर्जा

विनोद चौधरी, कुरुक्षेत्र

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट का दर्जा मिलेगा। यह देश का पहला इतना विशाल इवेंट रहा, जो 18 दिन तक चला और जिसमें लाखों लोग पहुंचे। महोत्सव को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रीन अर्थ संगठन की पांच टीमें लगी रहीं। संगठन को यह सफलता 2010 से लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद मिली है।

23 नवंबर से 10 दिसंबर तक चला महोत्सव ब्रह्मसरोवर के तट पर लगने वाला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चला। इस महोत्सव में गत वर्ष 40 लाख पर्यटक पहुंचे थे। इस बार केडीबी प्रशासन की ओर से संख्या और अधिक होने का दावा किया जा रहा है।

शिल्प और क्राफ्ट मेले में सजे थे 800 स्टॉल : इतना ही नहीं महोत्सव को लेकर लगाए जाने वाले शिल्प और क्राफ्ट मेले में लगभग 800 स्टॉल सजे और करीब 100 फूड स्टॉल लगाए गए। यह अपने आप में एक मिसाल है कि सैकड़ों फूड स्टाल सजने पर भी एक भी प्लास्टिक के चम्मच, कटोरी और थर्मोकॉल का उपयोग नहीं हुआ।

थर्ड पार्टी से करवाया वेरीफिकेशन

इसके लिए गुरुग्राम की एक एजेंसी से थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन करवाया गया। इस एजेंसी ने सर्वे के बाद संतुष्टि जताई और इसे सफल बताया है। जल्द ही इसके लिए सत्यापन पत्र जारी कर दिया जाएगा।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान सरस व क्राफ्ट मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। जागरण आर्काइव

15 सदस्यों की पांच टीमों ने किया दिन-रात काम

ग्रीन अर्थ संस्था के पदाधिकारी डॉ. नरेश भारद्वाज ने कहा कि महोत्सव को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट घोषित कराने के लिए वह लगातार 2010 से प्रयासरत हैं। इस बार शिल्पकारों और अन्य दुकानदारों को जागरूक करने के लिए 15 सदस्यों की पांच टीमों का गठन किया गया। इस टीम ने एक-एक स्टॉल पर जाकर लोगों को जागरूक किया। इसके लिए बाकायदा पंफलेट बांटे गए और कपड़े के बने 150 बैनर महोत्सव में लगाए गए। इस अभियान को जिला प्रशासन का भी सहयोग मिला और वह कामयाब रहे।

पूर्वी घाट पर 87 हजार पॉलीथिन से तैयार कछुए से किया जागरूक

लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण प्रेमियों की ओर से 87 हजार से अधिक पॉलीथिन से कछुआ तैयार कर रखा गया। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के लिए तैयार किए गए इस कछुए के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

महफिल जब शायरों की हो तो भला किसमा मन रुमानी नहीं होना चाहेगा। भले ही यह दृय पिछले वर्ष आयोजित जश्न-ए-रेख्ता का हो लेकिन हर वर्ष कमोबेश यही नजारा होता है। सौजन्य आयोजक

जश्न-ए-रेख्ता

साज करेंगे बात... महफिल देगी साथ

आज से तीन दिन के लिए आप सब कुछ भूलकर जश्न की महफिल में होंगे। दिल से राबता करेंगे। संगीत...शायरी में आपकी सांझ भीगी होगी। क्योंकि जश्न-ए-रेख्ता एक बार फिर आ रहा है साज...संगीत और शायरी का उत्सव लेकर। क्या-क्या होने वाला है खास...कैसे जुड़ेंगे आपके दिल के तार...सबरंग के इस अंक में कैसी होंगी जश्न की खास शाम इसी से रूबरू करा रहे हैं

संजीव कुमार मिश्र :

गजल जहां कहानी सुनाएगी... कलाम-ए-कबीर भी होगा। मुशायरे के साथ सुर साज व सितार होगा। बालीवुड की बेगम और बाईजी, मीर, मिर्जा गालिब एक-एक कर आपके सामने ऐसे सेशन आते जाएंगे कि आप कुर्सी पर बैठे महफिल लूटने वालों की वाहवाही में ही मशगूल रह जाएंगे। सूफी संगीत, दास्तानगोई, बहस-मुबाहिसे, मशहूर हस्तियों से बातचीत आदि तो होंगी ही, फिल्मों में भाषा के पहलू पर भी चर्चा होगी। इन सबके जरिये उर्दू की विरासत को दिखाया जाएगा। समकालीन और शास्त्रीय साहित्य पर विचार विमर्श, कथा साहित्य पर चर्चा, फिल्म, कला और संस्कृति के अन्य विषयों पर होगी दिलचस्प बातचीत भी होगी। वहीं फूड कोर्ट में दिल्ली, लखनऊ के लजीज जायकों का भी अलग ही अंदाज-ए-बयां होगा।

साहिर तेरा भी क्या 'साहिर' रहा : लुधियाना के एक जागिरदार घराने में पैदा हुए साहिर की जिंदगी किसी किताब से कम नहीं है। मां-पिता धनी जरूर थे लेकिन उनसे अलग रहने के कारण तंगी भरे दिन भी देखे। कॉलेज के दिनों में शेर-ओ-शायरी से छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय रहे साहिर को इश्क की वजह से कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। 1943 में प्रकाशित पहली पुस्तक तल्खियां के बाद साहिर लोकप्रिय हो गए थे। 1949 में साहिर दिल्ली आ गए थे एवं यहां से फिर मुंबई का सफर तय किया। साहिर के लुधियानवी, दिल्ली से होकर मुंबई के सफर समेत उनकी जिंदगी की किताब के पन्नों को दर्शकों के सामने पलटेंगे जावेद अख्तर। सैफ महमूद संग परिचर्चा मैं पल दो पल का शायर हूं शीर्षक से होगी। यह सेशन 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर होगा।

गजल सुनाएगी अपनी कहानी : एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह गजल है। गजल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। कहानी गजल की सेशन दरअसल इसके इतिहास से दर्शकों को रूबरू कराता है। गजल क्या होती है। कैसे बनती है। प्रमुख साहित्यकारों के बारे में यह सेशन विस्तार से बताएगा। प्रसिद्ध गजल गायक चंदन दास, राधिका चोपड़ा और दिग्गज अभिनेता रजा मुराद की यह परिचर्चा दर्शकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन करेगी। यह सेशन 14 दिसंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे से आयोजित होगा।

ग्रैंड मुशायरा : मुशायरा का ग्रैंड शो। कितना दिलचस्प होगा। इसमें आपको समकालीन प्रसिद्ध उर्दू शायरों को सुनने का मौका मिलेगा। मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, खुशबीर सिंह शाद, मुकेश आलम, निजामत मोइन शादाब, अज्म शकरी, मुकेश आलम शरीक होंगे। यह महफिल सजेगी 14 दिसंबर की शाम को।

तुम मीर को सुनो : उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर यानी खुदा-ए-सुखन मुहम्मद तकी उर्फ मीर तकी। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य हो। अहमद शाह अब्दाली और नादिरशाह के हमलों से कटी-फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखी और अपनी रचनाओं के जरिए प्रस्तुत किया।

हमको शायर न कहो मीर कि साहिब हमने
दर्दों गम कितने किए जमा तो दीवाना किया।।

इस सेशन में मीर की जिंदगी और उनकी रचनाओं को गोपीचंद नारंग की जुबानी जानने एवं सुनने का मौका मिलेगा।

दास्तानगोई की बात... : जश्न-ए-रेख्ता की महफिल हो और दास्तानगोई की बात ना हो, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। इस बार भी महफिल में चार चांद लगाने के लिए दास्तानगोई होगी। फौजिया जहां दास्तान-ए-महाभारत पेश करेंगी वहीं हिमांशु वाजपेयी दास्तान ए लखनऊ प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ के इतिहास को हिंमाशु की आवाज में सुनना एक दिलचस्प अनुभव होगा।

जानिए पीयूष मिश्रा को : एक अन्य दिलचस्प सत्र जिंदगी : आवाज से अंदाज तक में अभिनेता, पटकथा लेखक और कवि पीयूष मिश्रा अपनी जिंदगी के विविध पहलुओं पर दर्शकों से बातें करेंगे। इस सेशन में पीयूष अपने जीवन और अपनी रचना के रचनात्मक पहलुओं को साझा करेंगे। यह सेशन 15 दिसंबर को शाम पांच बजे आयोजित होगा। जबकि एक अन्य सत्र कुछ दिल की कुछ दुनिया की में लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या दत्ता से गुफ्तगु करेंगी रिचा अनिरुद्ध। इसमें दिव्या अपनी कविताओं के बारे में बात करेंगी। उनकी रचनाएं, भाषा किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, के बारे में बात करेंगी। यह सेशन 15 दिसंबर की शाम साढ़े तीन बजे आयोजित होगा।

गांधी दर्शन में उर्दू : महात्मा गांधी सभी धर्मों के लोगों के प्रिय थे। गांधी के दर्शन में उर्दू की क्या भूमिका थी? यह जानने एवं समझने का मौका मिलेगा गांधी के दर्शन में गांधी सेशन में। देश गांधी जी की 150 वी जयंती मना रहा है। ऐसे में उनके पोते तुषार गांधी दर्शकों को बताएंगे कि गांधी के दर्शन में उर्दू की क्या भूमिका थी एवं भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर उनके प्रभाव पर वे अपने विचार साझा करेंगे।

गुरु नानक देव को समर्पित : गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को समर्पित यह विशेष सत्र में भाई बलदीप सिंह विलुप्त हो रही सदियों पुरानी गुरु-सिख विरासत को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कलमी (लिखित), तंत्र (ऑडियो) की प्रस्तुति यादगार होगी। यह 15 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे होगा।

- **आयोजन** : जश्न-ए-रेख्ता
- **कहां** : मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट।
- **कब** : 13 से 15 दिसंबर तक, सुबह 11 से रात नौ बजे तक।
- **प्रवेश** : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा।
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : प्रगति मैदान।

ऐवान-ए-जायका

जश्न-ए-रेख्ता में शेर-ओ-शायरी की महफिल सजने के साथ ही लजीज जायका भी होगा। जो साहित्य के कद्रदानों को यादगार जायके की यादें भी सहेजने का मौका देगा। फूड फेस्टिवल में अवधी, हैदराबादी, पुरानी दिल्ली, रामपुरी, कश्मीरी, पारसी और पंजाबी से लेकर 15 से अधिक तरह के जायके होंगे।

कविता पाठ का खुला सत्र

दो दिनों में कई सत्र ऐस होंगे जिसमें दर्शकों को अपनी कविता और कहानी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। यह उत्सव नवोदित कवियों को ओपन माइक (खुली निशस्त) कविता सत्रों के माध्यम से अपनी कविता सुनाने का मंच भी देता है।

जश्न-ए-रेख्ता के 6 वें संस्करण की दहलीज पार करते हुए मैं मुड़कर उर्दू भाषा, साहित्य, संस्कृति और हिंदुस्तानी के इस उत्सव की पहुंच, पैमाने और लोकप्रियता को अपार संतुष्टि के साथ देखता हूं। 2015 में एक अपेक्षाकृत छोटी शुरुआत के साथ, जश्न-ए-रेख्ता दुनिया में कहीं भी किसी भी एक भाषा का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मध्य पूर्व सहित दुनिया भर के लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने वार्षिक कैलेंडर का हिस्सा बनाया है। संतुष्टि तब होती है जब दर्शकों की अपार संख्या जश्न में शामिल होती है।

संजीव सराफ, संस्था रेख्ता फाउंडेशन

अब जरा फ्रेमनुमा कार के साथ एक फोटो हो जाए। पिछले वर्ष दर्शकों में कुछ ऐसा ही उत्साह नजर आया। सौजन्य : आयोजक

इस बार यहां चलें

सकारात्मक सोच के साथ संदेश

कलावती ग्रुप ऑफ आर्ट की यह प्रस्तुति सकारात्मक सोच से जिंदगी में आए बदलाव को दर्शाती है। जीवन में बहुत सी अड़चनें आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हो तो आसानी से इनसे लड़ सकते हैं। जिंदगी के इसी फलसफे को बताती इस प्रदर्शनी में स्वपना दास समेत अन्य कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।

- **कहां** : विजुअल आर्ट गैलरी, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** :15 दिसंबर तक, सुबह 11 से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

प्रलय

रासाजा फाउंडेशन की यह यूनिक प्रस्तुति आपके दिल को छू लेगी। प्रलय दरअसल भरतनाट्यम प्रस्तुति है, जिसमें बाली नृत्य का भी समायोजन होगा। महाभारत की कथा को केंद्र में रखकर इस नृत्य प्रस्तुति का तानाबाना बुना गया है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आएगा।

- **कहां** : कमानी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली।
- **कब** : 13 दिसंबर, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

अगर वो देश बनाती

यह ऐसी फिल्म है जिसमें एक महिला के नजरिए से देश और समाज का चित्रण किया गया है। आदिवासी क्षेत्र की महिला देश को बदलते देखना चाहती है। उसके गांव के आसपास पावर प्लांट बनते चले जा रहे हैं। वह अपनी जमीन को इसमें जाते देखती है। ऐसे में वह अपने और गांव के लिए न्याय की मांग करती हैं।

- **कहां** : गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** :14 दिसंबर, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

वार्षिक कला प्रदर्शनी

92वां वार्षिक कला प्रदर्शनी में पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर और ग्राफिक की प्रदर्शनी देख सकेंगे। पेंटिंग सेशन में 579 कलाकारों ने 1130 पेंटिंग सबमिट की थी, जबकि स्कल्पचर श्रेणी में 87 कलाकारों ने 157 एंट्री भेजी थी। वरिष्ठ कलाकारों की एक ज्यूरी ने निष्पक्षता के साथ उपयुक्त कलाकृतियों का चयन किया है।

- **कहां** : ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी, नई दिल्ली।
- **कब** : 25 दिसंबर तक, सुबह 11 से शाम सात बजे तक। ● **प्रवेश** : निश्शुल्क।

जायका

आलू टुक और भुगल चिकन का सिंधी स्वाद

साई भाजी, तड़ियल आलू, आलू टुक, अरबी टुक, सना पकौड़ा, सेयल तीवन, भुगल चिकन इन जायकों के नाम सुने हैं? आपमें से बहुत कम लोग ही इन जायकों से परिचित होंगे। क्योंकि ये सिंधी जायके किसी भी रेस्त्रां या होटल्स में बमुश्किल ही मिलते हैं। मुंबई व राजस्थान तक सीमित सिंधी डिशेज की करीब दो सौ रेसिपीज को शेफ पीयूष वाधवानी दिल्ली-एनसीआर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

ऐसे हुई शुरुआत : एमबीए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पीयूष ने विभिन्न रेस्त्रां और होटल्स में काम किया। फूड ज्वाइंट्स में बतौर क्यूरेटर व फूड डिविजन में रहे। मां की बीमारी के कारण वे बचपन में ही घर की रसोई में कामकाज करने लगे थे। पहले तो उन्हें यह काम दबाव में करना पड़ता, लेकिन बाद में उन्हें इसमें आनंद आने लगा।

लोगों को चखा रहे सिंधी स्वाद : रसोई में पीयूष का मन इतना रम गया कि धीरे-धीरे वे सिंधी रेसिपीज पर प्रयोग करने लगे। उन्होंने प्रयोग के जरिए दो सौ से ज्यादा अपनी रेसिपीज बना ली हैं। उन्होंने मां से सीखे सिंधी क्यूजीन को अलग टच देकर रीजनल क्यूजीन बनाना शुरू किया। दाल पकवान, सिंधी कढ़ी, साई भाजी, तड़ियल आलू, आलू टुक, अरबी टुक, सना पकौड़ा के अलावा नॉनवेज में सेयल तीवन, भुलग चिकन, तरियल फिश, सेयल फिश, दादी मां की विशेष मटन कमल ककड़ी और कीमा मगज जैसी रेसिपीज को वे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न कंपनियों में रहते हुए मैरिनेशन व ग्रेवी में अलग से डिग्री प्राप्त की है। लिहाजा उन्हें अच्छी तरह पता है कि किस तरह से परफेक्ट ग्रेवी बनाई जाती है। पीयूष कहते हैं कि मैरिनेशन व ग्रेवी ऐसी चीज है, जिसमें सामग्री का अनुपात घटा या बढ़ाकर नई डिश बनाई जा सकती है।

चाय के साथ दाल पकवान का स्वाद : अगर आप संडे की सुबह किसी सिंधी परिवार में जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से दाल पकवान का स्वाद मिलेगा। दाल में मैदा को छानकर बनी हुई क्रिस्पी प्यूरी मिलाई जाती है। इसे चना दाल के साथ स्पाइसी मीठी और टैंगी डिप्स के साथ परोसा जाता है। मैदा के बने पकवान को दही छोले और चटनी के साथ चाट की तरह या चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी अलग से उपयोग में लाया जा सकता है।

शेफ पीयूष वाधवानी

भुगल चिकन सौजन्यः शेफ

सेयल तीवन (सिंधी स्टाइल मटन करी)

इस विशेष डिश को बनाने के लिए 750 ग्राम मटन, छह से सात प्याज कटे हुए, तीन से चार टमाटर कटे हुए, एक कटोरी दही, कटी हुई तीन से चार मिर्च, आठ से दस लहसुन, अदरक, दो तेज पत्ता, दालचीनी स्टिक, कीली इलायची दो, दो से तीन चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच पीली मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच इलायची के दाने, एक चम्मच कसूरी मेथी, रिफाइंड, घी या तेल, नमक स्वादानुसार, धनिया पत्ते, गरम मसाला। कड़ाही में तेल गरम करके सभी मसाले मिला दें, खुशबू आने पर लहसुन-अदरक पेस्ट मिलाएं, एक मिनट तक भूनें, मटन पीस मिलाकर तेज आंच पर तब तक भूनें जब तक रंग न बदल जाए। अब कसूरी मेथी व हरी इलायची पाउडर को छोड़कर कटा प्याज व अन्य मसाले मिलाएं। अब इसे ढंक कर धीमी आंच पर पकाएं ताकि रंग बदल जाए। फिर नमक, कटी हुई हरी मिर्च और कटे टमाटर मिलाएं और कम आंच पर तबतक पकाएं जब तक टमाटर मुलायम न हो जाए। इसमें हिलाते हुए दही मिलाएं। दस से बारह मिनट तक पकाएं। मसाला न चिपके इसके लिए बीच-बीच में हिलाते रहें। पकने के बाद इलायची के पिसे हुए दाने और कसूरी मेथी डालें। इस पर धनिया पत्ता और गरम मसाला डालकर सजाएं। इसे रोटी, चावल व सलाद के साथ परोसें।

प्रियंका दुबे मेहता

सोपान उत्सव

सिद्दी गोयल सौजन्य : आयोजक

पारंपरिक कला में पारंगत युवाओं की प्रस्तुति

दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में तो खूब शॉपिंग की होगी, सर्द मौसम के दौरान सेंट्रल पार्क में बैठ धूप का भी मजा लिया होगा, पर क्या वहां शास्त्रीय नृत्य और संगीत का लुत्फ उठाया है। अगर नहीं तो इस खूबसूरत शाम को इंज्वॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। आज से शुरू हो रहे छह दिवसीय सोपान उत्सव में 24 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति आपका मन मोह लेगी।

पारंपरिक कला का प्रदर्शन : सोपान, द फेस्टिवल ऑफ यंग म्यूजिशियन और डांसर्स, साहित्य कला परिषद से जुड़े युवा कलाकारों को बेहतरीन मंच प्रदान करने का जरिया है। ये सभी कलाकार साहित्यकला परिषद द्वारा छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं, जो कथक, भरतनाट्यम, ओडिशी और शास्त्रीय संगीत जैसे पारंपरिक कला से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमें इन युवा और नए सितारों पर गर्व है। ये हमारी पारंपरिक भारतीय कला को जीवंत बनाते हैं।

अष्टपदी में राधा की शिकायत : पहले दिन जी राघवेंद्र प्रसाद की वायलिन और कथक पर गरिमा आर्य चतुरलाल की प्रस्तुति होगी। उसके बाद अंकिता कौशिक द्वारा भरतनाट्यम और अंत में अल्लारिपु अपनी कला से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। दूसरे दिन रिया बनर्जी अपने संगीत से दर्शकों का दिल जीत लेंगी वहीं भानु सिसोदिया की पखावज पर प्रस्तुति भी देखने लायक होगी। तीसरे दिन शिवम दुबे की संगीतमय प्रस्तुति के बाद कोमल निर्वाण वायलिन, यामिनी दीक्षित ओडिशी और वृंदा बाहेती द्वारा कथक की प्रस्तुति होगी। चौथे दिन गुरु कनक सुधाकर की एक वरिष्ठ शिष्या तान्या गंभीर भरतनाट्यम में दो कृति करेंगी और अपना प्रदर्शन भगवान कृष्ण को समर्पित करेंगी। उनकी प्रस्तुति में भगवान को दो अलग-अलग मनोदशाओं में दर्शाया गया है। पहला अष्टपदी याही माधव का है, जिसमें राधा कृष्ण के अन्य गोपियों के साथ व्यवहार की निंदा कर रही हैं। वह एक खंडिता नायिका में बदल जाती हैं जो भैरवी व तामुल आसि को स्थापित करती है।

सर्व शक्तिमान के लिए शिव का आह्वान : उत्सव में भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति भी बेहद खास है। मुरादाबाद घराने से ताल्लुक रखने वाले मेहताब अली खान भरतनाट्यम तो अनन्या चटर्जी और सलोनी कपूर द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य देख आनंदित हो उठेंगे। आखिरी दिन पवित्रा चारी विलंबित और द्रुत ख्याल और निर्गुण भजन प्रस्तुत करेंगी तो रोमन दास, तान्या सक्सेना, कमलिनी दत्त का परफॉरमेंस होगा। अभिनव मुखर्जी बहुआयामी कलाकार हैं। वह शाम को अपने कथक प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे, जिसमें वे 3 टुकड़े प्रस्तुत करेंगे। शिव वंदना जो सर्व शक्तिमान के लिए एक आह्वान है, इसके बाद ताल धमार, कथक का एक शुद्ध अमृत पहलू है और अंत में कृष्ण लीला के साथ उनका प्रदर्शन समाप्त होगा।

संजीव कुमार मिश्र

- **आयोजन** : सोपान
- **कहां** : सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस।
- **कब** : 13 से 18 दिसंबर, शाम छह बजे से।
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : राजीव चौक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

तान्या सक्सेना सौजन्य : आयोजक

थियेटर फेस्टिवल

स्पर्श नाट्य रंग द्वारा आयोजित चार दिवसीय थियेटर फेस्टिवल का सातवां संस्करण एक बार फिर हाजिर है। इसमें दिल्ली स्थित स्पर्श नाट्य रंग की नाड़ी परीक्षा और पति गए री काठियावाड़ का मंचन के साथ ही जयपुर स्थित क्यूरियो के नाटक फ्लर्ट का भी बेहतरीन मंचन दर्शक देख पाएंगे। इस वीकेंड थियेटर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यहां जाएं।

- **कहां** : श्रीराम सेंटर, मंडी हाउ, नई दिल्ली।
- **कब** : 12 से 15 दिसंबर।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

येति-द हिमालयन किचन

मुगलई जायकों से इतर तिब्बती और नेपाली जायके का लुत्फ उठाना चाहते हैं। नूडल्स, चिली चिकन, चिकन मोमोज, मटन मोमोज, वेज मोमोज, वेज ढुपका समेत लाजवाज जायके का कुछ नया स्वाद चाहते हैं तो येति जरूर जाएं। शांत वातावरण और लाजवाब स्वाद से वीकेंड में तरोताजा हो जाएंगे।

- **कहां** : बी ब्लॉक, इनर सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
- **कब** : दोपहर 12 से रात साढ़े ग्यारह बजे तक। ● **शुल्क** : 1900 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

सुराही

चिली मशरूम, ग्रीन पाइन एप्पल सलाद हो या फिर पाश्ता, नूडल्स, चाइनीज जायका, राइस के विविध जायके या पनीर सुराही की बात ही जुदा है। एक बार यहां बिरयानी, पुलाव समेत नॉर्थ इंडियन जायका चख कर देखें। स्वाद इतना लाजवाब है कि बार बार आना चाहेंगे।

- **कहां** : एम ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
- **कब** : दोपहर 12 से रात साढ़े ग्यारह बजे तक।
- **शुल्क** : 1300 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

नेस्ले पर 73 करोड़ रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का फायदा नहीं देने पर एफएमसीजी कंपनी नेस्ले को 73.15 करोड़ रुपये जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। कंपनी को यह पैसा उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा कराना होगा। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि नेस्ले ने टैक्स में कटौती के साथ उत्पादों की कीमतें कम कर दी हैं। एनएए ने कंपनी की ओर से टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाया है।

एसएमई के लिए एंजल निवेशक कहां से आएंगे, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
— राजीव कुमार
वाइस चेयरमैन, नीति आयोग

सेंसेक्स	40,581.71	169.14
निफ्टी	11,971.80	61.65
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,564	₹71
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 44,984	₹359
डॉलर	₹ 70.83	₹0.02
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 64.78	

कारपोरेट हलचल

आइपी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन

आइपी यूनिवर्सिटी ने साल 2019 के लिए अपना सालाना कन्वोकेशन द्वारका कैम्पस में तीन दिसंबर को आयोजित किया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विशेष अतिथि थे। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बीते तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए यूनिवर्सिटी ने 68,662 डिग्रियों का वितरण किया।

दिल्ली ट्रांसको का पारेषण तंत्र

दिल्ली ट्रांसको की सीएमडी श्रीमती पद्मिनी सिंघला ने कहा है कि उनकी संस्था ने अपने ढांचे को इस प्रकार विकसित किया है कि वह आपदा का सामना सक्षमता से कर सके। दिल्ली ट्रांसको अपने ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड बनाने की दिशा में अग्रसर है। सिंघला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्पेशल सेंटर के डिजास्टर रिसर्च द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए दिल्ली ट्रांसको ने एमर्जेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम खरीदा है जिसे क्षतिग्रस्त टावर के स्थान पर लगाकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भेल का सीएसआइआर संग करार

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सीएसआइआर के साथ एक करार किया है। इसके तहत भेल सीएसआइआर द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक और उनके अमल में सहयोग करेगी। करार के अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट वाटर प्योरिफायर के कॉमर्शियलाइजेशन का लिया गया है।

सरकार पर औद्योगिक उत्पादन व महंगाई दर की दोहरी मार

सांसत ▶ अक्टूबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन में 3.8 परसेंट की कमी

नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 परसेंट पर पहुंची

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत तलाश कर रही सरकार को औद्योगिक उत्पादन और खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने निराश किया है। कारखानों के उत्पादन में अक्टूबर में 3.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब कारखानों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। वहीं, खुदरा महंगाई की दर नवंबर में 5.54 परसेंट पर पहुंच गई, जो बीते तीन साल में सर्वाधिक है। अक्टूबर में यह 4.62 परसेंट थी।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2018 में औद्योगिक उत्पादन (आइआइपी) में 8.2 परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन इस वर्ष अक्टूबर में बिजली, खनन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के चलते देश में कारखानों का कुल उत्पादन 3.8 परसेंट पर सिमट गया। इस अवधि में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में 2.1 परसेंट की कमी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 8.2 परसेंट की दर से बढ़ा था। इसी तरह बिजली

प्रतीकात्मक

के उत्पादन में भी 12.2 परसेंट की कमी अक्टूबर 2019 में दर्ज की गई है। जबकि पिछले साल अक्टूबर महीने में इसमें 10.8 परसेंट की वृद्धि हुई थी। खनन का उत्पादन भी बीते साल के 7.3 परसेंट वृद्धि के मुकाबले इस साल अक्टूबर में 8 परसेंट कम हुआ।

निवेश का बैरोमीटर माने जाने वाले कैपिटल गुड्स सेक्टर के उत्पादन में अक्टूबर 2019 में 21.9 परसेंट की कमी दर्ज की गई है। जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का उत्पादन 18 परसेंट कम हुआ है। औद्योगिक श्रेणियों के लिहाज से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 23 में से 18 श्रेणी में उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ खाद्य उत्पादों की ऊंची कीमतों के चलते नवंबर में खुदरा महंगाई की दर 5.54 परसेंट पर पहुंच गई।

ईंधन के मामले में राहत की संभावना

पेरिस, एएफपी : पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और इसके सहयोगी देशों की तरफ से उत्पादन में अतिरिक्त कटौती के बावजूद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भंडार कम होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि कच्चा तेल और महंगा नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने कहा कि ओपेक और इसके सहयोगी देश पिछले हफ्ते कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना पांच लाख बैरल कटौती करने पर सहमत हुए हैं। ओपेक के सबसे बड़े उत्पादक सदस्य सऊदी अरब ने स्वेच्छा से दैनिक उत्पादन में चार लाख बैरल कटौती की इच्छा जताई थी। आइईए का कहना है कि इनमें से अधिकांश कटौती पहले ही की जा चुकी है। नए समझौते के बाद रोजाना उत्पादन में नवंबर के स्तर की तुलना में 5.30 लाख बैरल की कमी आएगी। यदि कड़ाई से कटौती की जाती है तब भी अगले साल के शुरुआती छह महीनों के दौरान कच्चे तेल का बड़ा भंडार मौजूद रहेगा।

एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

- नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा को दी जानकारी
- चालू वित्त वर्ष में कंपनी को साढ़े आठ हजार करोड़ से अधिक घाटे का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने प्रस्तावित विनिवेश प्रक्रिया के तहत विमानन कंपनी एयर इंडिया में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय विमानन कंपनी पर फिलहाल 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। यह लंबे समय से घाटे में चल रही है। इसका विनिवेश पटरी पर लाने के लिए सरकार ने इसका विनिवेश करने का फैसला किया है।

नागरिक विमानन मंत्री पुरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि नई सरकार के गठन के बाद एयर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआइएसएएम) का दोबारा गठन किया गया है और एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की दोबारा शुरू की गई प्रक्रिया मंजूर कर ली गई है। एआइएसएएम ने 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

एयर इंडिया को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। पुरी ने कहा कि विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें जेट एयरवेज के विमान दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर करना भी शामिल है। जेट एयरवेज ने अप्रैल में नकदी के संकट की वजह से परिचालन बंद कर दिया था। पुरी ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने अगले पांच वर्षों में देश के कई एयरपोर्ट के नवीनीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये

प्रतीकात्मक

निवेश का लक्ष्य रखा है।

इस बीच, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) के महानिदेशक एलेक्जेंडर डि जुनिएक ने एयर इंडिया का विनिवेश उचित और पारदर्शी तरीके से होने की उम्मीद जताई है। एसोसिएशन ने यह भी उम्मीद जताई है कि फैसले से विमानन उद्योग फिर से खड़ा होगा। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को एयर इंडिया का विनिवेश इस तरह करना चाहिए कि देश के विमानन सेक्टर में स्पर्धा बढ़े। उनका कहना था कि निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के दिवालिया प्रक्रिया में जाने से देश में विमानन सेक्टर की स्थिरता और स्थायित्व पर सवाल खड़े होते हैं।

दो लाख करोड़ डॉलर की पहली कंपनी बनी अरैमको

रियाद, एपी : सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरैमको शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दूसरे ही दिन दो लाख करोड़ डॉलर की बाजार वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। अरैमको को पहले ही दुनिया की सबसे कीमती लिस्टेड कंपनी होने का श्रेय हासिल है। दूसरे स्थान पर अमेरिका की कंपनी एपल है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.19 लाख करोड़ डॉलर है। गुरुवार को रियाद के तदावुल शेयर बाजार में ट्रेडिंग बंद होने से तीन घंटे पहले अरैमको का शेयर 38.60 रियाल यानी 10.29 डॉलर पर रहा। कंपनी ने आइपीओ की प्राइसिंग 32 रियाल (8.53 डॉलर या करीब 604 रुपये) प्रति शेयर तय की थी और प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचकर 25.6 अरब डॉलर जुटाए। इस आइपीओ ने 2014 में अलीबाबा का आइपीओ के जरिए 25 अरब डॉलर की जुटाने का रिकॉर्ड तोड़ा है।

बुधवार को शेयर बाजार में पहले दिन की ट्रेडिंग में कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत उछाल के साथ 35.2 रियाल (9.39 डॉलर) पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव के लिए 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय की गई है। व्यक्तिगत निवेशक के रूप में अरैमको के शेयर केवल सऊदी अरब के निवेशक ही खरीद सकते हैं।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानकों पर पूरी तरह खरा है आयुर्वेद : नाइक

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- आयुर्वेद पर आयोजित सेमिनार में 61 देशों के राजनयिकों ने लिया हिस्सा
- वैश्विक पटल पर आयुर्वेदिक दवाओं को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी

भारत अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मानकों पर खरी आयुर्वेदिक दवाओं को वैश्विक पटल पर बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित समिनार में 61 देशों के राजनयिकों ने हिस्सा लिया। इससे पहले आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि डायबिटीज के इलाज के लिए सीएसआइआर द्वारा विकसित आयुर्वेदिक दवा बीजीआर-34 को सभी क्लीनिकल ट्रायल में सफल पाया गया है।

आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद विज्ञान की संभावना' पर आयोजित सेमिनार का उद्देश्य सभी राजनयिकों को आयुर्वेद में हुए उन्नत अनुसंधान और हाल की प्रगति के बारे में जानकारी देना था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार और मान्यता दिलाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर श्रीपद नाइक ने कहा कि आयुष मंत्रालय विश्व स्तर पर आयुर्वेद और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आयुष सेवाओं के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता मानकों को मजबूत मनाने के लिए कई पहल की गई है। इस अवसर पर राजदूतों और उच्चायुक्तों को भारत में आयुर्वेद प्रणाली के मजबूत बुनियादी ढांचे और विनियामक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

पिछले हफ्ते लोकसभा में नाइक ने बताया था कि सीएसआइआर द्वारा विकसित डायबटीज की दवा बीजीआर-34 को आधुनिक चिकित्सा मानकों के तहत किए गए क्लीनिकल ट्रायल में प्रभावी पाया गया है। उन्होंने कहा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुए स्वतंत्र परीक्षणों में भी इसे प्रभावी पाया गया। नाइक ने कहा कि सीएसआइआर की लखनऊ स्थित दो प्रयोगशालाओं सीमैप और एनबीआरआइ ने आयुर्वेद के प्राचीन सूत्रों पर शोध करने के बाद इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मानकों पर विकसित किया था।

राज्यों को जल्द मिलेगा जीएसटी कंपेंसेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जीएसटी कंपेंसेशन पर राज्यों की तरफ से बढ़ते जा रहे विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बारे में जो भी वैधानिक प्रावधान हैं, केंद्र सरकार उन्हें पूरा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस वर्ष अगस्त के बाद से राज्यों को जीएसटी कंपेंसेशन की राशि नहीं मिली है। लेकिन यह भी वादा किया कि यह राशि उन्हें दी जाएगी। हालांकि यह कब दी जाएगी इसका उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वित्त मंत्री राज्य सभा में अनुदान मांगों पर जारी बहस पर जवाब दे रही थीं तब जीएसटी को लेकर कई सांसदों की तरफ से चिंता जताए जाने पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। अगले सप्ताह ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी मुद्दों पर बात होनी है। इस बैठक में कुछ उत्पादों पर जीएसटी की दर बढ़ाने के विकल्प पर भी विमर्श किया जाना है।

फास्टैग के लिए केवाईसी से छूट संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केवाईसी के कारण कंपनियों व ट्रांसपोर्टरों को फास्टैग लेने में दिक्कत
- अड़चनों के कारण और बढ़ सकती है फास्टैग अनिवार्यता की तारीख

वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख एक बार फिर बढ़ सकती है। फास्टैग को हासिल, एक्टिवेट और रिचार्ज करने के अलावा इस्तेमाल करने में आने वाली प्रक्रियागत और तकनीकी समस्याओं के कारण सरकार को ऐसा करना पड़ सकता है। सरकार ने बैंकों से फास्टैग हासिल करने में केवाईसी को बड़ी अड़चन माना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आरबीआइ से फास्टैग के लिए केवाईसी की अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार गडकरी ने इस संबंध में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की है। गडकरी का यह भी मानना है कि जिन ड्राइवरों के पास फास्टैग नहीं है उन्हें फास्टैग देने की व्यवस्था हर टोल बूथ पर होनी चाहिए।

मौजूदा व्यवस्था के तहत बिना फास्टैग वाहनों के ड्राइवरों से कैश लेन में दोगुना टोल देने का प्रावधान है। फास्टैग को पहली दिसंबर से ही अनिवार्य होना था। लेकिन कई अड़चनों के कारण एनएचएआइ ने फास्टैग अनिवार्यता की तारीख को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। दिक्कतों के न सुलझने के कारण अब इस तारीख को और बढ़ाकर पहली जनवरी किए

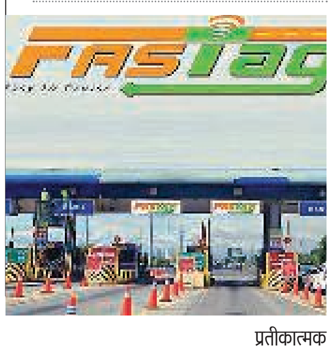

प्रतीकात्मक

जाने की संभावना है।

फास्टैग को लेकर कई तरह की समस्याएं देखने में आ रही हैं। इनमें सबसे पहली समस्या इसकी उपलब्धता और खरीद की है, जिसमें केवाईसी सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। केवाईसी की अनिवार्यता के कारण विशेषकर कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के नाम पर पंजीकृत वाहनों के फास्टैग लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवाईसी के तहत बैंक आधार नंबर, पैन नंबर समेत एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। लेकिन यदि इनमें दर्ज पता वाहन के आरसी में दर्ज पते से मेल नहीं खाता है तो फास्टैग नहीं दी जाती है। केवाईसी की अनिवार्यता खत्म होने से यह दिक्कत दूर हो जाएगी। चूंकि आगे चलकर एनएचएआइ की योजना फास्टैग को नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी लागू करने की है। इसलिए केवाईसी की बाध्यता खत्म होना जरूरी है।

दूसरी समस्या फास्टैग के एक्टिवेशन और रिचार्ज से संबंधित है। जिन लोगों ने फास्टैग ले लिए हैं, उन्हें इन्हें एक्टिवेट और रिचार्ज करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बैंकों की वेबसाइट और फास्टैग मोबाइल एप में इसके लिए पूरी व्यवस्था है, परंतु मामूली गलती से पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है।

तीसरा झंझट टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है, जहां कई लोगों के फास्टैग काम नहीं कर रहे हैं अथवा खाते से निर्धारित से ज्यादा राशि काटी जा रही है। कई जगह टोल प्लाजा में ही तकनीकी खामी पाई गई है। इन हालात को देखते हुए कुछ संगठनों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने तथा फास्टैग की तारीख को और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती चिंता की बात नहीं : मुखर्जी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में धीमी वृद्धि चिंता बात नहीं है। कई चीजें हो रही हैं, जिनका असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी की जरूरत है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुखर्जी ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्लैटिनम जुबली पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में आर्थिक संकट के दौरान बैंकों ने मजबूती दिखाई थी। उस वक्त वे वित्त मंत्री थे। तब किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने उनसे अतिरिक्त रकम के लिए अनुरोध नहीं किया था।

पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समस्याओं को हल करने के लिए लोकतंत्र में संवाद होना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आंकड़ों की प्रमाणिकता का तथ्य के रूप में बरकरार रखना भी जरूरी है। इसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी वह अखबारों में पढ़ते हैं कि डाटा पर सवाल उठाया जाता है, तो उन्हें दुख होता है। योजना आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छी बात यह है कि नीति आयोग भी उसी दिशा में काम कर रहा है।

अमेरिका में इन्फोसिस के खिलाफ एक और मुकदमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका स्थित स्काल लॉ फर्म ने कहा है कि वह भारतीय आइटी दिग्गज इन्फोसिस के खिलाफ दूसरा मुकदमा दायर करेगी। कंपनी ने पिछले वर्ष सात जुलाई और इस वर्ष 20 अक्टूबर के बीच इन्फोसिस के शेयर खरीदने वालों से कहा है कि वे 23 दिसंबर तक उससे संपर्क करें। स्काल का कहना है कि इन्फोसिस की तथाकथित अनुचित गतिविधियों से अमेरिका में उसके निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन्फोसिस ने अभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। शेयर बाजारों ने कंपनी से इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है कि खबरों के मुताबिक अमेरिका में उस पर दूसरा मुकदमा होने वाला है।

इस वर्ष अक्टूबर में इन्फोसिस ने शेयर बाजारों को बताया था कि उसे कुछ व्हिसलब्लोअर्स की तरफ से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन्फोसिस का शीर्ष प्रबंधन अनुचित कारोबारी गतिविधियों में शामिल है। अमेरिका के शेयर बाजार नियामक एसईसी ने भी इस मामले में जांच शुरू की है। वहीं, रोजेन लॉ फर्म ने कहा है कि वह अमेरिका में कंपनी के निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमे की तैयारी कर रही है।

इस मामले में व्हिसलब्लोअर्स ने अक्टूबर में आरोप लगाया था कि जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स को बही खाते की जांच को कम करने के लिए कहा गया। उनसे 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को भी नजरंदाज करने के लिए दबाव डाले जाने की बात कही गई है। आरोपों के मुताबिक अधिकारियों ने मुनाफा बढ़ाकर स्टॉक्स की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए।

पहले भी लगते रहे हैं आरोप

कंपनी पर इससे पहले भी वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। हाल में ही कंपनी द्वारा इजरायल की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी पनाया की खरीद के समय भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस दौरान भी व्हिसलब्लोअर की ओर से ही शिकायत आई थी। इसे कंपनी की इंटरनल कमेटी ने निराधार बताया था।

टेक महिंद्रा को मिली पिंपरी स्मार्ट सिटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग और बिजनेस री-इंजीनियरिंग सेवाएं व सॉल्यूशन देने वाली टेक महिंद्रा को पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से 500 करोड़ रुपये की लागत वाली स्मार्ट सिटी परियोजना मिली है। टेक महिंद्रा की इस परियोजना का लाभ शहर के 15 लाख लोगों को मिलेगा।

टेक महिंद्रा के एपीसी बिजनेस हेड सुजित बक्शी ने कहा कि इस परियोजना को एक साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। यह परियोजना हासिल कर टेक महिंद्रा ने कानपुर, गांधीनगर, नासिक और जयपुर के अपने स्मार्ट सिटी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

पिंपरी चिंचवाड़ परियोजना कंपनी को प्राप्त अब तक की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी परियोजना है। इसे प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत बजट आवंटित किया गया है। टेक महिंद्रा परियोजना में कंपनी सिटी नेटवर्क, स्मार्ट वाटर, सीवरेज, ट्रैफिक और स्मार्ट पार्किंग जैसी सेवाएं स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त टेक महिंद्रा रोयल टाइम डाटा मैनेजमेंट, अलर्ट व इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को समर्थ बनाने में भी मदद करेगी जिससे नगर प्रशासन को सहयोग मिल सकेगा।

लेखाजोखा

डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने के चलते आइटी स्टॉक्स पर दिखा दबाव, यस बैंक के शेयरों में मजबूती दिखी

बैंकिंग, मेटल स्टॉक्स ने शेयर बाजारों को संभाला

मुंबई, प्रेट्र : बुधवार के सत्र में सधी वापसी करने वाले घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को भी तेजी दिखी। बैंकिंग और मेटल शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी के दम पर गुरुवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 169.14 अंकों यानी 0.42 प्रतिशत की उछाल के साथ 40,581.71 अंक पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा तक उछला ले चुका था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी 61.65 अंक यानी 0.52 प्रतिशत संभलकर 11,971.80 अंक पर स्थिर था।

सेंसेक्स पैक में गुरुवार को सबसे ज्यादा 7.17 प्रतिशत का उछाल टाटा मोटर्स के शेयरों में दर्ज की गई। यस बैंक (5.96 प्रतिशत), वेदांता (3.68 प्रतिशत), टाटा स्टील (3.29 प्रतिशत), एसबीआइ (2.91 प्रतिशत) कोटक महिंद्रा बैंक (1.76 प्रतिशत) में निवेशकों की दिलचस्पी ने शेयर बाजारों का मूड पॉजिटिव बनाए रखा। हालांकि इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस समेत कई अन्य आइटी शेयरों में

प्रतीकात्मक

169.14 अंक सुधरकर 40,581.71 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स

61.65 अंक मजबूत होकर निफ्टी पहुंचा 11,971.80 पर

गिरावट दिखी। ओएनजीसी और भारती एयरटेल को भी गिरावट का सामना करना पड़ा। बुधवार को भारतीय प्रमुख शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। उस सत्र में सेंसेक्स 172.69 अंक, और निफ्टी 53.35 अंक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा था।

गुरुवार के कारोबार के बारे में सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर (इक्विटी इन्वेस्टमेंट) हेमंग कापसी ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने के फैसले का दुनियाभर के कई बाजारों में सकारात्मक असर दिखा। भारतीय बाजार इसका अपवाद नहीं थे और यहां भी बीएसई में मेटल, पीएसयू और बैंकिंग समेत सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने के चलते सिर्फ आइटी स्टॉक्स और उसके सेक्टोरल इंडेक्स पर दबाव देखा गया।

एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों के मामले में हांगकांग, सियोल और टोक्यो के शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की जबर्दस्त ओपनिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों को निवेशकों ने ओपनिंग के दिन हाथोंहाथ लिया। बैंक ने शेयरों का प्राइस 37 रुपये रखा था। गुरुवार को बीएसई में बैंक के शेयर 57 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 58 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। हालांकि कारोबार के आखिर में बैंक के शेयर बीएसई में 33.90 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में भी इसके शेयर 58.75 रुपये पर खुले। इस बाजार में बैंक के शेयर का बंद भाव 55.30 रुपये रहा।

तीन कंपनियों के कॉमर्शियल पेपर हुए सूचीबद्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसई में गुरुवार को नेशनल फर्टिलाइजर्स, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन और जीआइसी हाउसिंग फाइनेंस के कॉमर्शियल पेपर सूचीबद्ध हुए। पिछले महीने कॉमर्शियल पेपर्स की सूचीबद्धता को इजाजत मिलने के बाद से बीएसई में अब तक इनको मिलाकर सात ऐसे पेपर्स सूचीबद्ध हो चुके हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स के पेपर का आकार 1,600 करोड़ रुपये, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन का 900 करोड़ रुपये और जीआइसी हाउसिंग फाइनेंस का 100 करोड़ रुपये का है।

उत्पादन घटने से बढ़ा प्याज का भाव : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में प्याज की पैदावार घटने से मूल्य में भारी इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि चालू खरीफ सीजन में प्याज का उत्पादन 16 लाख टन कम हो गया है, जिससे प्याज महंगी हुई है। लेकिन प्याज की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

फसल के खराब होने के बारे में पूछे सवालों के जवाब में तोमर ने कहा कि राज्यों के मुताबिक 30 नवंबर तक 69.9 लाख टन प्याज के उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। लेकिन वास्तविक पैदावार 53.67 लाख टन ही हुई है। प्याज की पैदावार में आई कमी से यह संकट पैदा हुआ है, जिसके समाधान की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें प्याज निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध और आयात के लिए कई सारी रियायतें दी गई हैं।

तोमर ने बताया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, जिसके तहत राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कारगर कदम उठाने की सलाह दी गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हित में और बेहतर बनाकर लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। योजना में हिस्सा लेने वाले 80 फीसद दावों का भुगतान कर दिया गया है। तोमर ने खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रभावों को कम करने की दिशा में प्रयासरत है, जिसके लिए कई योजनाएं और अनुसंधान किये जा रहे हैं। तोमर ने कहा कि देश के चार करोड़ से अधिक किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के मार्फत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

2015 में 3,532 भारतीयों को हिरासत में लिया था अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (आइसीई) एजेंसी ने, जबकि 2016 में 3,913 और 2017 में 5322 भारतीयों को पकड़ा गया था। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,811 हो गया।

देश और ब्रेक्जिट का भविष्य तय करने के लिए ब्रिटेन में उमड़े वोटर

लोकतंत्र का पर्व ▶ पांच साल के भीतर ब्रिटेन में तीसरा आम चुनाव, आज आएंगे नतीजे

2016 के बाद से ही देश में बना हुआ है सियासी गतिरोध मतगणना शुरू

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में गुरुवार को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में वोटरों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों से ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव) का भविष्य तय होगा। ब्रिटेन में 2016 से ब्रेक्जिट के चलते सियासी गतिरोध बना हुआ है। इसी वजह से इस यूरोपीय देश में पांच साल के अंदर तीसरी बार आम चुनाव कराने की नौबत आई।

इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मतदान केंद्रों पर लोगों ने स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे से लेकर रात दस बजे तक मतदान किया। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो गई। चुनाव नतीजे शुक्रवार सुबह घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि सिर्फ उनकी ही पार्टी देश को ब्रेक्जिट के जाल से निकाल सकती है। जबकि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली विपक्षी लेबर पार्टी ने वादा किया है कि वह ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह कराएगी। ब्रेक्जिट के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय थी, लेकिन इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाने के बाद जॉनसन ने मध्यावधि चुनाव कराने का एलान किया था। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वह चुनाव में जीत दर्ज कर 31 जनवरी को 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन से अपने देश को अलग करने में सफल होंगे।

लंदन में गुरुवार को एक पोलिंग स्टेशन पर आम चुनाव के लिए वोट डालने के बाद अपने कुत्ते के साथ प्रस्थान करते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। रायटर

मतदान करने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन और उनकी पत्नी लॉरा अल्वारेज। एपी

650 सीटों पर 3,322 उम्मीदवार : ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए कुल 3,322 उम्मीदवार मैदान में हैं। 326 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाएगी। मतदान से पहले कराए गए जनमत सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत मिलता दिखाया गया है।

63 भारतीय आजमा रहे किस्मत : इस चुनाव में भारतीय मूल के 63 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 25 को कंजरवेटिव पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेबर पार्टी से 13, ब्रेक्जिट पार्टी से 12 और लिबरल डेमोक्रेट्स से आठ भारतवंशी चुनाव मैदान में हैं। बाकी लोग अन्य दलों के उम्मीदवार या निर्दलीय हैं।

40 सीटों पर भारतवंशियों का प्रभाव : छह करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी संख्या है। यहां करीब 15 लाख भारतवंशी रहते हैं। अनुमान है कि करीब 40 सीटों पर भारतवंशी वोटर नतीजे प्रभावित कर सकते हैं।

एफआइआर रद कराने गए आतंकी सईद की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज

लाहौर, प्रेट्र : लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद उसके 67 सहयोगियों की अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की याचिका खारिज कर दी। मामला गैरकानूनी घोषित हो चुके संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत से संबंधित है। इसमें सईद और उसके सहयोगियों ने अपने खिलाफ दर्ज 23 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) को रद करने की मांग की थी। आरोप है कि सईद और उसके सहयोगी लोगों ने दोनों संस्थाओं की संपत्ति का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया।

हाई कोर्ट की जस्टिस मुहम्मद कासिम खान अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सईद और उसके सहयोगियों की याचिका का निपटारा किया। आदेश दिया कि अब प्रत्येक एफआइआर रद करने के लिए अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिया जाए। इस दौरान सईद के वकील एके डोगर ने कहा, जमाद उद दावा और फलाह ए इंसानियत की किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल आतंकी कार्यों के लिए नहीं हुआ। अभियोजन की ओर से उनके मुवक्किल पर यह गलत आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सईद और उसके कुछ साथी नेताओं का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का दावा तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत है। सईद और उसके साथी किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में कभी भी शामिल नहीं रहे।

आतंकियों को धन मुहैया कराने पर आज होगी सुनवाई : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों की गुरुवार को वकीलों की हड़ताल के चलते आतंकवाद निरोधी अदालत में पेशी नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।

सईद और उसके सहयोगियों की आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में पेशी होनी थी। इस मामले में अदालत ने बुधवार को सईद और उसके सहयोगियों-हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल पर आरोप तय कर दिए थे। अब मामले में गवाह और सुबूत पेश होंगे। लाहौर की अदालत के वकील अपने साथी के साथ अस्पताल में हुई घटना के विरोध में हड़ताल पर थे।

▶ गैर सरकारी संस्थाओं का आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप

मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद। फाइल फोटो (प्रेट्र)

अमेरिका ने पाकिस्तान को किया आगाह, सईद मामले में न्याय होता दिखे

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मामले की अदालत में तथ्यपरक और त्वरित गति से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय मुंबई हमला मामले में न्याय होते देखना चाहता है। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में कई विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। मारे गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी थे। अमेरिका की यह प्रतिक्रिया लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत के उस फैसले के कुछ घंटे बाद आई जिसमें सईद और उसके तीन खास सहयोगियों पर आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। दक्षिण-मध्य एशिया मामलों की सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने ट्वीट कर हाफिज सईद और उसके सहयोगियों पर आरोप तय होने का स्वागत किया।

न्यूज गैलरी

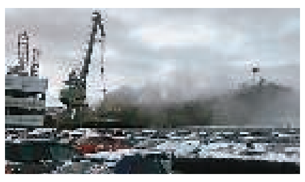
रूस का विमानवाहक युद्धपोत एडमिरल कुजनेत्सोव। एपी

रूस के इकलौते विमानवाहक पोत में लगी आग

मॉस्को : रूस के इकलौते विमानवाहक युद्धपोत एडमिरल कुजनेत्सोव पर गुरुवार को आग लग गई। आर्कटिक शिपयार्ड में पोत की मरम्मत के दौरान यह आग लगी। घटना के वक्त युद्धपोत पर चार सौ लोग थे। इस घटना के बाद से तीन कामगारों के लापता होने की खबर है। एडमिरल कुजनेत्सोव की मरम्मत का काम अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। (एएफपी)

अमेरिका में इस साल दी गई 22वीं सजा-ए-मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बुधवार को हत्या के एक दोषी को मौत की नींद सुला दिया गया। इस साल अमेरिका में मौत की सजा पर अमल का यह 22वां मामला है। वर्ष 1999 में अमेरिका में सबसे ज्यादा 86 मुजरिमों को मौत की सजा दी गई थी। टेक्सास में 46 साल के जिस व्यक्ति को मौत की सजा दी गई उसने जेल में रहते एक जेलकर्मी की हत्या कर दी थी। (एएफपी)

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की जमानत नामंजूर

ढाका : भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद के नेतृत्व वाली छह जजों की पीठ ने गुरुवार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही यह आदेश भी दिया कि 74 वर्षीय जिया के इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। (प्रेट्र)

फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका में दाखिल हो रहा भारतीय धरा गया

वाशिंगटन : फर्जी पासपोर्ट के जरिये अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश में 20 साल के एक भारतीय को वाशिंगटन एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। उसने स्लोवेनिया का जाली पासपोर्ट बनवा रखा था। अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने के प्रयास में रोजाना 14 लोग जाली दस्तावेजों के साथ पकड़े जाते हैं। (प्रेट्र)

इजरायल में साल भर के भीतर होगा तीसरा संसदीय चुनाव

यरुशलम, रायटर : इजरायल में एक साल के अंदर तीसरी बार संसदीय चुनाव कराने का एलान कर दिया गया है। यह चुनाव अगले साल दो मार्च को कराया जाएगा। गत सितंबर में हुए संसदीय चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिर विपक्षी नेता बेनी गेंट्स को सरकार बनाने का मौका दिया था। लेकिन दोनों नेता बुधवार की समयसीमा तक गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहे।

इजरायली संसद को भंग करने के लिए गुरुवार को लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 94 सांसदों ने मतदान किया। विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। इजरायल में एक साल के अंदर तीसरी बार संसदीय चुनाव नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साये में होंगे। उन्होंने हालांकि कुछ भी गलत करने से इन्कार किया है। उनका कहना है कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि आलोचकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। 70 वर्षीय नेतन्याहू नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

नहीं मिला था किसी को बहुमत : इजरायल में गत 17 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 और गेंट्स की ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी को 33 सीटें मिली थीं। बाकी सीटों पर छोटी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले गत अप्रैल में हुए चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिला था।

राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन (दाएं) के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल/रायटर

▶ चुनाव कराने के लिए भंग की गई संसद अगले साल दो मार्च को होगा मतदान

▶ पिछले संसदीय चुनाव में किसी दल को नहीं मिला था बहुमत

▶ गठबंधन सरकार बनाने की समय सीमा भी हुई खत्म

बगदाद के तहरीर स्क्वायर में दिखा प्रदर्शनकारियों का 'लघु इराक'

बगदाद, एएफपी : शासन व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव की मांग को लेकर यूं तो लगभग पूरा इराक ही गत अक्टूबर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों की चपेट में है। राजधानी बगदाद भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन यहां के मशहूर तहरीर स्क्वायर में जमा प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन स्थल को कुछ इस तरह बसा दिया है, जिसमें लघु इराक की झलक देखने को मिल रही है।

प्रदर्शन स्थल बने तहरीर स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों के रूप में सुरक्षा गार्ड से लेकर सफाई कर्मी तक तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं। बेबीलोन प्रांत से यहां सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैदर चाकर ने बताया, 'सरकार ने जितना काम 16 साल में किया, उतना काम हमने यहां महज दो महीनों कर दिखाया।' तहरीर स्क्वायर में तमाम नागरिक सुविधाएं टेंटों में मुहैया कराई गई है। यहां भोजन से लेकर पेंटिंग बनाने तक हर व्यक्ति की भूमिका तय की गई है। वे पालियों में अपने काम का अंजाम दे रहे हैं। जबकि इस स्थल की सुरक्षा के लिए प्रवेश द्वारों पर अवरोध लगाए गए हैं। इन जगहों पर दर्जनों महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी तैनात हैं। वे यहां आने वाले सभी आंगतुकों की तलाशी के बाद प्रवेश देते हैं। प्रदर्शनकारियों का यह लघु इराक हालांकि गत शुक्रवार को हमलावरों का निशाना बन गया था। कुछ बंदूकधारियों ने घुसकर तहरीर स्क्वायर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इसमें करीब 25 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और 130 घायल हुए थे।

दो माह से हो रहा विरोध प्रदर्शन : सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बगदाद में गत एक अक्टूबर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुका है। दो माह से जारी विरोध प्रदर्शनों ने कई बार हिंसक रूप भी लिया। सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में करीब 450 लोग मारे गए और करीब 20 हजार घायल हुए। प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बावजूद विरोध प्रदर्शन थमा नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी भ्रष्ट नेताओं के हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

▶ अस्पताल से लेकर सुरक्षा तक सभी नागरिक सुविधाएं करा रहे मुहैया

▶ सरकार से व्यवस्था बदलाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी

इराक के मशहूर तहरीर स्क्वायर में प्रदर्शन करते लोग। एपी

ईरानी विमानन कंपनी और उद्योग पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका ने ईरान की महान विमानन कंपनी और जहाजरानी उद्योग पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए बुधवार को यहां अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीव मुचिन ने कहा, आतंकी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति के लिए ईरान अपने विमानन और जहाजरानी उद्योग का उपयोग करता है। ऐसा कर वह सीरिया और यमन में विनाशकारी मानवीय संकट में सीधे योगदान दे रहा है। विमानन और जहाजरानी उद्योग को सतर्क रहना चाहिए और आतंकी गतिविधियों की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

स्टीव मुचिन। फाइल

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने बताया कि महान एयर के तीन कर्मचारी इस काम में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों की घोषणा ईरान और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला-बदली के कुछ ही दिनों बाद तब की गई जब ईरान समर्थित तीन आतंकी इराकी नेताओं और बेकसूर लोगों की हत्या कर इराक में हालात बिगाड़ने की योजना बना रहे थे।

अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकी हमले में 71 सैनिकों की मौत

नियामी, आइएएनएस : अफ्रीकी देश नाइजर में एक बड़े आतंकी हमले में 71 सैनिकों की मौत हो गई। नाइजर के रक्षा मंत्री ने गुरुवार को यहां बताया कि माली से सटे सीमावर्ती इलाके में स्थित एक सैन्य अड्डे पर मंगलवार को सैकड़ों आतंकियों ने हमला बोला था। सेना की जवाबी कार्रवाई में 57 हमलावर भी मारे गए। इस हमले की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इसके पीछे इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े स्थानीय आतंकी समूह या नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ माना जा रहा है।

नाइजर में पिछले कुछ हफ्तों में आइएस आतंकियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। यह आतंकी हमला ऐसे वक्त पर किया गया जब नाइजर की सरकार ने देश में पिछले दो वर्षों से जारी आपातकाल की अवधि को तीन महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

हॉलीवुड निर्माता वीनस्टीन 176 करोड़ का हर्जाना देने को राजी

न्यूयॉर्क, एएफपी : दर्जनों अभिनेत्रियों का यौन शोषण करने वाले चर्चित अमेरिकी फिल्म निर्माता हार्वे वीनस्टीन ने 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 176 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने पर सहमति जताई है। हर्जाने की यह राशि यौन शोषण की शिकार अभिनेत्रियों और उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाली पूर्व कर्मचारियों के बीच बांटी जाएगी।

वर्ष 2017 में वीनस्टीन के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से ही 'मी टू' अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दुनियाभर की महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण के मामले को उजागर करने का साहस दिखाया था। वीनस्टीन पर आरोप लगाने वालों में एंजेलिना जोली, ग्विनेथ पाल्ट्रो और सलमा हयाक जैसी चर्चित अभिनेत्रियां भी शामिल थीं। हालांकि वीनस्टीन के खिलाफ मुकदमा करने वालों में ये तीनों शामिल नहीं हैं।

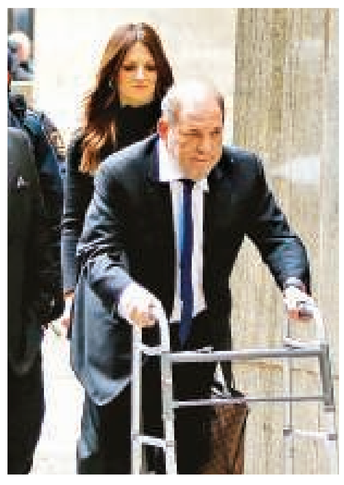
अमेरिकी फिल्म निर्माता हार्वे वीनस्टीन (वॉकर का सहारा लिए) न्यूयॉर्क स्थित अदालत में सुनवाई के लिए पेश हुए। रायटर

प्रचार टीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को थानोस के रूप में दिखाया

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम ने उन्हें चर्चित हॉलीवुड फिल्म सीरीज अवेंजर्स के खलनायक थानोस के रूप में दिखाया है। ट्रंपवाररूम के ट्विटर हैंडल से जारी एक छोटे से वीडियो में ट्रंप के चेहरे वाले थानोस को दिखाया गया है। इसमें थानोस के चुटकी बजाते ही विपक्षी नेता गायब हो जाते हैं।

वीडियो के परिचय में लिखा गया है कि विपक्षी नेताओं के हमले के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को कोई हरा नहीं सकता। अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से फिर ताल ठोक रहे ट्रंप के खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम सुर्खियां बटोरने के लिए तरह-तरह के तरीके अख्तियार कर रही है। ट्रंप को हालांकि खलनायक थानोस के रूप में दिखाने पर खूब आलोचना भी हुई है।

चिली के लापता विमान का मलबा ड्रेक पैसेज में मिला

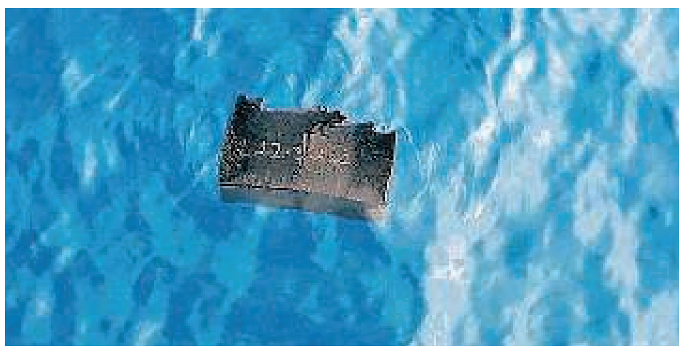
समुद्र में तैरता चिली के लापता विमान का मलबा। एएफपी

सेंटियागो, आइएएनएस: तीन दिन पहले अंटार्कटिका की उड़ान के दौरान लापता हुए चिली की वायुसेना के सी-130 हरक्यूलिस विमान का कुछ मलबा समुद्र में मिला है। इस विमान में 38 लोग सवार थे। चिली की वायुसेना ने बुधवार को यहां बताया कि मछली पकड़ने वाले एक जहाज के चालक दल को ड्रेक पैसेज में चिली के झंडे, मानव अवशेष और कुछ चीजें मिली हैं। ड्रेक पैसेज अंटार्कटिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। इसी जगह पर उड़ान के दौरान विमान का रेडियो संपर्क टूट गया था।

छाए रहे भारतीय

पूरे साल नेट पर अभिनंदन को खोजते रहे पाकिस्तानी

गूगल ने वर्ष 2019 के दौरान पड़ोसी देश में इंटरनेट पर चर्चित रही हस्तियों व अन्य की सूची जारी की

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पराक्रम पाकिस्तानियों के दिलोदिमाग पर पूरे साल छाया रहा। वह पड़ोसी देश में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी गई शीर्ष दस हस्तियों व अन्य में शामिल रहे।

सोशल मीडिया में वायरल हुई विंग कमांडर वर्धमान की दिलेरी : इस साल 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की रात में पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों पर एयरस्ट्राइक की। अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने उन्हें खदेड़ते हुए पाकिस्तानी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया।

हालांकि, इस दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वह गुलाम कश्मीर में चले गए थे। पकड़े जाने पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के सवालों का निर्भीकता व दिलेरी के साथ जवाब दिया। उनके जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय दखल के बाद पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को 48 घंटे के भीतर वापस भेजना पड़ा। वह गूगल ट्रेंड की सूची में नौवें स्थान पर रहे।

अभिनंदन वर्धमान।

सारा अली खान।

अदनान सामी। सभी फाइल

बिग बॉस सीजन-13 व सारा अली खान के प्रति रही दिलचस्पी : विंग कमांडर अभिनंदन के अलावा पाकिस्तानियों की दिलचस्पी अभिनेत्री सारा अली खान और भारतीय टीवी रियलिटी सीरीज बिग बॉस सीजन-13 में भी रही। गूगल की तरफ से जारी सूची के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान पाकिस्तान में सर्च के मामले में बिग बॉस सीजन-13 दूसरे स्थान पर रहा। टीवी शो मोटू-पतलू गूगल ट्रेंड में आठवें स्थान पर रहा। सूची को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की तुलना के आधार पर कंपाइल किया गया है। लोकप्रिय सर्च के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की बेटी व अभिनेत्री सारा अली खान छठे स्थान पर रहीं। केदारनाथ व सिंबा जैसी फिल्में कर चुकीं सारा आनेवाले दिनों में कॉमेडी फिल्म कुली नंबर-1 के रीमेक में अभिनेता वरुण धवन के साथ दिखाई देंगी।

अदनान सामी, फिल्म कबीर खान व गली ब्वॉय भी ट्रेंड में : भारत की नागरिकता पा चुके पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में शामिल रहे। पाकिस्तान का एक वर्ग सामी पर जासूस होने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तानियों ने बॉलीवुड फिल्म कबीर सिंह व गली ब्वॉय के बारे में भी इंटरनेट पर खूब सर्च किया। दोनों फिल्में गूगल ट्रेंड की सूची में क्रमशः पांचवें और दसवें स्थान पर रहीं।

हांगकांग में लोगों ने बिछुड़े साथियों को किया याद

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में गुरुवार को हजारों लोगों ने सेंट्रल पार्क में एकत्रित होकर अपने आंदोलन के हिंसक स्वरूप में तब्दील होने के छह महीने पूर्व के दिन को याद किया। शांत लोगों ने 12 जून का वह दिन याद किया जब सड़क जाम करने के दौरान पहली बार उनका पुलिस से टकराव हुआ था और उन पर रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले चले थे। आंदोलन चीन समर्थित हांगकांग सरकार के चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को लेकर शुरू हुआ था। कुछ हफ्ते बाद आंदोलन लोकतंत्र की मांग में तब्दील हुआ और अब चीन से आजादी का नारा बुलंद हो रहा है। गुरुवार को उन आंदोलनकारियों को भी याद किया गया, जो इन छह महीनों में बिछड़ गए। हजारों लोगों ने मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते।

जनसमूह को संबोधित करते हुए 24 वर्षीय इंजीनियर मार्क चो ने कहा, सरकार के प्रत्यर्पण प्रस्ताव के विरोध में दस लाख लोगों ने नौ जून को शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। सरकार से अपील की थी कि वह हांगकांग के लोकतांत्रिक आचार-विचार को कुचलने के लिए यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश न करे। लेकिन सरकार ने दस लाख शांत लोगों की अपील नहीं सुनी। प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। इस अनुभव ने हमें सबक दिया कि शांतिपूर्ण आंदोलन से काम नहीं चलेगा। 23 साल की शिक्षिका मैंडी चान ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को याद करते हुए कहा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। कार्यक्रम में छह हजार से ज्यादा गिरफ्तार आंदोलनकारियों को क्रिसमस कार्ड भेजने की मुहिम का भी एलान किया गया। यह सिलसिला गुरुवार से ही शुरू हो गया। आंदोलन के छह महीनों में पुलिस ने विभिन्न मामलों में छह हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।

▶ सरकार से टकराव के छह महीने के अनुभव किए साझा

ये भी जानिए

भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में अब तक 12 वनडे मुकाबले खेले हैं। भारतीय टीम ने यहां सात में जीत दर्ज की है, जबकि चार में हार मिली है।

नई परीक्षा के लिए तैयार टीम इंडिया

वनडे सीरीज के लिए चेन्नई पहुंची कोहली एंड कंपनी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे रविवार को

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम नई परीक्षा के लिए चेन्नई पहुंच गई है। कोहली एंड कंपनी को अब वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मुकाबल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। सीरीज के अगले दो मैच 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम और 22 दिसंबर को कटक में खेले जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की है, जिसमें उनके साथ कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा भी नजर आ रहे हैं। कोहली ने लिखा, 'चेन्नई पहुंच गए।'

टी-20 सीरीज में जीत से भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा होगा। इसके अलावा भारतीय टीम ने जो अपनी पिछली वनडे सीरीज खेली थी वह इसी साल अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी की सरजमीं पर खेली थी। तीन मैचों की उस सीरीज को भारत ने 2-0 से अपने नाम किया था। हालांकि, टीम इंडिया को अपनी पिछली घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया घर में एक बार फिर जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से उतरेगी।

जहां तक भारतीय टीम की बात है तो वनडे टीम में मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केदार जाधव शामिल रहेंगे, जो टी-20 टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं, टी-20 टीम में शामिल रहे संजू सैमसन, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं। वहीं, वेस्टइंडीज टीम की अगुवाई कीरोन पोलार्ड ही संभालेंगे, जो टी-20 टीम के भी कप्तान थे। वेस्टइंडीज ने भारत में अपनी पिछली सीरीज पिछले ही महीने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी जिसमें उसे 3-0 से जीत मिली थी। लेकिन, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने और भारत के खिलाफ उसके घर में खेलने में बहुत अंतर होता है, यह बात कैरेबियाई टीम बेहद अच्छे से जानती है। वेस्टइंडीज की वनडे टीम में सुनील अंब्रीश, शाई होप, रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड शामिल रहेंगे, जो टी-20 टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं टी-20 टीम का हिस्सा रहे फेबियन एलन, दिनेश रामदीन, शेरफेन रदरफोर्ड, लेंडिल सिमंस, केसरिक विलियम्स वनडे टीम में नहीं है। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ उनके घर पर 2002 के बाद से वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है। 2002 में भारत को सात वनडे मैचों की सीरीज में 4-3 से हराने के बाद विंडीज की टीम यहां पांच सीरीज हारी है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले वनडे के लिए चेन्नई पहुंचने के बाद कप्तान कोहली ने रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की ● ट्विटर

रणनीति पर अमल नहीं कर सके : कीरोन पोलार्ड

मुंबई, प्रेट्र: भारत के हाथों टी-20 सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने कहा कि उनकी टीम पूरी सीरीज में रणनीति पर अमल नहीं कर सकी। पोलार्ड ने मैच के बाद कहा, 'उनकी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन हमने कुछ विकेट लेकर वापसी की। उस समय हम हालांकि अपनी रणनीति पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सके। पूरी सीरीज में कमोबेश यही कहानी रही। हमने पहले भी बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने 230 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इस मैदान पर हमने 2016 में 220 रन बनाए थे।

मैंने अपनी बल्लेबाजी से खुश होना सीख लिया है : केएल राहुल

मुंबई, प्रेट्र: केएल राहुल ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की नहीं होने पर चैन से रहना मुश्किल है, लेकिन कहा कि उन्होंने टीम में जगह की परवाह किए बिना अपनी बल्लेबाजी से खुश होना सीख लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 91 रन बनाने वाले राहुल को शिखर धवन के चोटिल होने के कारण टीम में चुना गया। राहुल ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि दबाव नहीं था। टीम से अंदर-बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विरोधी टीम के दबाव को झेलने की आदत डालने में समय लगता है। ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसके खिलाफ आप आसानी से रन बना सकें। आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। मेरे सिर्फ यही कर सकता हूं कि मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकूं।

आखिरकार पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर बना सके : कोहली

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यहां तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज पर सीरीज जीत का सबसे अच्छा पहलू यह है कि उनकी टीम आखिरकार पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। हालांकि, भारतीय टीम ने कुछ समय से लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह अगले साल टी-20 विश्व कप से पूर्व पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर बनाने के प्रयास कर रही है। कोहली ने आगे बढ़कर टीम की अगुआई की और 29 गेंदों पर 70 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसके चलते भारत ने यहां बुधवार को वेस्टइंडीज को तीसरे व अंतिम टी-20 में 67 रन से शिकस्त दी। इस दौरान कोहली ने सात छक्के भी जड़े। कोहली ने मैच के बाद कहा, 'मैंने पहले बल्लेबाजी करने और मैच जीतने के बारे में काफी बात की थी। उसे सिर्फ मैदान पर जाकर अंजाम देना था। ऐसा हुआ भी। मेरे पास कुछ अलग करने का मौका था, जो आमतौर पर मैं नहीं करता हूं। मैंने केएल से कहा कि अंत तक टिके रहना और मैं कोशिश करूंगा एवं मैंने कुछ शॉट खेले।' कोहली अपनी बल्लेबाजी के कुछ अलग पहलू दिखाना चाहते थे और इसके लिए वह अपनी शादी की दूसरी सालगिरह से बेहतर दिन नहीं चुन सकते थे। उन्होंने कहा कि यह सीरीज जीत उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए 'खास तोहफा' है। उन्होंने कहा, 'यह पारी कुछ खास थी और हमारी शादी की दूसरी सालगिरह भी थी, यह खास तोहफा था। यह रात खास थी और मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली।' कप्तान की विनम्रता से कोई भी प्रभावित हो सकता था जब कोहली ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह सभी प्रारूपों में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं जानता हूं कि मैं सभी प्रारूपों में योगदान दे सकता हूं। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। मेरी भूमिका अहम होती है, क्योंकि मुझे दो भूमिकाएं निभानी होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने को इसी तरह खेलने के काबिल बना सकूं।' कोहली ने केएल राहुल और रोहित शर्मा की भी तारीफ की। राहुल ने 56 गेंदों पर 91 रन बनाए, जबकि रोहित ने 34 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली।

> किसी ने भी सोचा होगा कि भारत यह सीरीज हारेगा। जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काबिल-ए-तारीफ यह है कि भारत ने जिस तरह से निर्भीक होकर बल्लेबाजी की। कोई टीम में अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा था, सभी जीत के इरादे से खेल रहे थे। शाबास भारत।
>
> **सौरव गांगुली**, बीसीसीआइ अध्यक्ष

लाबुशाने का शतक, ऑस्ट्रेलिया मजबूत

डे-नाइट टेस्ट

मेजबानों ने पहले दिन बनाए चार विकेट पर 248 रन, मात्र 43 रन ही बना सके दिग्गज बल्लेबाज स्मिथ

पर्थ, एएफपी: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने के लगातार तीसरे टेस्ट शतक ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन गुरुवार को यहां हावी नहीं होने दिया। पर्थ में पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में कुछ चुनौतीपूर्ण कीवी गेंदबाजों का सामना करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 248 रन बनाए हैं। लगभग 40 डिग्री तापमान में पसीना बहाने के बाद कीवी गेंदबाजों ने बाद में स्टीव स्मिथ (43) और मैथ्यू वेड (12) को आउट करके अपनी टीम की वापसी कराई। लाबुशाने हालांकि डटे रहे। उन्होंने अभी 110 रन बनाए हैं। उनके साथ ट्रेविस हेड 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। गर्मी अधिक होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहा, लेकिन लाबुशाने पर इसका असर नहीं पड़ा।

इस साल टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले इस 25 वर्षीय बल्लेबाज ने इस सबसे लंबे प्रारूप में 1000 रन भी पूरे किए। एशेज के दौरान स्मिथ के चोटिल होने के कारण टीम में जगह बनाने वाले लाबुशाने ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में शतक लगाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने स्पिनर मिशेल सेंटनर पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। इसके विपरीत स्टार बल्लेबाज स्मिथ जूझते हुए नजर आए और उन्होंने अपने 43 रन के लिए 164 गेंदें खेली। नील वैगनर (दो विकेट) ने उन्हें पवेलियन भेजा। वैगनर ने इससे पहले डेविड वार्नर (43) का अपनी ही गेंद पर खूबसूरत कैच लिया था। जो बर्न्स (09) आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे।

दार के नाम सबसे अधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड: पाकिस्तान के अलीम दार सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए हैं। दार ने गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। 51 वर्षीय दार ने वेस्टइंडीज के स्टीव बकनर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 128 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की थी। पाकिस्तान में कई वर्षो तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद अंपायरिंग में आए दार का बतौर अंपायर यह 129वां टेस्ट मैच है। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच ढाका में खेले गए मैच में पहली बार टेस्ट में अंपायरिंग की थी। बकनर ने 1989 से 2009 तक 128 टेस्ट मैचों और 181 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी।

दार ने कहा कि अपने दो दशक के करियर में मैं भाग्यशाली रहा कि ब्रायन लारा की 400 रनों की नाबाद पारी और दक्षिण अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 434 के स्कोर वाला वनडे मैच देख सका। दार अब तक 207 वनडे मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं और अब वह दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्टजन से मात्र दो मैच ही दूर हैं। कर्टजन ने अब तक 209 वनडे मैचों में अंपायरिंग की है।

स्कोर बोर्ड

टॉस : ऑस्ट्रेलिया (बल्लेबाजी)

ऑस्ट्रेलिया 284/4 (90 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
डेविड वार्नर का. एवं बो. वैगनर	43	74	04	00
जो बर्न्स एलबीडब्ल्यू बो. ग्रैंडहोम	09	42	01	00
मार्नस लाबुशाने नाबाद	110	202	14	01
स्टीव स्मिथ का. साउथी बो. वैगनर	43	164	04	00
मैथ्यू वेड बो. साउथी	12	26	01	00
टिम हेड नाबाद	20	34	04	00

अतिरिक्त : (बा-2, नोबॉ-2, वा-7) 11, **कुल :** 90 ओवर में चार विकेट पर 284 रन, **विकेट पतन :** 1-40 (बर्न्स, 12.6), 2-75 (वार्नर, 25.4), 3-207 (स्मिथ, 74.3), 4-225 (वेड, 82.1),

गेंदबाजी :
टिम साउथी 20-4-53-1
लॉकी फर्ग्यूसन 11-1-47-0
नील वैगनर 22-4-52-2
डि ग्रैंडहोम 16-6-24-1
मिशेल सेंटनर 20-3-65-0
जीत रावल 1-0-5-0

डे-नाइट टेस्ट के दौरान शॉट खेलते ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने ● एएफपी

देश में खेल प्रशिक्षकों की भारी कमी पर संसद में जताई गई गंभीर चिंता

मुश्किल
- संसदीय समिति ने 'खेलो इंडिया' पर राज्यसभा में पेश की रिपोर्ट
- घरेलू खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय निजी प्रशिक्षकों को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में खेल प्रशिक्षकों की भारी कमी पर संसदीय स्थायी समिति ने गंभीर चिंता जताई है। खिलाड़ियों को शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए समिति ने आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की सिफारिश की है, जिससे ज्यादातर खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं। हाल के वर्षों में अपने खेलों में सफलता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के पीछे उनकी व्यक्तिगत पहल और निजी प्रशिक्षक रहे हैं।

राज्यसभा में गुरुवार को मानव संसाधन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने 'खेलो इंडिया' योजना पर अपनी रिपोर्ट पेश की। सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यों की समिति ने विस्तार से खेलों में किये जा रहे प्रयासों को नाकाफी बताया है। समिति ने वैश्विक स्तर पर घरेलू खिलाड़ियों की धमक बनाने के उपाय भी सुझाए हैं। जटिया की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया कि देश में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं बहुत संतोषजनक नहीं हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र को को खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की समिति ने सिफारिश की है। समिति का कहना है कि खेल संस्कृति और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र काफी मुफीद साबित हो सकता है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाना होगा। खेल क्षेत्र में क्वालिटी को बढ़ाने, बेहतर प्रशिक्षण और हुनरमंद खिलाड़ियों की तलाश के लिए निजी खेल अकादमी को दायित्व सौंपना होगा। संसद की स्थायी समिति ने खेल मंत्रालय को ओडिशा के खेल मॉडल को अन्य राज्यों में अपनाने का सुझाव दिया है। ओडिशा की राज्य सरकार ने कारपोरेट सेक्टर से हाथ मिलाकर 10 उच्च स्तरीय बैंडमिंटन व शूटिंग सेंटर स्थापित किया है, जिसके उत्कृष्ट नतीजे मिलने लगे हैं।

देश में खेल प्रशिक्षकों की भारी कमी पर चिंता जताते हुए समिति ने बताया कि फिलहाल मंजूर 1524 पदों में से 544 प्रशिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इन 36 फीसद पदों को भरने की जल्दी नहीं दिख रही है, जो गंभीर विषय है। समिति ने इन पदों को तत्काल भरने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने खेल के क्षेत्र के होनहार खिलाड़ियों की बेसिक शिक्षा पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खेलों में कड़ी मेहनत और व्यस्तता के चलते उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे बचने के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के साथ आवासीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की गई है। चुने गए तमाम खिलाड़ी कई बार शिक्षण की व्यवस्था न होने की वजह से खेल को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वर्ष 2018-19 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों ने कई खेलों में बेहतरीन व उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। समिति ने पाया कि इसका श्रेय सरकारी खेल नीति और सरकारी खेल प्रशिक्षकों के बजाय निजी प्रयास और निजी प्रशिक्षक रहे। समिति ने खेलो इंडिया जैसी योजना की सफलता के लिए अच्छे प्रशासक अथवा खिलाड़ी की नियुक्ति की सिफारिश की है, जो खेल और खिलाड़ियों की जरूरत को समझे और सुलझा सके।

राहुल, कोहली टी-20 रैंकिंग में ऊपर चढ़े

मुंबई, आइएएनएस: भारत के कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को गुरुवार को जारी ताजा आइसीसी टी-20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। इन दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की सीरीज के आखिरी टी-20 मैच में दमदार पारियां खेली थीं जिनके दम पर भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

ताजा रैंकिंग में राहुल तीन स्थान की छलांग लगाकर छठे स्थान पर आ गए हैं, जबकि कोहली पांच स्थान आगे बढ़ते हुए शीर्ष-10 में शमिल हो गए हैं। राहुल ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी-20 मैच में 56 गेंदों पर 91 रन बनाए थे। इसी पारी के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस सीरीज के तीन मैचों में राहुल ने कुल 164 रन बनाए। कोहली ने कुल 183 रन बनाए और टीम को 2-1 से सीरीज जिताने में मदद की। इसी कारण वह मैन ऑफ द सीरीज चुने गए।

रोहित पहले दो मैचों में नाकाम रहे थे, लेकिन अंतिम मैच में उन्होंने भी दमदार पारी खेलकर 71 रन बनाए। फिर भी वह एक स्थान नीचे खिसककर नौवें स्थान पर आ गए हैं। रोहित और कोहली इस समय टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दोनों के नाम 2633 रन दर्ज हैं।

गुवाहाटी में कर्फ्यू से खेल में खलल

नई दिल्ली, प्रेट्र: नागरिकता (संशोधन) विधेयक के कारण उपजी हिंसा के चलते गुवाहाटी में खेल भी प्रभावित हो रहे हैं। यहां कर्फ्यू के चलते इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के मुकाबले गुरुवार को स्थगित करने पड़े। हालांकि, असम और सर्विसेज के बीच रणजी मैच को बाद में ड्रॉ घोषित कर दिया गया। असम को तीन अंक और सर्विसेज को एक अंक दिया गया।

बीसीसीआइ के क्रिकेट मामलों के महाप्रबंधक सबा करीम ने कहा, 'असम और सर्विसेस के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला चौथे दिन नहीं खेला जा सका। हमें राज्य संगठन ने मैच नहीं कराने की सलाह दी थी। खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को होटल में ही रहने को कहा गया। इस समय हमारे लिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।' इस बीच अगरतला में भी विरोध के बावजूद मेजबान त्रिपुरा और झारखंड के बीच मैच आगे खेलने का फैसला किया गया। यह मुकाबला झारखंड ने 54 रन से जीता। इस जीत से झारखंड को छह अंक मिले।

शहर के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में आइएसएल के तहत नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी और चेन्नईयन एफसी का मुकाबला भी होना था, जो स्थगित करना पड़ा। आइएसएल द्वारा गुरुवार को कहा गया, 'गुवाहाटी में कर्फ्यू के चलते अगले आदेश तक के लिए नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी और चेन्नईयन एफसी का मैच स्थगित किया जाता है। हम संबंधित अधिकारियों से पिछले 48 घंटे से संपर्क में हैं। खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ प्रशंसकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला लिया है।'

दोनों टीमों ने बुधवार को अभ्यास भी नहीं किया था और मैच से पहले होने वाली प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। मालूम हो कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध का केंद्र गुवाहाटी ही है। यहां बुधवार रात से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है।

हरियाणा की विशाल जीत

रोहतक: हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-सी के मैच में महाराष्ट्र को पारी और 68 रनों से करारी शिकस्त दी। हरियाणा ने पहली पारी में 401 रन बनाए थे, जिसके जवाब में महाराष्ट्र की पहली पारी 247 रनों पर सिमटी थी। फॉलोऑन खेलते हुए महाराष्ट्र की टीम दूसरी पारी में 29 ओवर में 86 रनों के शर्मनाक स्कोर पर सिमट गई। कप्तान नौशाद शेख (27) शीर्ष स्कोरर रहे। हर्षल पटेल ने पांच विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने पहली पारी में भी चार विकेट लिए थे।

बाधा
- असम-सर्विसेस रणजी मैच के चौथे दिन का खेल स्थगित, मैच ड्रॉ
- नॉर्थईस्ट युनाइटेड व चेन्नईयन एफसी का मैच भी स्थगित

उप्र व रेलवे मुकाबला ड्रॉ

मेरठ: उत्तर प्रदेश और रेलवे के बीच मैच ड्रॉ रहा। पहली पारी की बढ़त से रेलवे को तीन अंक मिले, जबकि उत्तर प्रदेश को एक अंक से संतोष करना पड़ा। रेलवे ने पहली पारी में 253 रन बनाए थे जिसके जबाव में उत्तर प्रदेश की पहली पारी 175 रनों पर सिमटी थी। रेलवे ने दूसरी पारी में 270 रन बनाते हुए उत्तर प्रदेश को 349 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन उत्तर प्रदेश ने 21 ओवर में दो विकेट पर 62 रन बनाए। रेलवे के दिनेश मोर मैन ऑफ द मैच चुने गए।

बीसीसीआइ सीएफओ के बाद एनसीए सीओओ का इस्तीफा

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वित्त प्रमुख संतोष रांगनेकर के बाद अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के मुख्य परिचालन अधिकारी तूफान घोष ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआइ का नया सीओओ होगा या एनसीए का पुराना उपसमिति वाला ढांचा फिर शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के दौर में वह व्यवस्था बंद कर दी गई थी।

घोष ने अपना इस्तीफा सीईओ राहुल जोहरी को भेज दिया है। बोर्ड के एक आला अधिकारी ने कहा कि घोष ने इस्तीफा दे दिया है और राहुल को ईमेल कर दिया है। उन्होंने निजी कारणों से पद छोड़ा है। उन पर कोई दबाव नहीं था और यह व्यक्तिगत फैसला है। क्रिकेट प्रशासन को लेकर उनकी जानकारी का अभाव इसका अहम कारण माना जा रहा है। इसके अलावा 'अनुभव' हासिल करने के लिए उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी सवाल उठे थे। यह माना भी जा रहा था कि अक्टूबर में बीसीसीआइ के नए पदाधिकारी बनने के बाद घोष को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है।

यूएफा चैंपियंस लीग बायर्न म्यूनिख ने टॉटनहम को 3-1 से दी शिकस्त, जुवेंटस, रीयल मैड्रिड, पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी की टीमें भी जीतीं

एटलेटिको मैड्रिड और अटलांटा प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

पेरिस, एएफपी: एटलेटिको मैड्रिड ने अपने ग्रुप-डी के मुकाबले में लोकोमोटिव मास्को को 2-0 से हराकर यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में जगह बनाई, जबकि ग्रुप-सी से शाख्तर डोनेट्स्क पर 0-3 की जीत के साथ अटलांटा ने भी अपनी जगह इस स्थान के लिए पक्की की।

वहीं, बायर्न म्यूनिख ने ग्रुप-बी में अपने विजयी अभियान को जारी रखते हुए मैनेजर जोस मौरिन्हो की टीम टॉटनहम को 3-1 से शिकस्त दी। म्यूनिख ने अपने ग्रुप के सभी छह मैच जीते हैं। इसके अलावा रीयल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) और जुवेंटस ने अपने ग्रुप स्तर का अभियान जीत के साथ समाप्त किया। मैनेजर डिएगो सिमोन की टीम एटलेटिको के लिए पहला गोल दूसरे मिनट में ही आ जाता, लेकिन किरेन ट्रिपयर पेनाल्टी का फायदा नहीं उठा पाए और लोकोमोटिव के गोलकीपर एंटोन कोचेनकोव ने इसका अच्छा बचाव किया। हालांकि, इसके बाद एटलेटिको की टीम को फिर से पेनाल्टी मिली, लेकिन इस बार फेलिक्स ने कोई गलती नहीं की। फेलिक्स ने 17वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल किया। इस बीच, सिमोन की टीम 2-0 की बढ़त के मौके को गंवा बैठी जब अल्वारो मोराटो के गोल को वार के जरिये ऑफ साइड करार दे दिया गया। वहीं, दूसरा गोल एटलेटिको के लिए दूसरे हाफ में आया जब फेलिप मोंटेइरो ने 54वें मिनट में आसानी से गोल करके टीम को 2-0 की उपयोगी बढ़त दिलाई और टीम का अगले दौर के लिए स्थान पक्का किया। फेलिप ने यह गोल कोके की मदद से किया।

जीसस की हैट्रिक: चैंपियंस लीग में पदार्पण कर रहे अटलांटा ने अपने ग्रुप-सी के अभियान का समापन अंतिम-16 में जगह बनाकर किया। टीम ने शाख्तर डोनेट्स्क को 3-0 से शिकस्त दी। टिमोथी केस्टाज्ने (66वें मिनट), मारियो पासालिक (80वें मिनट) और रॉबिन गोसेंस (90+4वें मिनट) ने अटलांटा के लिए गोल दागे। इस दौरान 77वें मिनट के बाद शाख्तर डोनेट्स्क की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि डोमिलसोन सैंटोस को रेड कार्ड दिखाए जाने के कारण मैदान से बाहर होना पड़ा था। वहीं, इस ग्रुप के शीर्ष पर मौजूद मैनचेस्टर सिटी भी आगे बढ़ने में सफल रही। मैनेजर पेप गॉर्डियोला की टीम सिटी ने डायनमो जाग्रेब को 4-1 से मात दी। डायनमो की टीम को अगले दौर में पहुंचने के लिए सिटी को हराने की जरूरत थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। ग्रेबियल जीसस की हैट्रिक और युवा मिडफील्डर फिल फोडेन के गोल ने गॉर्डियोला की टीम को 4-1 के स्कोर से जीत दिलाई। जीसस ने 34, 50 और 54वें मिनट में गोल किए, जबकि फोडेन का गोल 84वें मिनट में आया। ओलमो (10वां मिनट) के गोल ने डायनमो के हार के अंतर को कुछ कम किया।

म्यूनिख से बदला नहीं ले सका टॉटनहम: इस लीग के पिछले ग्रुप स्तर के मैच में मौरिन्हो की टीम को लंदन में म्यूनिख के हाथों 2-7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस बार उसके पास म्यूनिख को हराकर अपना बदला पूरा करने का मौका था, लेकिन टॉटनहम की टीम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई। टॉटनहम की टीम यह मैच 1-3 से गंवा बैठी। म्यूनिख के स्ट्राइकरों ने इस बार भी टॉटनहम के कमजोर डिफेंस की पोल खोल दी।

रोनाल्डो ने दागा गोल

जुवेंटस ने बायर लेवरकुसेन को 2-0 से हरा दिया, जिसमें उसके दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (75वां मिनट) और गोंजालो हिग्वियन (90+2वां मिनट) ने गोल दागे। जुवेंटस ने अपने ग्रुप-डी में छह में से पांच मुकाबले जीते और 16 अंक के साथ शीर्ष पर रहा। रोनाल्डो का इस सत्र में चैंपियंस लीग में अपनी टीम के लिए यह दूसरा गोल है। पहले हाफ तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं और दूसरे हाफ में ही दो गोल हुए। रोनाल्डो के गोल में स्थानापन्न खिलाड़ी डायबाला का योगदान रहा। डायबाला ने बॉक्स के अंदर से रोनाल्डो को गेंद पास की और उन्होंने दायें पैर से गेंद को सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। रोनाल्डो का इस लीग में यह 128वां गोल है। इंजुरी टाइम में डायबाला ने टीम के दूसरे गोल में भी मदद की। उन्होंने हिग्वियन को गेंद दो खिलाड़ियों के बीच में से पास की, जिन्होंने बिना कोई गलती किए टीम का जीत का अंतर 2-0 कर दिया।

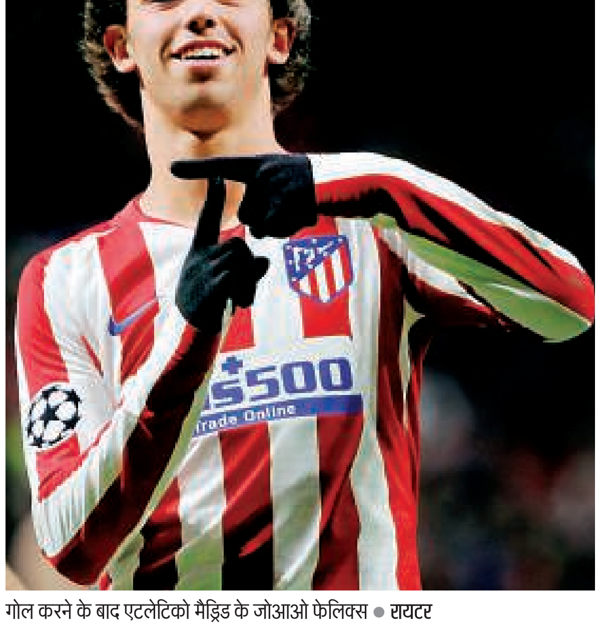

गोल करने के बाद एटलेटिको मैड्रिड के जोआओ फेलिक्स ● रायटर

नेमार, एमबापे ने दागे गोल

पीएसजी की ग्रुप-ए में गालातसारी पर 5-0 की जीत में उसके स्टार खिलाड़ी नेमार, कायलियन एमबापे और एडिनसन कवानी ने गोल किए। माउरो इकार्डी (32वां मिनट) और पाब्लो सराबिया (35वां मिनट) के गोलों से पीएसजी ने 2-0 की बढ़त बनाने में ज्यादा देर नहीं की। नेमार (46वां मिनट), एमबापे (63वां मिनट) और कवानी (84वां मिनट) ने शानदार गोल करके पीएसजी की जीत का अंतर 5-0 कर दिया। कवानी ने यह गोल पेनाल्टी पर किया। इस ग्रुप में पीएसजी 16 अंक के साथ अगले दौर में पहुंची हुई है जबकि इस ग्रुप से दूसरी टीम रीयल मैड्रिड है जिसने क्लब ब्रुग को 3-1 से हरा दिया। इस मैच में दोनों टीमों की ओर से गोल दूसरे हाफ में हुए। रोड्राइगो गोस (53वां मिनट), विनिसियस (64वां मिनट) और मॉड्रिक (90+1वां मिनट) ने रीयल के लिए गोल दागे। वहीं, ब्रुग का एकमात्र गोल हैज वैनेकन (55वां मिनट) ने किया।

06 मैचों में चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख की यह छठी जीत है। म्यूनिख जर्मनी का पहला ऐसा क्लब बन गया जिसने इस लीग में सभी ग्रुप मैच जीते हैं

500 गोल सिटी ने सभी टूर्नामेंटों में मिलाकर किए हैं। ये सभी मैनेजर पेप गॉर्डियोला के मार्गदर्शन में हुए हैं। गॉर्डियोला के मार्गदर्शन में सिटी का यह 199वां मैच था

भारत में ला लीगा फुटबॉल लीग के ब्रांड एंबेसडर बने रोहित

भारतीय बल्लेबाज ने कहा, फुटबॉलरों के हेयरस्टाइल की कॉपी करते हैं भारतीय क्रिकेटर

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय सीमित प्रारूपों के उप कप्तान रोहित शर्मा को भारत में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही वह भारत में इस लीग के पहले ब्रांड एंबेसडर भी बन गए हैं। वह ला लीगा के इतिहास में पहले गैर फुटबॉलर हैं जिसे ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

इस दौरान रोहित ने फुटबॉल में अपनी पसंदीदा टीम, खिलाड़ी और क्लब के बारे में बताया। सलामी बल्लेबाज रोहित ने कहा कि क्रिकेट में खुद को स्थापित कर चुके कई क्रिकेटर हेयरस्टाइल के मामले में फुटबॉलरों को कॉपी करते हैं। उन्होंने कहा, 'श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे युवा खिलाड़ी फुटबॉल के शौकीन हैं। वे फुटबॉलरों के हेयरस्टाइल भी अपनाते हैं।' उनके पसंदीदा फुटबॉलर और क्लब के बारे में पूछने पर रोहित ने जिदान और रीयल मैड्रिड का नाम लिया। रोहित चाहते हैं कि रीयल मैड्रिड चैंपियंस ट्रॉफी जीते। फीफा विश्व कप में उनकी पसंदीदा टीम स्पेन है। उन्होंने कहा, 'मुझे जिदान का खेल बहुत पसंद है। उन्हें देखकर ही मैं फुटबॉल का शौकीन बना। स्पेन के कौशल का मैं मुरीद हूं।' भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, 'हमारी टीम का ज्लाटन इब्राहिमोविक इशांत शर्मा है। एमएस धौनी नंबर एक फुटबॉलर हैं।' ला लीगा से जुड़ने के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं इनके साथ जुड़कर बहुत खुश हूं।'

प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ● प्रेट्र

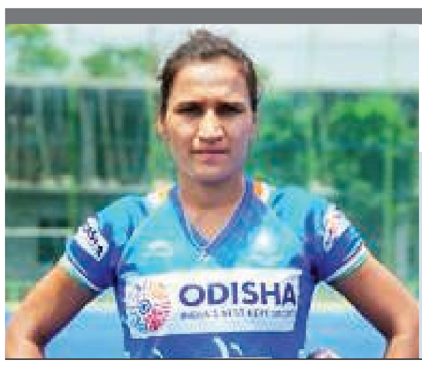

ओलंपिक से पहले फिटनेस पर ध्यान : रानी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के तहत उनकी टीम शीर्ष टीमों के खिलाफ अच्छे मैच खेलना चाहती है और उनका ध्यान फिटनेस और रिकवरी पर रहेगा। भारतीय टीम बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग ले रही है जो 15 दिसंबर तक चलेगा। क्रिसमस और नववर्ष पर तीन सप्ताह के ब्रेक के बाद टीम पांच जनवरी को फिर एकजुट होकर न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी करेगी।

ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट में यूवी बेहद अनमोल है, क्योंकि युवी अनमोल है। जन्मदिन मुबारक युवराज
– वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय कप्तान

न्यूज गैलरी

साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं बार्टी

वाशिंगटन : महिला टेनिस संघ (डब्ल्यूटीए) ने गुरुवार को विश्व की नंबर एक ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी चुने जाने की घोषणा की। 23 वर्षीय बार्टी इस साल छह बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं, जिसमें से वह चार बार खिताब जीतने में सफल रही हैं। इनमें शेनझेन में खेले गए डब्ल्यूटीए फाइनल्स और फ्रेंच ओपन के रूप में उनका पहला ग्रैंडस्लैम खिताब भी शामिल है। बार्टी 1976 में एवोन गूलागोंग के बाद से डब्ल्यूटीए द्वारा साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी चुनी जाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इस साल रिकॉर्ड 57 मैचों में अपनी जीत का परचम लहराया है। बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल और विंबलडन तथा यूएस ओपन के अंतिम-16 में भी पहुंची थीं। (आइएएनएस)

भारतीय शतरंज का भविष्य अच्छा : विश्वनाथन आनंद

चेन्नई : पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने गुरुवार को कहा कि भारतीय शतरंज का भविष्य अच्छा है और कुछ खिलाड़ी फिडे रैंकिंग में जल्द ही शीर्ष-10 में जगह बनाएंगे। आनंद अभी फिडे रैंकिंग में 15वें स्थान पर हैं और उनको लगता है कि पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती जैसे खिलाड़ी आगामी वर्षों में शीर्ष-10 में जगह बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हरिकृष्णा, विदित, शेखर, शशि भविष्य के स्टार हैं। जल्द ही भारत से कोई खिलाड़ी शीर्ष-10 में जगह बनाएगा। भारत में शतरंज का भविष्य अच्छा दिखता है क्योंकि हमारे यहां काफी प्रतिभा है। भारतीय शतरंज के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व के नंबर एक मैगनस कार्लसन और बाकी खिलाड़ियों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों जैसे फैबियानो कारुआना और चीन के डिंग लीरेन ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया। (प्रेट्र)

सिंधू फिर हारीं

ग्वांग्झू : मौजूदा चैंपियन पीवी सिंधू गुरुवार को यहां चीन की यी युफेई के हाथों हार के साथ बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल में खिताब की दौड़ से लगभग बाहर हो गईं। सिंधू ने पहला गेम जीता, लेकिन इसके बाद वह लय बरकरार रखने में नाकाम रहीं और 22-20, 16-21, 12-21 से हार गईं। सत्र के इस आखिरी टूर्नामेंट में यह उनकी लगातार दूसरी हार है। बुधवार को पहले मैच में जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ भी सिंधू को गेम से बढ़त पर थी, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा पाई थी। (प्रेट्र)

पहला टेस्ट ▸ श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के दूसरे दिन सिर्फ 18 ओवर का खेल हुआ

पाकिस्तान पर मौसम नहीं मेहरबान

पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में टेस्ट मैच के दौरान अर्धशतक लगाने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते श्रीलंकाई बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा। एपी

श्रीलंका ने 86 .3 ओवर में छह विकेट पर 263 रन, धनंजय का नाबाद अर्धशतक

02 दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहनत पर बारिश ने फेर दिया पानी, दर्शक जुटाने के लिए पाकिस्तानी बोर्ड ने प्रवेश फ्री किया था

रावलपिंडी, प्रेट्र : करीब 10 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच की वापसी तो हो गई, लेकिन मौसम की बाधा से मेजबान को जूझना पड़ रहा है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने प्रवेश फ्री कर दिया, लेकिन दूसरे दिन खराब मौसम के कारण सिर्फ 82 मिनट का खेल हो सका। इस दौरान 18.2 फेंके गए और श्रीलंका ने एक विकेट गंवाकर 61 रन बनाए। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 86.3 ओवर में छह विकेट पर 263 रन था। दिन का खेल खत्म होने के समय धनंजय डिसिल्वा नाबाद 72 रन और दिलरुवान परेरा नाबाद दो रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने गुरुवार सुबह पांच विकेट पर 202 रनों से आगे पारी बढ़ाई। पाकिस्तान ने अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भी गैरजरूरी जोखिम भरे शॉट नहीं खेले। नसीम शाह द्वारा फेंके पारी के 74वें ओवर की दूसरी गेंद को धनंजय ने मिड विकेट पर खेलते हुए दो रन लिए और टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 94 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके लगाए। दो ओवर बाद ही बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और फिर मैदान गीला होने से काफी देर तक खेल रुका रहा। 81वें ओवर में पाकिस्तान ने नई गेंद ली।

इस दौरान डिसिल्वा और डिकवेला ने छठे विकेट के लिए न सिर्फ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की, बल्कि श्रीलंका का 250 के पार भी पहुंचाया। इसमें 13 अतिरिक्त रनों का भी योगदान रहा। हालांकि नई गेंद का फायदा पाकिस्तान को जल्द मिला। 85वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की ओर निरोशन डिकवेला (33) के बल्ले का किनारा लेते हुए पीछे गई, जहां बाबर आजम ने खूबसूरती से कैच लपका। इसी के साथ छठे विकेट के लिए 67 रनों की इस अहम साझेदारी का भी अंत हुआ। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर अफरीदी ने दिलरुवान परेरा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की। अफरीदी को लग रहा था वह सही हैं और उन्होंने अपने कप्तान पर रिव्यू के लिए दबाव बनाया। हॉकआई में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी और पाकिस्तान ने अपना एक रिव्यू गंवा दिया। थोड़ी देर बाद खराब रोशनी के कारण फिर खेल रोकना पड़ा और फिर खेल दोबारा शुरू नहीं हुआ। ऐसे में मैच के दूसरे दिन सिर्फ 18 ओवर हो सके।

स्कोर बोर्ड

टॉस : श्रीलंका (बल्लेबाजी)

श्रीलंका **263/6** (86 .3 ओवर) (202/5 से आगे)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
धनंजय डिसिल्वा नाबाद	72	131	11	00
डिकवेला का. आजम बो. अफरीदी	33	63	04	00
दिलरुवान परेरा नाबाद	02	06	00	00

अतिरिक्त : (बा-5, लेबा-6, नोबॉ-3) 14, **कुल** : 86 .3 ओवर में छह विकेट पर 263 रन, **विकेट पतन** : 6-256 (डिकवेला, 84 .3), **गेंदबाजी** : मुहम्मद अब्बास 24-9-56-1

शाहीन शाह 19 .3-7-47-2
उस्मान शिनवारी 15-4-54-1
नसीम शाह 22-4-75-2
हैरिस सोहेल 3-0-12-0
शान मसूद 1-1-0-0
असद शफीक 2-0-8-0

'भारत को डे-नाइट टेस्ट खेलने के लिए मनाना आसान'

मेलबर्न, प्रेट्र : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन रॉबर्ट्स का मानना है कि विराट कोहली की टीम का अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना तय है तो उसे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गुलाबी गेंद से टेस्ट खेलने के लिए मनाना आसान होगा।

भारतीय टीम ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डे-नाइट टेस्ट खेलने से इन्कार कर दिया था लेकिन पिछले महीने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की पहल पर बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट खेला। रॉबर्ट्स ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत के खिलाफ अगले साल हम गुलाबी गेंद से एक टेस्ट खेलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और उसका 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना तय लग रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से अगले सत्र में डे-नाइट टेस्ट के लिए उन्हें मनाना आसान होगा। भारत का अगर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना तय है तो डे-नाइट का टेस्ट खेलने से इन्कार का कोई कारण नहीं दिखता। भारतीय टीम चैंपियनशिप में सात टेस्ट में 360 अंक लेकर शीर्ष पर है और उसका फाइनल खेलना तय लग रहा है। भारत में डे-नाइट टेस्ट आयोजित करने का आइडिया गांगुली का था और रॉबर्ट्स ने कहा कि इससे लगता है कि भारत ने डे-नाइट टेस्ट खेलने की शुरुआत कर दी है।

उन्होंने कहा कि जबसे गांगुली बोर्ड अध्यक्ष बने हैं। वह भारत में डे-नाइट टेस्ट आयोजित कराने के लिए काफी उत्सुक दिखे और हमने देखा कि तीनों दिन के टिकट पूरी तरह से बिक गए थे। जो पिछली सीरीज की टिकट बिक्री से कई ज्यादा थे। भारत ने डे-नाइट टेस्ट खेलने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और वह जानते हैं कि यह क्रिकेट के लिए अच्छा है। भारत ने अपने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत एडिलेड से की थी जबकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट हमेशा गाबा (ब्रिसबेन) में खेलना चाहते हैं, जहां वह 1988 से हारे नहीं हैं। रॉबर्ट्स ने इस पर कहा कि भारत को गाबा में खेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

कश्मीरी खिलाड़ियों से सीखा चुनौतियों से लड़ना : लावड़े

रजिया नूर, श्रीनगर

बेहतर मंच मिले तो कश्मीरी युवा खेलों में बहुत आगे जा सकते हैं। जहां तक फुटबॉल की बात है तो इस खेल में भी कश्मीर के युवा जुवेंटस क्लब के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह अपना नाम कमा सकते हैं। यह बात महज कश्मीरी युवाओं को खुश करने के लिए नहीं बल्कि तजुर्बे से कह रहा हूं। पिछले तीन वर्षों में मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है। मैं 2016 से कश्मीर आ जा रहा हूं। यहां रहने का मौका मिला। हमारी टीम के स्थानीय खिलाड़ियों ने सिखाया कि स्थित कैसी भी हो, मौसमी हालात जैसे भी हों, हम किस तरह इन चुनौतियों व बाधाओं को पार कर आगे बढ़ सकते हैं। इस टीम ने मुझे सही माइनों में आगे बढ़ने का हुनर सिखाया। यह बात दैनिक जागरण के साथ एक खास बातचीत में रीयल कश्मीर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और नाइजीरिया से आए 28 वर्षीय लावड़े एनीनया ने कही।

लावड़े इन दिनों आइ-लीग फुटबॉल लीग के सिलसिले में कश्मीर में आए हैं और अपना कौशल दिखाने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद मैदान में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। वर्ष 2016 में रीयल कश्मीर फुटबॉल क्लब के वजूद में आने के साथ ही लावड़े इसमें शामिल हो गए थे। तब से वह जर्सी नंबर छह के साथ रीयल कश्मीर क्लब के साथ बने हुए हैं। लावड़े ने कहा कि फुटबॉल का शौक मुझे बचपन से ही था और इसे पूरा करने के लिए मैंने नाइजीरिया फुटबॉल अकादमी शुरू की। उस अकादमी के अंतर्गत बहुत सारे मैच खेलने का मौका मिला। खेलता गया और अनुभव प्राप्त करता रहा। अकादमी के अंतर्गत मुझे भारत में भी फुटबॉल खेलने का मौका मिला और एक ऐसे ही मैच के दौरान कोच राबर्ट की नजर मुझ पर पड़ी। वह मेरा प्रदर्शन देखकर काफी प्रभावित हुए और मुझे रीयल कश्मीर टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तब से लकर मैं रीयल कश्मीर टीम के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे खुशी है कि मैं जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाली फुटबॉल टीम का सदस्य हूं।

28 वर्षीय लावड़े एनीनया रीयल कश्मीर फुटबॉल टीम की तरफ से खेलते हैं

लावड़े एनीनया। जागरण

हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे स्थानीय युवा : लावड़े ने कहा कि हमारे नाइजीरिया की बात हो या किसी और देश की, हम जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें, हमें अवसर प्राप्त रहते हैं, लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर राज्य की बात है, यहां कोई भी क्षेत्र हो, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण युवाओं को अपना भविष्य बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि कश्मीर के युवा काफी प्रतिभाशाली हैं। बेहतर मंच नहीं होने तथा कम अवसर प्राप्त होने के बावजूद यहां के युवा हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। अब फुटबॉल का ही ले लीजिए। हमारी फुटबॉल टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिला तो हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।

तन्मय और तसनीम प्री-क्वार्टर फाइनल में

सुराबाया (इंडोनेशिया), प्रेट्र : भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त शटलर तन्मय बोरा और तसनीम मीर ने गुरुवार को यहां एशिया अंडर-17 एवं अंडर-15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर-15 वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। असम के तन्मय ने मलेशिया के रामनो फर्डिनान को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-17, 15-21, 21-14 से, जबकि गुजरात की तसनीम ने इंडोनेशिया की कनाया पुत्री को 21-11, 21-15 से हराया। तन्मय ने बाद में लक्ष्य शर्मा के साथ मिलकर लड़कों के डबल्स के दूसरे दौर में भी जीत दर्ज की।

लड़कियों के अंडर-15 वर्ग में तारा शर्मा ने सिंगापुर की तीसरी वरीयता प्राप्त ली झिन्यी मेगान को 22-20, 21-14 से हराकर उलटफेर किया। लड़कों के अंडर-17 वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त वरुण कपूर ने दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन प्रणव राव गंधम और लड़कियों के वर्ग में मेघना रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा।

विविध

संक्रामक बीमारियों से लड़ने को एनसीडीसी से जुड़ेंगे कई विभाग

जागरण संवाददाता, हिसार

- प्रोजेक्ट वन हेल्थ के तहत आइएचआइपी पोर्टल पर जुड़ेंगे सभी विभाग
- फर्स्ट फेज में पशु चिकित्सक व मेडिकल चिकित्सकों को दी गई है ट्रेनिंग

देश के लोगों को मच्छरों, कुत्तों या अन्य जानवरों से होने वाली संक्रामक बीमारियों से लड़ने को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) भविष्य में पब्लिक हेल्थ, नगर निगम जैसे विभागों को भी जोड़ेगा। उन्हें भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ताकि अगर देश में कहीं भी यह बीमारी फैले तो रैपिड एक्शन लिया जाए। फर्स्ट फेज में पशु चिकित्सकों व मेडिकल चिकित्सकों को ही जूनोटिक बीमारियों के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। यह जानकारी एनसीडीसी के संयुक्त निदेशक डा. नवीन कुमार गुप्ता ने दी। वह एनसीडीसी के निर्देशन में हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीई) में जूनोटिक बीमारियों पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे। इस दौरान एनआरसीई के निदेशक डा. बीएन त्रिपाठी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

दूसरे फेज में आइएचआइपी पोर्टल पर साझा होंगे जूनोटिक मामले : एनसीडीसी ने दूसरे फेज के लिए आइएचआइपी यानि इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फोर्मेशन पोर्टल बनाया है। जो भी पशु चिकित्सक व मेडिकल चिकित्सक ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका एक अकाउंट इस पोर्टल पर खोला जा रहा है। देशभर से आए यह चिकित्सक अपने राज्यों में जूनोटिक बीमारियों पर काम करेंगे और इन बीमारियों के संबंध में कोई केस आता है तो तत्काल इस पोर्टल पर साझा करेंगे। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य है कि जूनोटिक बीमारियों की सूचना तेजी से विशेषज्ञों तक पहुंचेगी और परिस्थितियों को देखते हुए त्वरित एक्शन लिया जाएगा।

दिल्ली में चार बीमारियों से सूचना बुलेटिन किए तैयार : एनआरसीई के प्रमुख वैज्ञानिक डा. बीआर गुलाटी बताते हैं कि अभी तक जूनोटिक बीमारियों के संबंध में मास अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया गया। यानि अधिक से अधिक लोगों तक इन बीमारियों की जानकारी लेकर नहीं पहुंचा गया। अब एनआरसीई के निर्देशन में उन्होंने ग्लैंडर्स, जापानी इन्सेफ्टेलाइसिस, ब्रूसेलोसिस और रैबिज का इन्फोर्मेशन बुलेटिन तैयार किया है। यह बुलेटिन आसान भाषा में बनाया गया है ताकि लोगों को पहुंचाया जा सके।

कैप्टन के दावे के बावजूद पंजाब में नहीं टूट रही ड्रग्स की कमर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

देश के खाद्यान्न भंडार को भरने वाले पंजाब में ड्रग्स का कारोबार भी खूब हो रहा है। केंद्र सरकार के आकड़ों के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां ड्रग्स के मामले में हुई हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किए जा रहे ड्रग्स की कमर तोड़ देने के दावे की भी केंद्र के आंकड़ों के आगे हवा निकलती दिख रही है।

लोक सभा में गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 2018 में ड्रग्स के मामले में सबसे ज्यादा 13,743 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान से सटे पंजाब में सीमा पार से हेरोइन की तस्करी बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब के बाद केरल दूसरे नंबर है जहां पर 9,862 गिरफ्तारियां हुई हैं। आबादी में देश में सबसे आगे रहने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 8,395 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पंजाब में ड्रग्स की समस्या काफी समय से है, लेकिन 2015 के बाद से यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक-दूसरे को घेरती हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल

- ड्रग्स के मामले में 2018 में देश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं पंजाब में
- दूसरे नंबर पर केरल में 9,862 लोग गिरफ्तार किए गए
- कैप्टन ने चार सप्ताह में ड्रग्स की कमर तोड़ने का किया था दावा

छह हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स रैकेट में पकड़े गए पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भोला ने जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री व अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया तो यह मुद्दा और गर्मा गया। 2016 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो उन्होंने हाथ में गुटका साहिब लेकर शपथ ली कि उनकी सरकार बनने पर चार सप्ताह में ड्रग्स की कमर तोड़ देंगे।

2017 में सत्ता में आने के बाद कैप्टन ने ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया। सरकार की तमाम सक्रियता के बावजूद ड्रग्स कारोबार की कमर नहीं टूट पा रही है। 2017 में राज्य में 13,958 तस्कर पकड़े गए थे। दूसरी तरफ बीते चार सालों की बात करें तो इस अवधि में 46,909 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सीमा पर पकड़े जाने वाले ड्रग्स के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पंजाब सीमा पार के तस्करों के लिए सबसे पसंदीदा मार्ग है। 2017 में जहां 406 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी वहीं, 2018 में 481 किलोग्राम पकड़ी गई। इसके अलावा अफीम और चूरा पोस्त भी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 2018 में पंजाब में तस्करों से 432.95 किलो अफीम पकड़ी गई, जबकि 57,408 किलो चूरा पोस्त पकड़ी गई।

बिहार में हाई कोर्ट अधिकारी के बेटे ने दोस्तों संग किया युवती से सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, पटना

- एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
- सीएनएलयू में पढ़ता है आरोपित

पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अल्पना मार्केट के समीप युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार दोपहर को हुई। इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अधिकारी व भागवत नगर निवासी अरविंद कुमार के बेटे मनीष सिंह, अवन भूमि, विपुल कुमार और अश्विनी सिंह नामजद अभियुक्त हैं। मनीष चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू) का छात्र है। पुलिस ने गुरुवार की देर शाम अवन को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

विपुल की गर्लफ्रेंड थी पीड़िता : पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित युवती इवेंट कंपनी के साथ जुड़कर मॉडलिंग करती है। विपुल फोटोग्राफर है। वह भी भागवत नगर में रहता है। युवती और विपुल के बीच में प्रेम संबंध थे। एक इवेंट में विपुल ने उसकी कुछ अच्छी तस्वीरें खींची थी और उसको देने के बहाने उसने युवती को अवन के कमरे पर बुलावा था, जहां मनीष और अश्विनी मौजूद थे। दोनों ने खुद को इवेंट आयोजक बताया था। अवन अल्पना मार्केट के पास चार हजार रुपये में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करता है।

जान से मारने की धमकी दी : घटना के बाद युवती दर्द से कराह रही थी। तब विपुल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मनीष और अश्विनी ने ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो परिवार समेत जान से मार देंगे। आरोपितों ने पीड़िता का मोबाइल छीनकर उसमें रखे कुछ नंबर, फोटो और वीडियो मिटा दिए।

100 नंबर पर कॉल कर मांगी मदद

सोमवार की दोपहर युवती ने 100 नंबर पर कॉल कर शिकायत की थी कि उसे कुछ लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया है। उसने स्थान केवल अल्पना मार्केट बताया था। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस इस युवती का पता लगाने लगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तब पुलिस ने दोबारा युवती के नंबर पर संपर्क किया। युवती ने बताया कि लोगों ने उसे मुक्त कर दिया है। शाम को उसने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। गुरुवार को मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे संबंध में सेंट्रल रेंज के आइजी संजय सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम गठित कर अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को छापेमारी की जा रही है।

सेंसेटिव जोन का केस वाइल्ड लाइफ डिवीजन में अटका

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी

नंधौर सेंचुरी का नया ईको सेंसेटिव जोन निर्धारण करने में अभी और समय लगेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पहुंचने के बाद अब यह मामला वाइल्ड लाइफ डिवीजन में अटका है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव का कमेटी में शामिल विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाना है। अगर किसी भी बिंदु में आपत्ति आई तो बगैर निस्तारण के मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा।

नंधौर सेंचुरी की स्थापना साल 2012 में हुई थी। हालांकि इसके आसपास पहले से ही सिडकुल व क्रशर स्थापित हैं। बड़ी आबादी का रोजगार इस पर निर्भर है। पिछले साल जनवरी में एनजीटी के आदेश के बाद दस किमी परिधि में आ रहे दो स्टोन क्रशर को संचालन भी बंद कर दिया गया। इसके बाद नया सेंसेटिव जोन निर्धारण करने की कवायद शुरू की गई।

सेंचुरी के बाहर का नक्शा व ड्राफ्ट शासन को भेजने के बाद निर्णय लिया गया कि सेंसेटिव जोन का दायरा अब ढाई किमी से कम किया जाएगा। ताकि भविष्य में खनन व उद्योग कारोबार पर संकट न पड़े। वहीं, चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में आरटीआइ लगाकर जब जोन निर्धारण प्रस्ताव की प्रगति के बारे में जवाब मांगा तो पता चला कि फिलहाल मामला वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पास है। 19 सितंबर को डिवीजन के पास पहुंचे इस मामले के जल्द निस्तारण को लेकर राज्य सरकार स्तर से ठोस पैरवी करनी की जरूरत है।

जिहाद की हकीकत समझ आते ही लश्कर आतंकी घर लौटा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी गुरुवार को आतंकवाद छोड़ मुख्यधारा में लौट आया। परिजनों और पुलिस के प्रयासों से उसने आत्मसमर्पण किया। एक सप्ताह पूर्व हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी ने बीएसएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

जानकारी के अनुसार, पुलवामा में अवंतीपोर में रहने वाला युवक 24 नवंबर को लश्कर में शामिल हुआ था। पता चलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। उसे मुख्यधारा में वापस लाने के लिए परिजनों, दोस्तों की भी मदद ली गई। करीब पांच दिन पहले उससे संपर्क हुआ। अधिकारियों ने बताया कि युवक ने आतंकी संगठन में शामिल होने के बाद जिहाद और आजादी के नारे की हकीकत को करीब से देखा व समझा।

भाजपा सांसद के आवास पर हवलदार ने की खुदकशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह के सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। बृहस्पतिवार शाम सांसद आवास पर तैनात कर्मचारी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गार्ड रूम से बरामद किया। उनकी कनपटी पर गोली लगी थी। मरने वाले हवलदार की पहचान उनीश कुमार (46) के रूप में हुई है। उसकी तैनाती दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी यूनिट में थी। सांसद की सुरक्षा में उन्हें लगाया गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को लेडी हार्डिंग अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है उन्हें कोई पारिवारिक परेशानी थी। पुलिस परिजनों से बात कर खुदकशी के कारण का पता लगा रही है।

नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक उनीश मूलरूप से सोनीपत के रहने वाले थे। यहां परिवार के साथ वह नरेला में रहते थे। बृहस्पतिवार को पहली बार 21 अशोका रोड स्थित भाजपा सांसद के आवास पर उनकी ड्यूटी लगी थी। शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस को सांसद आवास से ही उनके खुदकशी करने की सूचना मिली। खून से लथपथ उनका शव गार्ड रूम में पड़ा हुआ था। पास में सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी और कनपटी में गोली लगने के निशान थे। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर हिबु तमंग मौके पर पहुंचे।

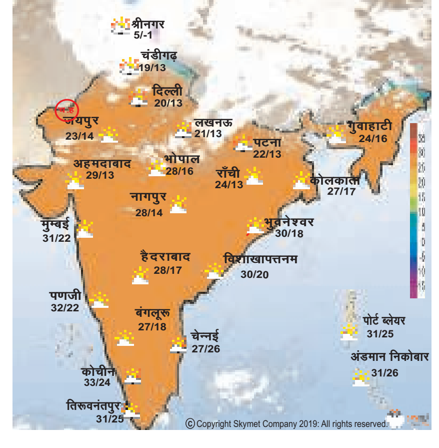

मौसम विशेष

दिल्ली, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इन राज्यों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व लद्दाख में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा व बर्फबारी संभव है।

© Copyright Skymet Company 2019. All rights reserved.

मानचित्रकार एबल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की

1642 में आज ही यूरोपीय खोजकर्ता एबल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। उन्होंने दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का भ्रमण किया और तस्मानिया, फिजी तथा छोटे-छोटे अन्य द्वीपों, समुद्रों तथा खाड़ियों की भी खोज की। वह कुशल खोजकर्ता होने के अतिरिक्त मानचित्रकार भी थे।

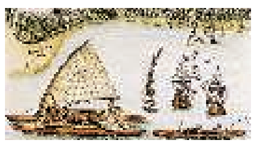

इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया

2003 में आज ही इराक के पूर्व राष्ट्रपति व तानाशाह सद्दाम हुसैन को तिकरित शहर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाकर तीन साल बाद फांसी दी गई। जंग में शिकस्त खाने के बाद अमेरिकी मोस्ट वांटेड सद्दाम नौ महीने से फरार था और एक बंकर में छिपा हुआ था।

भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पर हुआ आतंकी हमला

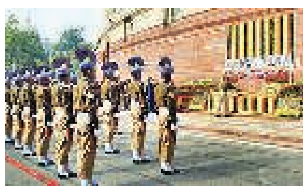

2001 में आज ही सफेद अंबेसडर कार में आए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के पांच फिदायनी आतंकवादियों ने भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद पर हमला कर दिया था। इस हमले के वक्त सांसदों और भारत सरकार के मंत्रियों समेत सौ से ज्यादा लोग संसद में मौजूद थे। इस हमले के बाद हुई मुठभेड़ में पांचों आतंकवादी के मारे जाने के साथ ही दिल्ली पुलिस के पांच जवान, संसद के दो सुरक्षाकर्मी और सीआरपीएफ की एक महिला कांसटेबल भी शहीद हो गई थी।

आठ साल की लिसिप्रिया ने जलवायु सम्मेलन में दुनिया को झकझोरा

▸ मणिपुर की नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता ने की धरती को बचाने की अपील

▸ यह कदम उठाने का वक्त, क्योंकि यह वास्तविक क्लाइमेट इमरजेंसी

मैड्रिड, प्रेट्र : महज आठ साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली भारतीय लड़की लिसिप्रिया कंगुजम ने अपनी चिंताओं से दुनिया को झकझोरा है। मणिपुर की इस नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीओपी-25 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसे मासूमों के भविष्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की गुहार लगाई।

लिसिप्रिया ने मंगलवार को अपने भाषण में कहा, 'मैं यहां वैश्विक नेताओं से कहने आई हूं कि यह कदम उठाने का वक्त है, क्योंकि यह वास्तविक क्लाइमेट इमरजेंसी है।' इतनी छोटी उम्र में इतने अहम मसले पर बात रखने के कारण लिसिप्रिया स्पेन के अखबारों की सुर्खियां बनी है। स्पेनिश अखबारों ने उसे भारतीय 'ग्रेटा' बताते हुए उसकी जमकर तारीफ की है। स्वीडन की 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सितंबर में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं को झकझोरा था। लिसिप्रिया के पिता केके सिंह ने कहा, 'मेरी बेटी की बातों को सुनकर कोई यह अनुमान नहीं कर पाया कि वह महज आठ साल की है।'

यूरोपीय देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान मणिपुर की आठ साल की पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम (सामने, बाएं), साथ में स्वीडन की 16 वर्षीया पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। इस दौरान लिसिप्रिया ने पोस्टर के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के चालू सत्र में जलवायु परिवर्तन पर कानून पास कराने की अपील की। प्रेट्र

21 देशों का कर चुकी है दौरा : लिसिप्रिया अब तक 21 देशों का दौरा कर चुकी है और जलवायु परिवर्तन मसले पर विविध सम्मेलनों में अपनी बात रख चुकी है। वह दुनिया में सबसे कम उम्र की पर्यावरण कार्यकर्ता बताई जा रही है।

इस सम्मेलन से बदली जिंदगी : महज छह साल की उम्र में लिसिप्रिया को 2018 में मंगोलिया में आपदा मसले पर हुए मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में बोलने का अवसर मिला था। उसने कहा, 'इस सम्मेलन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आपदाओं के चलते जब बच्चों को अपने माता-पिता से बिछड़ते देखती हूं तो रो पड़ती हूं।'

पिता की मदद से बनाया संगठन : मंगोलिया से लौटने के बाद लिसिप्रिया ने पिता की मदद से 'द चाइल्ड मूवमेंट' नामक संगठन बनाया। वह इस संगठन के जरिये वैश्विक नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने की अपील करती है।

पीएम मोदी से भी लगाई थी गुहार : लिसिप्रिया गत जून में संसद भवन के पास तख्ती लेकर पहुंची थी। इसके जरिये उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानून बनाएं।

छोड़ना पड़ा स्कूल : लिसिप्रिया का जन्म इंफाल में हुआ, लेकिन वह आमतौर पर पूरे समय शहर से बाहर रहती है। वह ज्यादातर दिल्ली और भुवनेश्वर में रहती है। जलवायु परिवर्तन मसले पर अपने जुनून के चलते वह स्कूल नहीं जा पाती थी। इस कारण उसने गत फरवरी में स्कूल छोड़ दिया।

स्पेन की सरकार ने उठाया खर्च : लिसिप्रिया के पिता के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बेटी को आमंत्रित किया था, लेकिन तब हमें लगा था कि स्पेन जाने के खर्च का कैसे प्रबंध होगा? इसके लिए ईमेल के जरिये कई मंत्रियों से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाद में भुवनेश्वर के एक व्यक्ति ने मैड्रिड के लिए टिकट बुक कर दिया। गत 30 नवंबर को मैड्रिड रवाना होने से एक दिन पहले एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि उनकी 13 दिन की यात्रा का खर्च स्पेन सरकार वहन करेगी।

फिल्म रिव्यू

★★☆

साधारण कहानी पर गढ़ा गया पीरियड ड्रामा

मामांगम

प्रमुख कलाकार : ममूटी, प्राची तेहलान, अच्युतन, उन्नी मुकुंदन
निर्देशक : एम पद्मकुमार
अवधि : 2 घंटे 36 मिनट

इन दिनों हिंदी सिनेमा के साथ-साथ दक्षिण में भी ऐतिहासिक फिल्मों का चलन जारी है। हाल में चिरंजीवी अभिनीत 'सैय रा नरसिम्हा रेड्डी' की कहानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की वीरगाथा पर आधारित थी। अब 'मामांगम' आई है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में केरल में भारतपुझा नदी के किनारे पर मनाए जाने वाले उत्सव मामांगम पर आधारित है। कुंभ की तरह इस मेले का आयोजन हर 12 साल पर होता था। इस मेले का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व होता था। पूर्व में महोत्सव के असली संचालक वल्लुनाडु के राजा को युद्ध में धोखे से हराकर मामांगम के मैदान को कोझीकोड के सम्राट सामुदरी ने अपने अधिकार में कर लिया था। पराजय को अस्वीकार करते हुए वल्लु राजा अपने बेहतरीन योद्धाओं को आत्मघाती योद्धा बनाकर हर मामांगम में भेजा करते थे। दोनों राजाओं के बीच दुश्मनी की घटनाओं में 1695 में घटी एक घटना को ऐतिहासिक साक्ष्य में कल्पना का योग करके फिल्म में गढ़ा गया है।

कहानी के आरंभ में सामुदरी राजा को मारने पहुंचा योद्धा चावेर (ममूटी) जब सिंहासन के करीब पहुंचता है तो राजा वहां से फरार हो जाता है। कहानी 24 साल आगे बढ़ती है। चंद्रोथ परिवार का बेटा (उन्नी मुकुंदन) और उसका बारह साल का भांजा (अच्युतन) दुश्मन राजा को हरा देने की प्रतिज्ञा के साथ रवाना होते हैं। उधर, कोझिकोड में एक परदेसी व्यापारी की हत्या हो जाती है। हत्यारों का पता लगाने के लिए महामंत्री कोठे पर पहुंचते हैं, जहां पर व्यापारी मनोरंजन के लिए आया है। पूछताछ के दौरान दीवार पर मामांगम से संबंधित चित्र देखकर महामंत्री उसके चित्रकार के बारे में पूछते हैं। वहां से पर्तें खुलनी आरंभ होती हैं। कोठे के लोग व्यापारी को मारने के पीछे अलग-अलग कहानी बताते हैं। महामंत्री भांप लेता है कि वे सब झूठ बोल रहे हैं। वहां से कहानी मोड़ लेती है। चित्रकार की जिंदगी के रहस्य और मामा-भांजे के अगले पड़ाव के साथ कहानी आगे बढ़ती है।

फिल्म की शुरुआत में मामांगम के इतिहास और दोनों राज्यों के राजाओं के बीच युद्ध और दुश्मनी के बारे में चित्रों से जानकारी दी गई है। कहानी का आरंभ और अंत युद्ध से ही होता है। श्याम कौशल द्वारा निर्देशित एक्शन दृश्य प्रभावशाली हैं। फिल्म की शुरुआत में कहानी और पात्रों को स्थापित करने में लेखक-निर्देशक ने काफी समय लिया है। मध्यांतर के बाद कहानी गति पकड़ती है। फिल्म में ट्विस्ट है, लेकिन वह चौंकाता नहीं है। कहानी एक राजा को मारने की है, लेकिन उसे गढ़ने में कई अनावश्यक प्रसंग डाले गए हैं। उसे हटाकर फिल्म की अवधि कम की जा सकती थी। क्लाइमेक्स को भी बेहतर बनाया जा सकता था।

हिंदी में तैयार किया गया गीत-संगीत प्रभावित नहीं करता है, जबकि फिल्मांकन और कोरियोग्राफी अच्छी है। उस समय की वास्तुकला, युद्धकला, वेशभूषा, सामाजिक आचरण आदि का कहानी में समुचित तरीके से समावेश किया गया है। एक्शन दृश्यों में ममूटी विश्वसनीय लगते हैं। बाल कलाकार अच्युतन के अभिनय की तारीफ करनी होगी। केरल के प्राचीन मार्शल आर्ट कलरियापट्टू का प्रदर्शन करते हुए वह मासूम और निर्भीक लगते हैं। प्राची देसाई खूबसूरत दिखी हैं। फिल्म युद्ध विभीषिका के परिणामों पर भी बात करती है। यह पहली मलयालम फिल्म है, जिसे तमिल, तेलुगु और हिंदी में एकसाथ रिलीज किया गया है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

इधर-उधर की

अमेरिकी कंपनी ने 70 करोड़ रुपये का बोनस बांटा

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका के मैरीलैंड की रियल एस्टेट कंपनी सैंट जॉन प्रॉपर्टीज ने अपने 198 कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपये (10 मिलियन डॉलर) का बोनस दिया। सभी कर्मचारियों को उनका बोनस लाल लिफाफे में कंपनी की हॉलीडे पार्टी में दिया गया। कर्मचारियों को औसतन 35 लाख रुपये (50 हजार डॉलर) दिए गए। सबसे अहम बात यह रही कि कंपनी ने कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। सेंट जॉन प्रॉपर्टीज के प्रेसिडेंट लॉरेंस मेक्रांट्ज के मुताबिक, 14 साल के दौरान कंपनी ने 200 लाख वर्ग फीट में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट किया। इस उपलब्धि को हासिल करने में कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की है। ऐसे में हम कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसको लेकर हम कुछ बड़ा करना चाहते थे। लिहाजा, यह सरप्राइज उन्हें धन्यवाद स्वरूप दिया गया है।

मंगल पर पानी की तलाश के करीब नासा

उम्मीद ▸ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने तैयार किया ग्रह का नया मानचित्र, दिखाई बर्फ

जेपीएल का दावा, लाल ग्रह की सतह से 2.5 सेंटीमीटर नीचे मौजूद है पानी

लॉस एंजिलिस : मंगल के बारे में वैज्ञानिक कई तरह के दावे कर चुके हैं। पृथ्वी के नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोग भी इस लाल ग्रह के बारे में जानने को काफी उत्सुक रहते हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक यहां जीवन और पानी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नया मानचित्र तैयार किया है, जिसमें वैज्ञानिकों के उस दावे को और विस्तार से प्रदर्शित किया है कि मंगल ग्रह में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाल ग्रह की सतह से 2.5 सेंटीमीटर नीचे पानी की मौजूदगी हो सकती है।

कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री (जेपीएल) के शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा, 'मंगल पर पानी की मौजूदगी वहां जीवन की संभावनाओं को और पुख्ता कर देती है।' उन्होंने कहा कि अब इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि भविष्य में यदि कोई यान मनुष्यों को लेकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों को खोजने निकलता है तो वह लाल ग्रह पर उतर कर पीने के लिए पानी और रॉकेट के लिए ईंधन भी बना सकता है।

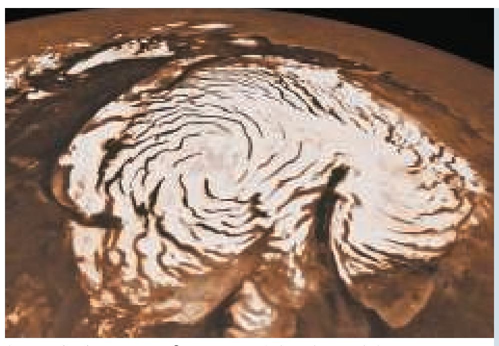

वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह पर बर्फ के संकेत मिले हैं। फाइल

जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लैटर्स में प्रकाशित इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह का चक्कर लगा रहे दो उपग्रहों के डाटा उपयोग किया है। नासा के मार्स रिकॉनिंसेंस ऑर्बिटर (एमआरओ) और मार्स ओडिसी ऑर्बिटर नामक ये उपग्रह यहां पानी का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किए गए थे।

जेपीएल के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक सिल्वेन पिक्सक्स ने कहा, 'हमारा अध्ययन यह बताता है कि मंगल पर पानी के लिए आपको किसी बड़ी मशीन के जरिये खोदाई करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक फावड़े से भी खोदाई कर पानी सतह में ला सकते हैं।' उन्होंने कहा कि हम मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में दफन हुए पानी का डाटा लगातार एकत्र कर रहे हैं और ऐसे स्थानों की तलाश में हैं जहां अंतरिक्ष यात्री आराम से लैंडिंग कर सकें और पानी प्रत्यक्ष रूप से देख सकें।

नई तकनीक का किया इस्तेमाल : अध्ययन में बताया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के फीनिक्स लैंडर ने मंगल के ध्रुवों के आस-पास ऐसे कई चित्र लिए हैं, जो वहां पानी से संभावनाओं को और मजबूती देते हैं। इस तथ्य को पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने मार्स ओडिसी ऑर्बिटर पर लगे हीट-सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और थर्मल इमिशन इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया।

अगले साल लांच होगा मार्स 2020 रोवर

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले साल अपने उन्नत रोवर 'मार्स 2020' को जीवन से जुड़े साक्ष्य खोजने के लिए मंगल पर भेजने की तैयारी में जुट गया है। कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित जेट प्रोपल्सन लैब द्वारा तैयार एक टन वजनी यह रोवर लाल ग्रह पर एक छोटी प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। यह वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूनों से जीवन से जुड़ी जानकारी हासिल करने का काम करेगा। नासा के अनुसार, इस रोवर को भेजने का मुख्य मकसद मंगल पर जीवन के साक्ष्यों का पता लगाना है। इससे पहले खोजी अभियान के तहत नासा ने मंगल पर क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था। मंगल अभियान के तहत मार्स 2020 को क्यूरियोसिटी से एक कदम आगे बताया जा रहा है।

शोध अनुसंधान

रात-दिन ज्यादा सोने से बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा

कम नींद ही नहीं, ज्यादा नींद से भी खतरा हो सकता है। हालिया शोध के मुताबिक, रात में नौ घंटे या इससे ज्यादा नींद के बाद दिन में डेढ़ घंटे या इससे ज्यादा सोने वाले बुजुर्गों में स्ट्रोक का खतरा 85 फीसद तक बढ़ जाता है। शोध के दौरान करीब छह साल तक 62 साल की औसत आयु वाले 31,750 लोगों के आंकड़े जुटाए गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि शोध की शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक की शिकायत नहीं थी और न ही किसी तरह की बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। अध्ययन के दौरान इनमें से 1,557 लोगों को स्ट्रोक आया। दिन और रात दोनों समय ज्यादा नींद से सबसे ज्यादा खतरा देखा गया। रात में सात से कम या सात से आठ घंटे तक सोने वालों में ऐसा खतरा नहीं रहता। हालांकि बहुत कम नींद से भी स्ट्रोक का खतरा 29 फीसद तक बढ़ जाता है। - प्रेट्र

ओबामा दंपती की फर्नीचर कारीगरी

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में गुरुवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल एक अलग रूप में ही दिखे। ओबामा दंपती एक कम्युनिटी सर्विस वर्कशॉप में शामिल हुए। इस दौरान फर्नीचर कारीगरी में कुछ इस तरह हाथ आजमाते नजर आए। दंपती ने यहां ओबामा फाउंडेशन के महिला शिक्षा और सशक्तीकरण पर केंद्रित लीडरशिप कांफ्रेंस में भी हिस्सा लिया। एपी

अमेरिका में बर्फबारी के चलते हुई दुर्घटना

अमेरिका के कोलफैक्स शहर में कारें लेकर जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर हाइवे के किनारे पर लटक गया। यह हादसा बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन के चलते हुआ है। इस वाकये में ट्रक पर लदे कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। हादसे के चलते लेन पर कई घंटे यातायात भी बाधित रहा। एपी

स्क्रीन शॉट

अपनी शादी के संगीत से प्रेरित सीरीज बनाएंगे प्रियंका और निक

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई है। अब पहली बार दोनों साथ मिलकर एक सीरीज का निर्माण करने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि यह सीरीज उनकी शादी पर हुए संगीत समारोह से प्रेरित होगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो की ओर से उनके इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। इस बात की जानकारी प्रियंका ने सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रियंका ने लिखा, 'हमारी शादी में दोनों परिवारों ने मिलकर संगीत समारोह में परफॉर्म किया था। यह ऐसा परफॉर्मेंस था, जो हमारे प्यार का जश्न मनाता है। हमारी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। मैं और निक नए प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसका शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। इसमें हम शादी की एक रात पहले परिवार और दोस्तों के तरफ से आने वाले प्यार और जादू का जश्न मनाएंगे, जो संगीत और डांस के साथ जुड़ा होता है। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो बेबी (निक)। यह हमारा पहला संगीत प्रोजेक्ट है। हम यह शानदार अनुभव उन जोड़ों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अगर आप 2020 की गर्मियों में शादी करने वाले हैं तो हम आपके इस जश्न का हिस्सा बनकर आपके इस अनुभव को और भी शानदार बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं।' फिलहाल इस सीरीज के लिए कास्टिंग की जा रही है। इसकी शूटिंग अगले साल से आरंभ होगी। सीरीज के हर एपिसोड में सगाई कर चुके जोड़ों की शादी की पार्टी, परिवार और दोस्तों में व्यस्त दिखाया जाएगा। शादी पर परफॉर्मेंस से पहले सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स, स्टाइलिस्ट और क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ रिहर्सल भी करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल जोधपुर के उमेद भवन में प्रियंका और निक शादी के बंधन में बंधे थे। उमेद भवन में ही दोनों की शादी की कई रस्में हुई थीं। संगीत की रात प्रियंका और निक के साथ दोनों के परिवार वालों ने जमकर डांस किया था।

मजेदार अंदाज में विद्या बालन ने बताई फिल्म की रिलीज तारीख

फिल्म के प्रमोशन से लेकर उसकी रिलीज तारीख बताने तक का अंदाज बदल चुका है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम है। विद्या बालन की आगामी फिल्म गणित की जीनियस और मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी की बायोपिक होगी। 1982 में शकुंतला देवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इस फिल्म से विद्या बालन का लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है। अब विद्या ने बड़े ही मजेदार अंदाज में अपनी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है। विद्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह फिल्म की तारीख एक पहेली की तरह बता रही हैं। विद्या वीडियो में कहती हैं, 'शंकुतलादेवी की रिलीज तारीख सामने आ गई है। यह फिल्म आज से ठीक 148 दिनों बाद रिलीज होगी।' इसके बाद विद्या ने कहा कि वह शंकुलता देवी बनी हैं, ऐसे ही आसानी से फिल्म के रिलीज की तारीख नहीं बताएंगी। फिर उन्होंने इमोजी के जरिए बताया कि उनकी फिल्म आठ मई 2020 को रिलीज हो रही है। शंकुतला देवी फिल्म से जो तस्वीर विद्या की रिलीज हुई थी, उसमें विद्या छोटे बालों में नजर आ रही थीं। फिल्म का निर्देशन अनु मेनन ने किया है। विद्या बालन के साथ फिल्म में बांग्ला फिल्मों के अभिनेता जीशु सेनगुप्ता नजर आएंगे। इस साल विद्या फिल्म 'मिशन मंगल' में नजर आई थीं।

शॉर्ट फिल्मों में काम करना मजेदार लगता है जाह्नवी को

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर वेब शो 'घोस्ट स्टोरीज' में नजर आएंगी। इस शो में चार अलग-अलग कहानियां होंगी, जिन्हें अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर निर्देशित कर रहे हैं। जाह्नवी ने जोया अख्तर की कहानी के लिए शूट किया है। जाह्नवी कहती हैं कि वह इस प्रोजेक्ट में काम कर खुश हैं। वह कहती हैं, 'मैंने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म में काम किया है और इसका अनुभव काफी मजेदार रहा। शॉर्ट फिल्म में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में 50-60 दिन से भी ज्यादा समय लगता है, इसलिए कभी-कभी इससे ऊब होने लगती है। जबकि शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग जल्द खत्म हो जाती है।' बता दें कि जाह्नवी शरन शर्मा की फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में नजर आएंगी। इसके अलावा अगले साल उनकी दो फिल्में 'रूही आफ्जा' और 'दोस्ताना 2' रिलीज होंगी। वह कहती हैं, 'मैं फ्लि के लिए उत्साहित हूं।

अध्ययन

रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा-अंतरिक्ष में चुंबक की तरह एक-दूसरे से चिपकर खगोलीय पिंड बनाते हैं धूल के कण

ऐसे होता है ब्रह्मांडीय धूल से ग्रहों का निर्माण

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : ग्रहों और खगोलीय पिंडों के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत धूल के कणों के आपस में चिपकने से इनका निर्माण हुआ। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि ब्रह्मांडीय धूल के कण कैसे आपस में चिपकते हैं और धीरे-धीरे एकत्र होकर ग्रहों के निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह अध्ययन औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली धूल से निपटने के लिए मददगार सिद्ध हो सकता है।

अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान पाया है कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी में धूल के कण स्वतः ही विद्युत आवेश पैदा करते हैं और बड़े समुच्चय बनाने के लिए एक-दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो ग्रहों और खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है।

नेचर फिजिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि जैसे चुम्बक के दो अलग-अलग ध्रुवों को यदि साथ मिला जाता है तो वे तुरंत एक-दूसरे से चिपक जाते हैं। वहीं, यदि दो समान ध्रुवों को मिलाने की कोशिश की जाती है तो वे एक-दूसरे दूर होने लगते हैं। ठीक वैसे ही धूल के कणों में भी विद्युत आवेश उत्पन्न होने पर वे विपरीत किस्म के कणों से चिपकते चले जाते हैं और धीरे-धीरे ग्रहों और खगोलीय पिंडों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है।

प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा है कि जब धूल के कणों का समुच्चय कुछ सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसके बाद वे एक ऐसे तंत्र का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल भी पैदा होने लगता है और उसका आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। जिसके बाद ये कई किलोमीटर लंबे हो जाते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार, 'प्लास्टिक से लेकर फार्मास्युटिकल दवाएं बनाने करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रासायनिक रिएक्टरों में भी इसी तरह की धूल एकत्रीकरण प्रक्रिया फायदेमंद हो सकती है। ऐसी निर्माण इकाइयों को फिल्यूडाइज बेड रिएक्टर कहा जाता है। उन्होंने कहा, रिएक्टरों में गैस छोड़कर धूल के सूक्ष्म कणों को ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और जब उनमें विद्युत आवेश पैदा होता है तो ये कण रिएक्टर की दीवारों से चिपक जाते हैं। इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए धूल के कणों का ठीक से निस्तारण करना फायदेमंद हो सकता है।

रटगर्स यूनिवर्सिटी के सह-लेखक ट्रॉय शिनब्रोट ने कहा, 'इस अध्ययन के जरिये हमने यह समझने का प्रयास किया कि ग्रहों का निर्माण कैसे हो सकता है और औद्योगिक क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल के सूक्ष्म कणों को वायुमंडल में फैलने से कैसे रोक सकते हैं।